R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.oksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 11
01 से 15 मार्च 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

रूस-यूक्रेन युद्ध
दो महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच
भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान

गर युद्ध लंबा चला तो...
तीसरे विश्व युद्ध की संभावना

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजकाज

9 | 8 साल बाद विधायकों को उत्कृष्टता पुरस्कार

संसदीय परंपरा में सांसदों और विधायकों के कार्यों का आंकलन कर सम्मान करने की परंपरा पुरानी है। मप्र में 2008 से पहले विधायकों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन कतिपय कारणों से यह बंद हो गया था।

राजपथ

10-11 | परफार्मेंस का आंकलन

विधानसभा चुनाव में अभी 18 महीने बचे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। चूंकि दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए कोई भी पार्टी...

अवैध खनन

14 | रिपेरियन जोन में अवैध खनन

प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में रेत माफिया की सक्रियता बढ़ गई है। हालात यह है कि नर्मदा किनारे रिपेरियन जोन से ही माफिया रेत निकाल रहे हैं। नर्मदापुरम जिला प्रशासन रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है...

विकास

18 | 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'

मप्र में अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिए नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

जब एक डर दूसरे डर के विरुद्ध होता है तो युद्ध होता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध किसी देश के पराक्रम का युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों के भयभीत होने का युद्ध है। दरअसल, दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अमेरिका नाटो के जरिए अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगा हुआ है। इसके लिए उसने यूक्रेन को मोहरा बनाया है, ताकि वह रूस के दरवाजे पर अपनी ताकत जमा सके। यह बात रूस को नागवार गुजरी है।

राजनीति

30-31 | मुफ्त का चंदन...!

5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इन सभी राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जी जान से पार्टी हर प्रकार के हथकंडे अपना रही हैं। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु एक के बाद एक नकद एवं मुफ्त उपहारों की घोषणा की जा रही है।

महाराष्ट्र

35 | नवाब के साथ पूरी सरकार

केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी रस्साकशी के ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अफसर गत दिनों सुबह-सुबह करीब 6 बजे नवाब मलिक के...

बिहार

38 | लालू फिर जेल में

लालू प्रसाद यादव की कुंडली से जेल योग नहीं निकल रहा है। लगातार 40 महीने जेल में बिता चुके राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 8वीं बार जेल पहुंच गए हैं। चारा घोटाला में डोरंडा ट्रेजरी से फर्जी कागजात के आधार पर 89 लाख रुपए...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो...

किसी शायर ने लिखा है...

जनता की आंखों में आंखे डालकर करीब से पूछो,
महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो।

लेकिन विडंबना यह है कि कोरोना संक्रमण से बेहाल हुई जनता पर निरंतर टैक्स, महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मप्र में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बिजली कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.71 प्रतिशत दर बढ़ाने को लेकर दायर याचिका को मप्र राज्य नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अगर कंपनियों की डिमांड के मुताबिक दरें बढ़ाई गईं तो बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। प्रति यूनिट 58 पैसे तक बढ़ सकते हैं। बढ़े हुए बिजली बिल पर 12 प्रतिशत सर्विस टैक्स भी लगेगा। बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की वजह बिजली कंपनियों का घाटा बताया जा रहा है। करे कोई और भरे कोई की तर्ज पर हर दो-चार माह बाद बिजली कंपनियां दरें बढ़ा देती हैं, जिसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। दरअसल, बिजली कंपनियां घाटे और कर्ज के बोझ तले इसलिए हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए एक तरफ जहां गरीबों के नाम पर लाखों लोगों को बिजली उपहार में दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दरें बढ़ाकर ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (पूर्व, मध्य और पश्चिम) की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है। इसमें सबसे अधिक 19 हजार 428 करोड़ रुपए पश्चिम क्षेत्र कंपनी खर्च करेगी। वहीं, सबसे कम खर्च पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी करेगी। जबकि इस कंपनी के कार्यक्षेत्र में 20 जिले शामिल हैं। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि उसे इस जरूरत के मुकाबले मौजूदा बिजली दर पर 3915 करोड़ रुपए कम प्राप्त होंगे। इसकी भरपाई करने के लिए उसे बिजली की दरों में 8.71 प्रतिशत बढ़ाना होगा। औसतन 8.71 प्रतिशत को सभी श्रेणियों में समान रूप से मानें तो प्रति यूनिट 28 पैसे से 58 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले से ही मप्र में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। राज्य सरकार 100 यूनिट तक सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को राहत जरूर दे रही है, लेकिन कंपनी अधिकारियों की मनमानी पर नकेल कसने में विफल है। 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। कंपनियों को दर बढ़ाने की बजाय अपनी कार्यदक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी की बिजली की दर बढ़ाने की याचिका उनकी अक्षमता को दिखाती है। बिजली कंपनी सरप्लस बिजली के बावजूद सालाना 3,324 करोड़ रुपए ऐसे पावर प्लांट को दे रही हैं, जिनसे बिजली ली ही नहीं जाती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कई ऐसे पावर परचेस एग्रीमेंट हुए हैं, जिस वजह से बिना बिजली लिए ही उन्हें फिक्स राशि भुगतान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही बिजली वितरण में होने वाली हानि के करीब 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान भी जनता से वसूलने की तैयारी है, जो पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। प्रदेश में अगर सरकार विद्युत उत्पादन, वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर दे और मुफ्तखोरी बंद कर दे तो प्रदेश में बिजली की दर सबसे कम हो जाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादक होने के बाद भी मप्र में बिजली सबसे महंगी है। वह वक्त कब आएगा जब कोई जनता की आंखों में आंखे डालकर करीब से पूछेगा कि आपको महंगाई का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 11, पृष्ठ-48, 1 से 15 मार्च, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

उद्योगों को राहत

मप्र के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को बिजली की आपूर्ति मप्र की विद्युत वितरण कंपनियां ही करती है। प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली की दरें घटाए बगैर मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के जरिए उद्योगों को सस्ती बिजली प्रदाय का रास्ता निकलता दिख रहा है।

● **कमल शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

बेरोजगारी दूर करे सरकार

मप्र में एक तरफ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी, यहां तक तो ठीक था, फिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देने के नाम पर सुविधा नियुक्ति की परंपरा शुरू हो गई। जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सही नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

● **जीवन उपाध्याय,** इंदौर (म.प्र.)

जंगल हरे-भरे ही रहें

वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मप्र में हो रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अब तक मप्र में करीब 5,347 वर्ग किमी से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। प्रदेश सरकार को जंगलों के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।

● **पंकज साहू,** जबलपुर (म.प्र.)

बेवजह खराब किया जा रहा है देश का माहौल

निस्संदेह हर किसी को अपनी पसंद के परिधान पहनने की आजादी है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। स्कूल-कॉलेज में विद्यार्थी मनचाहे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। इसी मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा संस्थान ड्रेस कोड लागू करते हैं। यह देखना दयनीय है कि जब ईरान में महिलाएं बुर्के के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और अफगानिस्तान में तालिबान बुर्का न पहनने वाली स्त्रियों पर कोड़े बरसा रहे हैं, तब कर्नाटक में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ाई करने पर आमादा हैं। कैंपस में हिजाब हो या न हो, शिक्षा हमारा अधिकार है। युवाओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि देश का माहौल बिगड़े।

● **राखी सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

विपक्ष मजबूत हो

5 राज्यों में के चुनावों की चर्चा देशभर में हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मुद्दे अलग-अलग उठाए हैं, लेकिन सभी के भाषण में बेरोजगारी, संविधान, पेगासस पर फोकस देखने को मिला है और ये सब अगले आम चुनाव तक जारी रहा तो लगता नहीं परिस्थितियां 2019 जैसी फिर से हो सकती हैं। कई विपक्षी पार्टियां भी एक-दूसरे से आगे रहने में लगी हुई हैं। जिससे सत्तापक्ष और मजबूत होता जा रहा है। उप्र में चल रहे विधानसभा चुनावों के नतीजे ही 2024 के लोकसभा चुनावों का भविष्य तय करेंगे।

● **भीम सिंह,** नई दिल्ली

किसानों को राहत कब?

भारत की अर्थव्यवस्था में खेती क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है, लेकिन इससे कुल रोजगार का 42 प्रतिशत सृजित होता है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित और चरम मौसम ने देश में दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। जब देश में खेती का 55 फीसदी बरसात पर निर्भर हो तो जाहिर है कि खेती-किसानी के प्रति कोताही देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती है।

● **प्रताप मंडल,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अखिलेश से सहमी नौकरशाही

उप्र में सत्ता परिवर्तन की आहट से राज्य की नौकरशाही में भारी खलबली मच चुकी है। लखनऊ के सत्ता गलियारों से लेकर प्रदेश के सभी जनपदों तक चौतरफा चर्चा का विषय योगी सरकार की संभावित विदाई और अखिलेश यादव की आमद को लेकर बन चुका है। खबर जोरों पर है कि योगी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे अफसरों की कार्यशैली से नाराज अखिलेश यदि सत्ता में आए तो इन अफसरों पर तत्काल गाज गिरेगी। जानकारों का कहना है कि सपा सरकार यदि बनी तो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश समेत ऐसे सभी जिलाधिकारियों को अखिलेश महत्वहीन पदों में भेज देंगे जिनकी भूमिका सीएए आंदोलन के दौरान दमनकारी रही। उल्लेखनीय है कि लखनऊ के डीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग नजदीकी के चलते उप्र के विपक्षी दलों की निगाह में खासे खटकते आए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ आईएएस एसपी गोयल, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी, वरिष्ठ आईएएस नवनीत सहगल, संजय प्रसाद इत्यादि को भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना तय माना जा रहा है। प्रदेश के बदलते राजनीतिक हालातों को भांपते हुए योगीराज में साइड लाइन किए गए अफसरों ने अभी से अखिलेश यादव के करीबियों संग मेलजोल बढ़ा डाला है।

दक्षिण भारत का बढ़ता कांग्रेस प्रेम

देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस इस समय बदहाली के चरम दौर से गुजर रहा है। एक के बाद एक बड़े नेता वर्तमान पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुखर तो हो ही रहे हैं, कई संगठन छोड़ भाजपा में शामिल तक हो चुके हैं। दस बरस तक केंद्र की सत्ता में काबिज रहा यूपीए गठबंधन भी अब बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस गठबंधन के अस्तित्व को ही नकार दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में बने इस गठबंधन की बागडोर हाल-फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में जरूर है लेकिन शरद पवार और ममता बनर्जी अब खुलकर एक नया विपक्षी फ्रंट बनाने की वकालत करने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए दक्षिण भारत से मदद के संकेत हैं। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का राहुल गांधी पर दिया गया आपत्तिजनक बयान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को खासा क्रोधित करने वाला रहा। राव ने सरमा पर कठोरतम कार्यवाही की मांग प्रधानमंत्री मोदी से करके स्पष्ट इशारा कर दिया कि वे गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कभी यूपीए का हिस्सा रहे राव का इस गठबंधन में वापसी करना आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व के लिए खासा मददगार साबित हो सकता है।

आत्मकथाओं से त्रस्त विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इन दिनों राज्य के पूर्व नौकरशाहों की आत्मकथाओं से भारी परेशान बताए जा रहे हैं। दरअसल, केरल के कुख्यात सोना तस्करी मामले में आरोपी बनाए गए राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह एम शिवाशंकर की आत्मकथा 'अश्वत्थामा इज जस्ट एन एलिफेंट' ने विजयन को बैकफुट में ला खड़ा किया है। अपनी इस आत्मकथा में शिवाशंकर ने राज्य सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने जैसे कई आरोप लगाए हैं। कभी मुख्यमंत्री विजयन के बेहद करीबी रहे इस नौकरशाह की आत्मकथा को आधार बना अब राज्य के विपक्षी दल मुख्यमंत्री पर न केवल निशाना साधा रहे हैं, बल्कि इस सोना तस्करी के मामले की एक बार फिर से जांच कराए जाने की बात कहने लगे हैं। सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) का मानना है कि यह आत्मकथा भाजपा के इशारे पर लिखी गई है। इतना ही नहीं विजयन के करीबी रहे एक अन्य नौकरशाह जैकब थॉमस की आत्मकथा 'स्विमिंग विद् शार्क्स' को लेकर भी विपक्षी दल खासा शोर मचा रहे हैं। अपनी इस आत्मकथा में राज्य के सतर्कता निदेशक रहे जैकब ने विजयन सरकार को आड़े हाथों लिया है। केरल में इन दिनों कहा-सुना जा रहा है कि विजयन को खतरा विपक्षी दलों से कहीं ज्यादा ऐसे अफसरों से है जो नौकरी में रहते तो उनके विश्वास पात्र बने रहते हैं लेकिन रिटायर होने के बाद उनके कटु आलोचक बन जाते हैं।

गोवा से निराश ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गोवा प्रेम तेजी से समाप्त होने की चर्चा चौतरफा हो रही है। दरअसल, अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री शाह की तमाम कोशिशों को धता बताने में सफल रहीं दीदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी ताकतों का चेहरा बनने की ठान ली है। अपने इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए दीदी ने तृणमूल कांग्रेस का देशभर में तेजी से विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस मिशन के तहत ही गोवा में पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। ममता ने बड़े स्तर पर कांग्रेस में सेंधमारी कर गोवा में तृणमूल को ताकतवर बनाने का काम किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई विधायक और नेता कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हुए। इससे दीदी का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो को पार्टी की तरफ से राज्यसभा तक भेज डाला। सूत्रों की मानें तो ऐसा एक राजनीतिक डील के तहत किया गया। डील यह थी कि फलेरियो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनते ही राज्यसभा से त्यागपत्र दे देंगे।

बदली-बदली सी नौकरशाही

उत्तराखंड के सत्ता गलियारों में इन दिनों चौतरफा चर्चा भाजपा सरकार की विदाई और कांग्रेस की आमद को लेकर हो रही है। अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार से नाराज मतदाता ने इस दफा कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन अर्सा पहले ही बना लिया था। इसे भांपकर ही भाजपा आलाकमान ने राज्य में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने का दांव चला लेकिन तीरथ रावत को मात्र चार माह के भीतर हटा एक और नया मुख्यमंत्री देने के चलते यह दांव बैकफायर कर गया। देहरादून के सत्ता गलियारों में खबर गर्म है कि राज्य के नौकरशाहों ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कुछ नौकरशाहों ने तो मुख्यमंत्री धामी तक के कई आदेश मानने से इंकार कर डाला है। चर्चा जोरों पर है कि किसी मसले पर मुख्यमंत्री की अपने प्रमुख सचिव आंनदबर्धन संग तीखी तकरार तक हो गई। प्रदेश के वित्त सचिव अमित नेगी ने भी मुख्यमंत्री कार्यालय की कुछ फाइलों पर प्रतिकूल टिप्पणी कर डाली है।

कातिल भी खुद... मुंसिफ भी खुद

उपरोक्त पंक्तियां आपने अक्सर बातों-बातों में किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी। लेकिन इन पंक्तियों पर एक पुलिस अधिकारी खरे उतर रहे हैं। जिन साहब की यहां बात हो रही है वे प्रदेश की राजधानी और व्यावसायिक राजधानी के बीच में स्थित एक जिले के जिला मुख्यालय पर पदस्थ हैं। सूत्रों का कहना है कि यहां पदस्थापना के बाद से ही साहब ने कमाई के लिए ऐसा अनूठा तरीका अपनाया है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन साहब के इस अनूठे तरीके की चर्चा प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में होने लगी है। सूत्रों का कहना है कि साहब ने हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा वाले जिस तरीके को अपनाया है, उस पर ये पंक्तियां 'कातिल भी खुद... मुंसिफ भी खुद' सटीक भी बैठती हैं। बताया जाता है कि साहब का कमाई का तरीका यह है कि वे खुद ही मालदार और विवादित लोगों के खिलाफ शिकायत करवाते हैं फिर उसकी जांच में जुट जाते हैं। साहब की जांच ऐसी होती है कि केवल पैसे तक ही सीमित रहती है। शिकायत होने के बाद साहब तथाकथित आरोपी को तलब करते हैं और उनसे बेझिझक शब्दों में कहते हैं कि आपको केवल और केवल मैं ही बचा सकता हूं। और यह तभी संभव है, जब आप मेरी मनचाही रकम दे देंगे। केस और कानून के डर से लोग साहब की मनमानी पूरी कर देते हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मी की कृपा से साहब इस कदर बौराये हुए हैं कि इन दिनों वे हाईवे पर संदिग्ध परिस्थिति में देखे जा सकते हैं।

यहां सबको पैसा चाहिए

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक विभाग इन दिनों खासा चर्चा में है। दरअसल, यह विभाग निर्माण कार्य करवाता है। यानी इस विभाग से ठेकेदारों का लगातार वास्ता बना रहता है। यह विभाग पहले से ही इस कदर बदनाम है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहां बिना लक्ष्मी चढ़ाए कुछ नहीं होता। लेकिन अब तो सारी हदें पार हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब स्थिति यह है कि विभाग के मंत्रीजी के यहां अगर कोई ठेकेदार भुगतान के लिए फोन करता है तो फोन उठाने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि आपका भुगतान हो जाएगा, बस आप मुझे 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में दे दें। इससे लाखों-करोड़ों रुपए का निवेश कर निर्माण करने वाले ठेकेदार परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी राशि के भुगतान के लिए वे किसके पास जाएं। क्योंकि विभाग में तो ठेके से लेकर भुगतान तक का हिसाब-किताब बना हुआ है। हिसाब-किताब करने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए ठेकेदार मंत्रीजी के यहां गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी डिमांड बढ़ती जा रही है।

टूट गया याराना

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक आईपीएस अधिकारी और एक महिला एसआई की यारी खूब चर्चा में है। उक्त आईपीएस अधिकारी राजधानी के पड़ोस के एक जिले में पुलिस के बड़े पद पर पदस्थ हैं। जिले में पदस्थापना के बाद साहब को उक्त महिला एसआई से इतना याराना हो गया था कि उन्होंने उसे अपने पास पदस्थ कर लिया था। साहब ने यह पदस्थापना यह कहकर की थी कि उक्त महिला अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। लेकिन मामला दिन पर दिन इस कदर प्रगाढ़ होता चला गया कि साहब अक्सर उस महिला अधिकारी के साथ देखे जाते। साहब की यह यारबाजी कुछ लोगों को इस कदर नागवार गुजरी कि इसकी शिकवा-शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गईं। सूत्र बताते हैं कि उच्च निर्देशों के बाद साहब ने उक्त महिला अधिकारी को अपने यहां से हटाकर दूसरी जगह पदस्थ कर दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि उक्त आईपीएस अधिकारी और महिला अधिकारी की दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। साहब ने उन्हें भले ही अपने पास से हटा दिया है, लेकिन अभी भी वे साहब के दिल में बसी हुई हैं। साहब का जब भी मन करेगा, वे उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। यहां बता दें कि प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारी अक्सर जिलों का दौरा कुछ इसी उद्देश्य से करते हैं कि उक्त जिले में उनकी कोई न कोई महिला अधिकारी पदस्थ रहती हों। यहां तो बात एक ही जिले की है।

भोपाल बना पहली पसंद

प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर नौकरी के दौरान अफसरों की पहली पसंद होती ही है। अब तो ये दोनों शहर अफसरों के रिटायरमेंट के बाद भी पसंदीदा जगह बन गए हैं। कई अफसरों ने रिटायरमेंट के बाद इंदौर में अपना आशियाना बना लिया है, वहीं अधिकतर अफसर भोपाल को पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक एसीएस और एक सचिव ने यहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन खरीदी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे अपना आशियाना बना सकें। पिछले एक दशक के दौरान रिटायर होने वाले अफसर राजधानी के आसपास के सुरम्य क्षेत्रों में बंगला बनाकर रह रहे हैं। अभी हाल ही में कई अफसरों ने राजधानी के सघन वनक्षेत्र वाले क्षेत्र कोलार और केरवा में जमीनें खरीद ली हैं। कुछ अफसरों का यहां पर आशियाना बनना शुरू हो गया है तो कुछ का आने वाले दिनों में बनेगा। गौरतलब है कि भोपाल देश के उन शहरों में शामिल है, जहां पर जमीनों की कीमत सबसे अधिक है। फिर भी यह अफसरों की पहली पसंद बना हुआ है।

आशीर्वाद फलेगा या फूलेगा

अक्सर साधु-संत नमन के बाद आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कई बार उनके मुंह से ऐसे आशीर्वाद निकल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा ही एक आशीर्वाद इन दिनों प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आशीर्वाद ग्वालियर में आयोजित पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव के दौरान जैन मुनि श्री विजयेश सागर महाराज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया। मुनिश्री का आशीर्वाद सुनकर सिंधिया भी मंद-मंद मुस्कुराए। लेकिन उसके बाद प्रदेश में राजनीति का माहौल इस कदर गरम हो गया है कि लोग पूछने लगे हैं कि यह आशीर्वाद फलेगा या फूलेगा। गौरतलब है कि सिंधिया वर्तमान में जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में संघ की मंशा के अनुसार ही नेता का कद और पद तय होता है। वर्तमान में सिंधिया का कद भी बढ़ा है और पद भी बड़ा मिला है। और बड़े की मंशा तो हर किसी के मन में होती है, लेकिन वह पूरी होगी कि नहीं यह तो अपने वाला समय ही बताएगा।

8 साल बाद विधायकों को उत्कृष्टता पुरस्कार

संसदीय परंपरा में सांसदों और विधायकों के कार्यों का आंकलन कर सम्मान करने की परंपरा पुरानी है। मप्र में 2008 से पहले विधायकों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन कतिपय कारणों से यह बंद हो गया था। जिसे एक बार पुनः शुरू किया जा रहा है। इसके लिए विधायकों की परफॉर्मेंस का आंकलन हो रहा है।

मप्र विधानसभा सचिवालय एक बार फिर से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विधायकों की सदन में परफॉर्मेंस का आंकलन कराया जा रहा है। इस आंकलन के बाद विधायकों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। विधायकों के साथ ही उत्कृष्ट मंत्रियों और पत्रकारों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2008 से नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि बीच-बीच में प्रयास हुए, लेकिन चयन नहीं हो सका।

जानकारी के अनुसार 8 साल बाद एक बार फिर विधानसभा सचिवालय उत्कृष्ट मंत्रियों, विधायकों और पत्रकारों को पुरस्कार देने जा रहा है। इसके लिए चयन समितियां गठित की गई हैं। इनकी अनुशंसा पर ये उत्कृष्ट पुरस्कार दिए जाएंगे। पर इस बार विधायकों के लिए माइनस मार्किंग का पैटर्न भी रखा गया है। विधानसभा संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करती थी पर पिछले 8 सालों से ये पुरस्कार बंद थे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक बार फिर इन्हें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधायकों को कई कसौटियों पर परखा जाएगा। विधानसभा में विधायक जनहित के मुद्दे उठाएं। ज्यादा से ज्यादा समय तक उपस्थित रहें। चर्चा में भाग लें। इसे प्रोत्साहित करने विधानसभा श्रेष्ठ विधायकों का चयन करेगी। इसके लिए समिति विधायकों के काम-काज का मूल्यांकन कर रही है। प्रत्येक काम के अंक तय किए गए हैं। जनहित के मुद्दे उठाने, उनकी जागरूकता, बेहतर आचरण के अंक मिलेंगे। यदि कोई विधायक सदन की गरिमा के विपरीत आचरण करता है तो निगेटिव मार्किंग होगी।

उत्कृष्ट विधायक के लिए विभिन्न मापदंड तय किए गए हैं तथा उसके अंक भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें सदस्य का अनुभव, वाद-विवाद कौशल, जनहित के मुद्दों के संबंध में जागरूकता, उठाए गए मुद्दों का वैविध्य एवं गंभीरता, मुद्दे के प्रस्तुतीकरण का तरीका, भाषा पर नियंत्रण इन सभी के पांच-पांच अंक तय किए गए हैं। वहीं संसदीय नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान, उनका सदन के बाहर और भीतर पालन, सभा की स्थापित परंपराओं, रूढ़ियों एवं प्रथाओं के प्रति दृष्टिकोण, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में आस्था के 7 अंक तय किए गए हैं। अध्यक्ष तथा पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के पालन में बरती गई तत्परता, सदस्य का सदन के भीतर और बाहर आचरण के 5-5 अंक दिए जाएंगे। वहीं सभा की व्यवस्था एवं शांति के स्थापन में असहयोग और प्रतिगामी रूख पर 5 अंक माइनस कर दिए जाएंगे। इसी तरह सदन की गरिमा के विपरीत आचरण पर 10 अंक माइनस होंगे। आंसदी द्वारा दी गई व्यवस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने, अवहेलना करने या अनुचित ठहराने की प्रवृत्ति पर 5 अंक माइनस किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही में नियमित उपस्थिति पर 10 अंक, अन्य दलों के प्रति सहिष्णुता के 5 अंक, सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता तथा प्रस्तुति के ढंग पर 8 अंक और सभा के संचालन में गतिरोध की दशा में उससे उबरने में किया गया सहयोग एवं प्रयास के 10 अंक दिए जाएंगे। 20 अंक समग्र मूल्यांकन पर समिति अपने विवेक से देगी। यानी विधायकों का मूल्यांकन 100 अंको पर होगा।

मप्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि लंबे समय से बंद संसदीय पुरस्कारों को शुरू किया जा रहा है। यह बेहतर काम-काज को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। पुरस्कारों के लिए चयन समिति काम-काज का मूल्यांकन कर रही है। विधानसभा के संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2008 से नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि बीच-बीच में प्रयास हुए, लेकिन चयन नहीं हो सका। अब विधानसभा संसदीय पुरस्कार फिर शुरू कर रही है। इनमें श्रेष्ठ मंत्री, विधायकों के साथ ही विधानसभा के श्रेष्ठ अधिकारी, कर्मचारी का चयन भी होगा। इसके लिए गठित समिति ने पिछले सत्र में मंत्री, विधायकों के काम-काज का मूल्यांकन किया। एक-एक विधायक के काम-काज का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। उत्कृष्ट मंत्री का चयन सदन में दिए जाने वाले उसके उत्तरों की अभिव्यक्ति, शैली, गुणवत्ता समेत आश्वासनों की प्रतिपूर्ति, वाद-विवाद कौशल आदि को ध्यान में रख किया जाएगा। इसमें सदन में उठाए गए मुद्दों पर मंत्री का रूख, गंभीरता, भाषा पर नियंत्रण, संसदीय नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान, कार्यवाही में उपस्थिति आदि का भी ध्यान रखा जाएगा।

● **सुनील सिंह**

इन श्रेणियों में मिलेंगे उत्कृष्टता पुरस्कार

उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की स्मृति में दिया जाएगा। उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की स्मृति में और उत्कृष्ट संसदीय मीडिया पुरस्कार पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुनादेवी की स्मृति में प्रिंट मीडिया और वरिष्ठ पत्रकार मानकचंद वाजपेई की स्मृति में इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को दिया जाएगा। उत्कृष्ट विधानसभा अधिकारी पुरस्कार प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे की स्मृति में और उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदेश के प्रथम विधानसभा सचिव खं.के. रांगोले की स्मृति में दिया जाएगा। यह पुरस्कार साल में एक बार दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ग हेतु पुरस्कार की संख्या न्यूनतम एक और अधिकतम तीन होगी। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक शील्ड तथा चयन समिति द्वारा तय राशि का चैक दिया जाएगा।

कैग की रिपोर्ट को पीडब्ल्यूडी ने नकारा

दो साल से 95 फीसदी पर ही अटका है निर्माण कार्य

कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होने को है, भर्ती मरीजों की संख्या भी अब कम हो रही है। हमीदिया अस्पताल के डी ब्लॉक में बना कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी लगभग खाली पड़ा है। ऐसे में इस ब्लॉक में अब अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल डी ब्लॉक में अब भी कई निर्माण कार्य अधूरे हैं जिसे पूरा किए बिना विभाग नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किए जा सकते। शिफ्टिंग में हो रही देरी को लेकर हर बार बैठकें होती हैं, जिसमें निर्माणकर्ता कंपनी का जवाब होता है, सिर्फ 5 फीसदी काम बाकी है। बीते 2 साल से 5 फीसदी काम नहीं हो पाया। जब तक निर्माण कार्य 100 फीसदी पूरा नहीं होता, शिफ्टिंग संभव नहीं है। मामले में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद राय का कहना है कि कंपनी से लगातार बात चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते इसे कोविड ब्लॉक बना दिया गया था, अब यहां अस्पताल के शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। डी ब्लॉक में 6 मुख्य ऑपरेशन थिएटर बनाए जाने हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही तैयार हो पाया है। इन ओटी में ओटी लाइट के साथ स्टरलाइजेशन यूनिट तैयार करनी है। हमीदिया अस्पताल के पीछे बड़ा तालाब होने के कारण एसटीपी का वेस्ट कहां निष्पादित किया जाए, इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। इसे लेकर हमीदिया अस्पताल और पीसीबी के साथ-साथ नगर निगम भोपाल के बीच कई बार संवाद हो चुका है, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बनी है।

म प्र में निर्मित हो रही अधिकांश परियोजनाएं लेतलाली और भ्रष्टाचार का शिकार हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि लोक निर्माण विभाग में बैठे अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार की नाक के नीचे भी नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रही हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में सुनियोजित तरीके से घपला करने का मामला सामने आया है। कैग की रिपोर्ट में मामला उजागर होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की भर्राशाही जारी है। आलम यह है कि शासन के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने **ढाई माह** बाद शासन को रिपोर्ट भेजी है और उसमें कहा गया है कि सबकुछ नियमानुसार हुआ है।

गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में 6 साल से बन रही हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का काम पूरा होने के पहले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया है। यहां निर्माण कार्य का ठेका गुजरात के वडोदरा की कंपनी क्यूब कंस्ट्रक्शन के पास है। पीडब्ल्यूडी की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के अफसरों ने अनुबंध की शर्तों के खिलाफ जाकर कंपनी को तय मात्रा से ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल के नाम पर 3.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। ऑडिट में ये पकड़ में न आए, इसके लिए अफसरों ने प्री-बिड डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की ताकि भुगतान के बदले सरकारी वसूली से बचा जा सके। लेकिन कैग ने ऑडिट में धांधलियां पकड़ लीं।

कैग ने अफसरों की इस करतूत और वित्तीय अनियमितता पर सख्त आपत्ति जताई है। कैग ने कहा है कि निर्माण कार्य में न केवल कई कमियां हैं, बल्कि सरकारी पैसे का ज्यादा भुगतान करना पड़ा है। यही नहीं कैग ने ये भी कहा है कि ज्यादा लागत के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है। कैग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार किस तरह किया गया है, इसका भी जिक्र किया गया है। कैग के मुताबिक ठेकेदार से करोड़ों की वसूली न हो, इसलिए डीपीई ने **पेवमेंट शब्द** को पेयमेंट में बदल दिया। लेकिन जब लेखा परीक्षक ने मूल दस्तावेज के साथ डीपीई कॉपी की छानबीन की तो गलती पकड़ में आ गई। कैग ने कहा कि बीओक्यू (बिल ऑफ क्वांटिटी) के अनुसार दरें बताई गई हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि बीओक्यू केवल एस्टीमेट का भाग है। जबकि ठेकेदार और पीआईयू के बीच हुआ अनुबंध ही वह दस्तावेज है, जो दोनों के लिए बाध्यकारी है।

कैग की आपत्ति पर शासन ने अगस्त 2020 में जवाब दिया कि, ठेकेदार ने बीओक्यू पर दरें बताई थीं, न कि एसओआर पर। बीओक्यू में 330 किलोग्राम से कम या ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल करने पर यथास्थिति वसूली या अधिक भुगतान का प्रावधान है। इसलिए ज्यादा भुगतान किया। कैग की रिपोर्ट बताती है कि इस इमारत के लिए पीआईयू ने 1 अगस्त 2014 में टेंडर (एनआईटी) निकाले थे। शेड्यूल ऑफ रेट यानी एसओआर निर्धारित होने के पहले ही अफसरों ने कंपनी को फायदा देने का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने 7 नवंबर 2015 को प्रस्तावित एसओआर में संशोधन कर डिजाइन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन में 330 किग्रा-घनमीटर न्यूनतम सीमेंट उपयोग की सीमा तय कर दी।

इसके बाद राज्य शासन ने 10 दिसंबर को भवन निर्माण के लिए एसओआर तय की, जिसमें ये संशोधन शामिल था। ये एसओआर पीआईयू और निर्माण कंपनी के बीच हुए अनुबंध का भी हिस्सा थी। इस संशोधन के बाद भी डिजाइन मिश्रण में उपयोग होने वाले सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा इस्तेमाल होने पर शासन की ओर से भुगतान की अनुमति नहीं थी। लेकिन पीआईयू के दस्तावेजों से पता चला कि भवन निर्माण के तीन कामों में निविदा का प्रकाशन सीमेंट इस्तेमाल के निर्धारित मात्रा के संशोधन के काफी बाद किया गया। साथ ही डिजाइन मिक्स में निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त सीमेंट उपयोग के लिए कंपनी को 3.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान भी कर दिया गया। ये मामला सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसकी शिकायत शासन को भेजी थी। शासन ने इसकी जांच के लिए ईएनसी पीडीपीआईयू को भेजा। जब इस संदर्भ में **ईएनसी गोविंद मेहरा** से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे पता चला है कि एपीडी एसएल सूर्यवंशी ने इसका जवाब शासन को भेज दिया है। इस **संदर्भ में सूर्यवंशी** ने बताया कि कंपनी को टेंडर के तहत काम मिला है। कंपनी ने टेंडर और एग्रीमेंट के अनुसार काम किया है। ऑडिट में कहा गया है कि दरें कम की जाएं, जो नियमानुसार असंभव है। हमने शासन को यह रिपोर्ट भेज दी है।

● **रजनीकांत पारे**

परफार्मेंस का आंकलन

2018 में झटका खाई भाजपा 2023 के लिए कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। इसलिए पार्टी अभी से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। कभी सदस्यता अभियान, कभी सम्मान निधि समर्पण अभियान, तो कभी किसी बड़े आयोजन के नाम पर पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं पार्टी ने अभी से अपने मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस का आंकलन भी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी जल्द ही सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे के आधार पर ही जहां नई रणनीति बनेगी, वहीं टिकट तय होगा।

विधानसभा चुनाव में अभी 18 महीने बचे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। चूंकि दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए कोई भी पार्टी अभी से कोताही नहीं बरतना चाहती है। भाजपा संगठन अब अपने ही विधायकों के कामों का आंकलन एक सर्वे के माध्यम से करवाने जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव के टिकट तय किए जाएंगे। सर्वे एक निजी सर्वे एजेंसी द्वारा किया जाना है। हालांकि चुनाव के पहले भाजपा संगठन इस प्रकार के सर्वे गुपचुप करवाते रहता है। संगठन को रिपोर्ट मिलने के बाद उसका कितना पालन किया जाता है, यह तो भाजपा के कर्ताधर्ता ही जानते हैं, लेकिन अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के 18 महीने पहले ही भाजपा संगठन सर्वे करवाने जा रहा है। भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक संगठन ने इसके लिए एक निजी सर्वे एजेंसी से बात भी कर ली है और इसी एजेंसी के मार्फत सभी जिलों में सर्वे का काम जल्द शुरू होने वाला है। चूंकि अभी बूथ विस्तारक और समर्पण निधि का कार्यक्रम जिलों में चल रहा है और छोटे से कार्यकर्ता से लेकर नेता और मंत्री इसमें लगे हैं, इसलिए इसके निपटने के बाद सर्वे शुरू हो जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि सर्वे में विधायकों के कामों का आंकलन, उनका आम लोगों से व्यवहार, जनता में उनकी छवि, सरकार की योजनाओं का कितना फायदा लोगों को दिलवाया तथा संगठन में उनकी क्या भूमिका रही है, जैसे बिंदु शामिल किए जाएंगे। यही नहीं विधायक का अपने कार्यकर्ताओं से व्यवहार भी देखा जाएगा। इसके बाद हर विधानसभा के विधायक की रिपोर्ट बनाकर संगठन को पेश की जाएगी। संगठन के नेताओं का कहना है कि इसी को आधार बनाकर 2023 में टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। सर्वे इस तरह किया जाएगा कि इसकी भनक न तो स्थानीय संगठन के कर्ताधर्ताओं को होगी और न ही संबंधित विधायक को।

मप्र में इन दिनों सत्ता में होने के बाद भी भाजपा का संगठन पूरी तरह से एक्टिव मोड में बना हुआ है। इसकी वजह है अपने जन प्रतिनिधियों की कार्यशैली से लेकर उनकी इलाके में पकड़ तक का गोपनीय तौर पर पता लगाना। दरअसल यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की जा रही है। इसके दायरे में सांसदों को जहां केंद्रीय संगठन ने रखा है तो वहीं प्रदेश ने भी अपने स्तर पर सांसदों व विधायकों की जानकारी एकत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब प्रदेश में हालात यह हैं कि कौन जनप्रतिनिधि कब क्या कर रहा है इसकी पूरी जानकारी प्रदेश संगठन को मिल रही है। इस पूरी कवायद को चुनाव के समय टिकट के लिए किया जा रहा है। हालांकि यह तय है कि अब भाजपा में युवा पीढ़ी यानि की 30 से लेकर 60 तक की आयु के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा और संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी। इससे अधिक उम्र के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शक की भूमिका में भेज दिया जाएगा। प्रदेश में संगठन स्तर पर इस पर अमल पहले ही किया जा चुका है। इधर केंद्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश के विधायकों के लिए दो दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किए जाने की तैयारी है। यह प्रशिक्षण ऐसे समय किया जाना प्रस्तावित है, जब संगठन द्वारा प्रदेश के मंत्रियों की क्लास लगाई जा चुकी है। माना जा रहा है कि यह प्रशिक्षण शिविर जल्द लगाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष खुद मौजूद रहेंगे। इस दौरान विधायकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनसे उनके क्षेत्र में अब तक किए गए कामों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसमें विधायकों से यह भी पूछा जाएगा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं आमजन तक पहुंचे इसके लिए उन्होंने अब तक

'माननीयो' के विकास प्रस्ताव फाइलों में कैद

मप्र में सत्ता और संगठन ने सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और विकास कार्य करवाने का निर्देश दिया है। ताकि मिशन 2023 और 2024 को आसानी से फतह किया जा सके। लेकिन 'माननीयों' के सामने समस्या यह है कि उनके पहले के विकास प्रस्ताव फाइलों में कैद है। ऐसे में नए प्रस्ताव कैसे दें। जानकारी के अनुसार, 2018 में भी सत्ता और संगठन ने 'माननीयों' को निर्देश दिया था कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे बड़े पोजेक्ट तैयार करें जो सीधे जनता से जुड़े हैं। उधर, विधायकों की ओर से बात सामने आ रही है कि मिशन 2018 के लिए भी बड़े प्लान दिए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सांसद रहते ज्योति धुर्वे और आमला के विधायक रहे चैतराम मानेकर के प्रस्ताव शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने से करीब 400 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचे। उधर, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि विभाग द्वारा केंद्र को भेजे गए सभी प्रपोजल मंजूर कर लिए गए हैं तथा एक माह पहले राशि भी मिल गई है।

क्या किया। बताया जाता है कि संगठन विधायकों से कहेगा कि वे अपना सेल्फ असिसमेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। इसके बाद संगठन उसका परीक्षण करेगा। दो दिनी प्रशिक्षण शिविर में विधायकों को चाल, चरित्र, चेहरे और व्यक्तित्व विकास, राजनीतिक कौशल समेत अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है। दरअसल यह पूरी कवायद मिशन 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों को दी गई नसीहत के बाद संगठन द्वारा अपने सांसदों के ढाई साल के कामों का ऑडिट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह काम एक निजी एजेंसी से कराया जा रहा है। इसमें सांसदों के काम-व्यवहार, क्षेत्र में सक्रियता के साथ अन्य मुद्दों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर ही उनका अगले चुनाव में टिकट तय होगा। यह ऑडिट अगले माह से शुरू होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में हाल ही में भाजपा सांसदों की बैठक में सांसदों द्वारा अनुशासन का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की थी। उनकी नाराजगी के बाद ही संगठन ने अब सांसदों का ऑडिट कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जल्द ही राज्यवार सांसदों की बैठक लेने जा रहे हैं। सांसदों के काम का संगठन एजेंसी से पूरा लेखा-जोखा तैयार करवाने जा रहा है। जिसमें उनके संसद सत्रों के कुल दिनों और घंटों समेत उपस्थिति, क्षेत्र से संबंधित क्या सवाल लगाए और संसद की बहस में हिस्सा लेने को शामिल किया जाएगा। इसके बाद उनके क्षेत्र में जाकर टीम यह सर्वे करेगी कि सांसद दिल्ली व प्रदेश की राजधानी में कितने और अपने क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं। इस दौरान उनकी क्षेत्र में हर दिन रहने वाली दिनचर्या की भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा सांसद ने पिछले ढाई सालों में क्षेत्र में कहां-कहां और कितने दौरे किए और पार्टी संगठन की बैठकों में उनकी मंडल, जिला और प्रदेशस्तर पर कितनी सक्रियता रही इसका भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य दो दर्जन बिंदुओं पर भी जानकारी ली जाएगी।

सर्वे टीम द्वारा सांसदों के इलाकों में जाकर कई तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी, जिसमें उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, किसानों से जुड़ी योजनाएं समेत अन्य योजनाओं का क्षेत्र में किस तरह और कितना क्रियान्वयन हुआ। इनके क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए किस तरह की रणनीति पर अमल किया गया और किन क्षेत्रों में कितने कैंप लगाए गए और इसमें से कितनों में सांसद मौजूद रहे। जिले के संगठन नेताओं से सांसद का तालमेल कैसा है। पार्टी के संगठनात्मक अभियानों में कितनी भागीदारी रहती है। संसद में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितने प्रश्न लगाए और अन्य किन तरीकों से उठाया। क्षेत्र की 5 मुख्य समस्याओं में किनको कितना सुलझा पाए और क्षेत्र में प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं को कितना वक्त देते हैं। पार्टी के जिला और मंडल कार्यालय कितनी बार जाते हैं और क्षेत्र में मौजूद होने पर संगठन की बैठकों में कितनी रूचि लेते हैं।

भाजपा विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुट गई है। सत्ता और संगठन के चुनावी मोड में आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। विस्तार को प्रदेश कार्यसमिति में हरी झंडी दिखाई जाएगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि परफॉर्मेंस के आधार पर 8 से 10 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं मंत्रियों का विभाग भी बदला जाएगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार के करीब एक दर्जन से अधिक मंत्रियों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं पाई गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल बड़े स्तर पर होगा और नकारा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही दो साल से कम समय है, इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी से चुनावी मोड में आते दिखने लगे हैं। यही वजह है कि उनके इस मोड में बाधा बनने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति वर्ष 2018 के चुनाव परिणामों की तरह रहे।

● **कुमार राजेन्द्र**

भाजपा हर गांव में तैयार करेगी 5-5 किसान

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को गांवों में करारी शिकस्त मिली थी, जिन्हें मजबूत करने के लिए संगठन अभी से जुट गया है। अपनी विचारधारा से जुड़े हर गांव में 5-5 किसानों की समिति बनाई जा रही है, जो मोदी और शिवराज सरकार की कल्याण योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगी। भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मूल संगठन ने बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से बूथ इकाइयों को दमदार बनाने का प्रयास किया, जिसके चलते हर बूथ पर 15 से 20 सदस्यों की सूची बना ली है, जो अब पार्टी के पास ऑनलाइन है। इसके अलावा सभी मोर्चा-प्रकोष्ठों को भी काम सौंपा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसान मोर्चा को दिया गया। वह गांव-गांव जाकर किसानों को संगठन से जोड़ने का काम करेगा। प्रदेश संगठन ने समिति के गठन की व्यवस्था ठीक बूथ विस्तारक अभियान की तरह की है। उसके जैसे ही रजिस्टर में एंट्री होगी ताकि सभी के नाम, नंबर और पते हों जिससे कभी भी संपर्क किया जा सके और उनके सोशल मीडिया के माध्यम से समय-समय पर जानकारी भी दी जा सके। बड़ी बात ये है कि इन समिति में उनको नहीं लिया जाएगा जिन्हें बूथ समिति का सदस्य बनाया जा चुका है। ये सदस्य अलग से ही होंगे। योजना के हिसाब से प्रत्येक गांव में 5-5 किसानों की समिति बनाई जाएगी। इन समितियों से संपर्क की जिम्मेदारी मंडल व विधानसभा के किसान मोर्चा की होगी। गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर व जिला मोर्चा मिलकर एक बड़ा सम्मेलन करेगा, जिसमें सभी समितियों के सदस्यों को बुलाया जाएगा। उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। संख्या पर फोकस रहेगा तो उन्हें संबोधित करने के लिए प्रदेश के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे।

अगला पीसीसी चीफ कौन?

मप्र में 20 अगस्त तक पार्टी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है। जो भी अध्यक्ष बनेगा, पार्टी उसके नेतृत्व में ही 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस वजह से हर गुट अपना प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहता है। ऐसे में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ को चुनौती देने के लिए नेताओं की लामबंदी शुरू हो गई है। विरोधियों के चेहरे के तौर पर दिग्विजय सिंह और अरुण यादव साथ आ सकते हैं। बीते दिनों के समीकरण इस ओर इशारे भी कर रहे हैं।

पिछले साल मार्च में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 विधायकों को साथ लेकर भाजपा में शामिल हुए थे, तब गुटबाजी सतह पर आ गई थी। पार्टी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। हर उपचुनाव में एक जैसे मुखौटे लगाकर सामने आए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के अंदरुनी सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ के खिलाफ अन्य नेताओं की लामबंदी तेज हो गई है। एक व्यक्ति एक पद के मुद्दे पर कमलनाथ का विरोध बढ़ रहा है। कमलनाथ इस समय दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की। मुख्यमंत्री रहते हुए भी कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद अपने पास रखा था। इसे लेकर विरोध के सुर तेज होते रहे हैं। यह बात अलग है कि हर बार आलाकमान के दबाव में विरोध को दरकिनार कर दिया गया।

पिछले कुछ समय से दिग्विजय सिंह की सक्रियता देखते ही बनती है। पिछले 6 महीने से उनके पैर किसी एक जगह ठहरे नहीं हैं। कभी खंडवा, खरगौन तो कभी रतलाम तो कभी ग्वालियर। वे प्रदेश में जितना सक्रिय दिख रहे हैं, उतना तो कोई है ही नहीं। जाहिर है कि वे इसके जरिए कमलनाथ के खिलाफ लामबंदी भी कर रहे हैं। पिछले दिनों वे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के गृह ग्राम में थे। उन्होंने कार्यक्रमों में भी साथ में भाग लिया। उसी दिन भोपाल में कमलनाथ जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे। मीडिया में भी बैठक से यादव-सिंह की दूरी ने ही सुर्खियां बटोरीं। उनके नाम लिखी खाली कुर्सियों के फोटो और वीडियो हर जगह दिखाई दिए। भाजपा ने भी इसे लेकर कांग्रेस की खिंचाई करने में कोई कोताही नहीं बरती।

यादव की कमलनाथ से नाराजगी नई नहीं है। बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल करने से लेकर खंडवा लोकसभा उपचुनावों में उनकी निष्क्रियता पर टकराव साफ दिखा है। दिग्विजय सिंह ने बुरहानपुर में कह दिया कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कोई युवा होना चाहिए। बगल में अरुण यादव खड़े थे। साफ है कि उनके निशाने पर कमलनाथ थे। आखिर, किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह व कमलनाथ की बहस का वीडियो भी वायरल हुआ था। साफ है कि दोनों में संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जितने दिखाने की कोशिश हो रही है।

दिग्विजय सिंह की सक्रियता देखकर लग रहा है कि वे अपने किसी करीबी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहते हैं। कमलनाथ से नाराज नेताओं को लामबंद कर रहे हैं। सरकार गिरने के बाद के उपचुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे कमलनाथ कांग्रेस कैडर में नया जोश भरने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इसी का लाभ दिग्विजय सिंह उठाना चाहते हैं। युवा मुख्यमंत्री की बात कहकर उन्होंने एक तरफ से युवाओं को भी अपनी ओर मोड़ लिया है। वहीं, कमलनाथ खेमा भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपने करीबी को बिठाना चाहता है। आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन खेमा किसे आगे बढ़ाता है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अगले अध्यक्ष का फैसला आलाकमान ही करेगा। अब तक ऐसा ही होता आया है। राहुल गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अरुण यादव पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। कमलनाथ खेमे से सज्जन सिंह वर्मा का नाम आगे चलाया जा सकता है। दूसरी ओर, प्रदेश के मंत्री रहे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, पार्टी के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा समेत कुछ अन्य नाम भी चर्चा में सामने आ रहे हैं।

उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठकें करके पदाधिकारियों को चुनावी मोड में ला रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिनों मप्र कांग्रेस के अंतर्गत कार्यरत समस्त विभागों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागों, प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा की गई। कमलनाथ ने कहा कि प्रकोष्ठों से सभी अध्यक्ष अपने-अपने कार्यों की रूपरेखा प्रत्येक माह की तैयार कर प्रदेश कांग्रेस को प्रस्तुत करें। कार्यों का संचालन करने के बाद प्रत्येक माह अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस को प्रस्तुत करें, ताकि उनके कार्यों का मूल्यांकन हो सके। जो अध्यक्ष संगठनात्मक गतिविधियों को सुदृढ और मजबूती प्रदान करने में अपने आप को सक्रिय महसूस नहीं करते हों, वे सूचित करें, ताकि उनके विकल्प के रूप में कार्य संचालित किया जा सके। प्रकोष्ठों का काम उन लोगों को जोड़ना है, जो सामने नहीं आते।

● **अरविंद नारद**

मिशन मोड में कांग्रेस

भाजपा की देखा-देखी अब कांग्रेस भी पूरी तरह मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी अब मिशन मोड में काम करेगी, ताकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत सके। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ निरंतर बैठकें कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं। गत दिनों उन्होंने पदाधिकारियों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि आने वाले 19 महीने हमारे लिए परीक्षा की घड़ी हैं। हमें लेटर हेड, रबर स्टांप तक सीमित न रहते हुए जमीन पर काम दिखाने की जरूरत है। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं, बल्कि एक ऐसे भाजपा संगठन से है, जो गुमराह और भ्रमित करने, ध्यान मोड़ने की राजनीति और कलाकारी करने वाला संगठन है। हमारी लड़ाई झूठ और दुष्प्रचार से है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा, इसलिए जैसा कि मुझे बताया गया है कि प्रत्येक विभाग, प्रकोष्ठों द्वारा पांच-पांच हजार नए सदस्य बनाए जाएंगे। इसका कार्य चल रहा है, लेकिन गतिशीलता लाने के लिए आवश्यक रूप से शीघ्रता से यह कार्य पूर्ण किया जाए। नाथ को सभी विभागों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने कार्यों की गतिविधियों से अवगत कराते हुए जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिलाने का आग्रह किया, जिसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि विभाग, प्रकोष्ठ जितनी गतिशीलता से काम करेगा, उनको उतना सम्मान मिलेगा।

अधोसंरचना विकास पर जोर

भले ही मप्र में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन वर्ष 2022-23 का बजट चुनावी ही रहेगा। इसमें अधोसंरचना विकास पर खासा जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति दी जाएगी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के विधायक लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। सड़क, पुल-पुलिया के साथ मेडिकल कॉलेज, स्कूल सहित अन्य भवनों का निर्माण होगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेशकों को सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। भोपाल-इंदौर के बीच मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना है तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 14 क्लस्टर प्रस्तावित हैं। प्रदेश में अधोसंरचना विकास की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसकी गति और बढ़ाने के लिए बजट में प्रविधान किए जाएंगे।

दरअसल, इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य एक तीर से दो निशाने साधने का है। रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता है। अधोसंरचना विकास का क्षेत्र ऐसा है, जो सर्वाधिक रोजगार देता है। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था में गति आती है। इसके मद्देनजर सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अटल एक्सप्रेस-वे को भारत माला परियोजना के प्रथम चरण में शामिल किया जा चुका है। 105 ओवर ब्रिज स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 36 के टेंडर की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

हाल ही में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड बनाने और 56 शहरों में आंतरिक सड़कों को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अब इसे भारत माला परियोजना में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के कामों को गति दी जाएगी। दरअसल, सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों ने इसकी मांग की है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपए के कामों के जो प्रस्ताव दिए हैं, उनमें 90 प्रतिशत अधोसंरचना विकास से जुड़े हैं।

आगामी 3 वर्षों में 3 लाख 75 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों के माध्यम से सरकार की गारंटी पर जुटाए जाएंगे। नर्मदा नदी से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ काम प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल, वर्ष 2024 में नर्मदा जल बंटवारे को लेकर नए सिरे से कवायद होगी। नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग को सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए बजट में अधिक राशि दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट में पिछली बार 79 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इस बार भी विभाग को अधिक राशि दी जाएगी। मई 2023 तक पूरी होने वाली समूह नलजल योजना को फास्ट ट्रेक पर क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं, आगामी समय में बिजली की मांग को देखते हुए नए ताप विद्युत गृह की स्थापना, वितरण व्यवस्था में सुधार, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार काम करेगी। इसकी कार्ययोजना बजट में प्रस्तुत की जाएगी। 2023 तक 45 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, आगर, शाजापुर, नीमच और छतरपुर सोलर पार्क को भी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दिसंबर 2023 तक कम आय वर्ग को तीन लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में प्रविधान होगा। प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस बार अधिक बजट देना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भू-अधिकारी आवासीय योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रविधान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार भोपाल और इंदौर के बीच मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अटल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ 20 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसकी रूपरेखा सरकार बजट में प्रस्तुत करेगी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

रोजगार के अवसर पर फोकस जरूरी

इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोनाकाल में रोजगार के अवसर घटे हैं। पंजीयन कार्यालयों में लगभग 34 लाख बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार भी यह भली-भांति समझ रही है, इसलिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आरक्षक के 6 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है तो 1 हजार 955 इंजीनियरों की भर्ती संयुक्त परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। 25 फरवरी को फिर से रोजगार दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय बजट में इस बार मनरेगा की राशि घटाई गई है। इसका असर मप्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि मप्र देश के उन राज्यों में है जहां इसके माध्यम से न सिर्फ बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। प्रदेश को राजस्व के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसका लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते, पेंशन और ब्याज की अदायगी पर खर्च होता है। वेतन, पेंशन और भत्ते पर सालभर में 60 हजार करोड़ रुपए के आसपास खर्च होते है। वहीं, ब्याज और कर्ज की किश्त चुकाने में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए सालाना लगते हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने ब्याज अदायगी के लिए 2 हजार 360 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है।

रिपेरियन जोन में अवैध खनन

रोक के बावजूद हो रहा अवैध रेत का खनन और परिवहन

एनजीटी की रोक के बाद भी तवा नदी से अवैध रेत का खनन जारी है। रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली सरेआम नगर में मेन रोड सहित गलियों में देखे जा सकते हैं। अवैध रेत खनन करने में 50 से अधिक ट्रैक्टर-ट्राली लगे हुए हैं, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। नगर के प्रमुख मार्गों से ट्राली निकलती है। यहां तक कि मेन रोड सबसे व्यस्ततम क्षेत्र पीपल चौक एवं ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पुलिस चौकी के सामने से अधिक स्पीड में निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा सदैव बना रहता है। जब जिले में रेत खनन पर पाबंदी है फिर भी नगर के मार्गों से रेत की ढुलाई हो रही है। जिन अधिकारियों के ऊपर अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी है उन्होंने सांठगांठ कर ली है। रात एवं दिन में रेत की ढुलाई के कारण लोगों की नींद हराम हो रही है। सेमरी हरचंद में दिनभर में लगभग 40 से 50 अवैध रेत के ट्रैक्टर-ट्राली रेत डल रही है। रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे इनके हौंसले बुलंद हैं। रेत बगैर रॉयल्टी के बाजार में बिक रही है। इसी रॉयल्टी से जिले में अनेक विकास कार्य होते थे। परिवहन विभाग द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर इनको छोड़ रखा है। ट्रैक्टर में लगी ट्राली का कमर्शियल पंजीयन नहीं है। ट्रैक्टर का पंजीयन भी कृषि कार्य हेतु किया गया है, जबकि वह भी कमर्शियल कार्य कर रहा है। रेत सरेआम बिक रही है। बेचने वाले के द्वारा किसी प्रकार की कोई बिलिंग नहीं हो रही है। जिससे आयकर विभाग को भी बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। रेत के इस पेपर में होने वाली आय का कहीं कोई अता-पता नहीं है जबकि प्रतिदिन मात्र सेमरी हरचंद में लाखों रुपए की रेत बिक रही है। आखिर क्यों और किसने इनको छूट दे रखी है यह एक चिंतन का विषय है। अब देखना यह है कि इन पर कब तक कार्रवाई होती है।

प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में रेत माफिया की सक्रियता बढ़ गई है। हालात यह है कि नर्मदा किनारे रिपेरियन जोन से ही माफिया रेत निकाल रहे हैं। नर्मदापुरम जिला प्रशासन रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन नहीं रुक रहा है। इतना ही नहीं रेत का भंडारण भी माफियाओं ने कर रखा है। जिले की रेत खदानों पर रात के समय में रेत माफिया के गुर्गे बेधड़क रेत निकाल रहे हैं। वहीं जिले के सामने स्थित नर्मदा तट से रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत निकाल रहा है। सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाली रेत खदान पर भी दिन दहाड़े रेत माफिया ट्रैक्टर ट्राली से रेत का उत्खनन कर रहा है। रेत माफिया के कारण जलीय जीव जंतुओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपेरियन जोन में रेत माफिया के बढ़ते दखल के कारण मछलियों और अन्य जलीय जीव-जंतु समाप्त होते जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने नर्मदा को चार जोन में बांटा है। रिपेरियन जोन एक से लेकर रिपेरियन जोन चार तक अलग-अलग भाग किए गए हैं। तत्कालीन कमिश्नर के निर्देशन में पर्यावरणविद व मप्र जैव विविधता बोर्ड के सदस्य आरआर सोनी ने सर्वे कर नर्मदा के जोन की रिपोर्ट तैयार कर सौंपी। रिपेरियन जोन एक में सर्वाधिक पानी रहता है। यह क्षेत्र जलीय जीवों के विचरण और वनस्पतियों के लिए सबसे उपयुक्त है। रिपेरियन जोन दो किनारे और गहरे पानी के बीच का हिस्सा कहलाता है। यह क्षेत्र जलीय जीवों के प्रजनन और **आवास के अनुकूल** रहता है। रिपेरियन जोन तीन में किनारे से लगा जमीनी हिस्सा रहता है। जिस पर सर्वाधिक पौधारोपण का दावा किया गया है। रिपेरियन जोन चार किनारे से दूर ठोस जमीन है। जहां पौधारोपण सहित अन्य अभियान चलाए जाते हैं।

जिला प्रशासन की सख्ती के कारण रेत माफिया दिन के समय तो शांत रहता है, लेकिन देर रात माफिया की सक्रियता बढ़ जाती है। बांद्राभान, मरोड़ा, बुधनी, गूजरवाड़ा, पिपरिया, रायपुर की रेत खदानों से चोरी छुपे रेत निकाली जा रही है। सूत्रों की माने तो रेत माफिया के गुर्गे रेत उत्खनन के दौरान सभी जगह तैनात रहते हैं। जिला प्रशासन व खनिज अमले की कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के बाद भी कार्रवाई की गोपनीय सूचना लीक हो गई थीं। अमला कार्रवाई करने के लिए पहुंचा तो था, लेकिन खाली हाथ लौटा। रेत माफिया के कारण पर्यावरण को लेकर काम करने वाले संगठनों की सक्रियता भी कम हो गई है। स्वयंसेवी संगठन के सदस्य भी पर्यावरण को लेकर किसी तरह का अभियान नहीं चला पा रहे हैं। एक संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि जब तक रेत माफिया को नहीं रोका जाता तब तक पर्यावरण पर बढ़ते खतरे को नहीं रोका जा सकता।

जिले के सबसे बड़े विकासखंड पिपरिया व बनखेड़ी में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। रेत ठेकेदार कंपनी आरकेटीसी द्वारा रेत खदान सरेंडर करने के बाद रेत माफिया नदियों से बेरोकटोक अवैध खनन कर रहा है। जिन्हें रोकने में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रेत का अवैध खनन जोरों से जारी है। खनिज विभाग एवं स्थानीय प्रशासन शिकायत करने पर थोड़े समय के लिए कार्रवाई करता है। जिससे कुछ दिन तो खनन रुक जाता है। बाद में फिर खनन माफिया रेत का अवैध खनन करने लगता है।

जिला समन्वयक मप्र जैव विविधता बोर्ड आरआर सोनी कहते हैं कि नर्मदा के रिपेरियन जोन से रेत निकाली जा रही है जो कि काफी दुखदायी स्थिति है। रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। नर्मदा किनारे से जिस तरह से रेत का उत्खनन किया जा रहा है उससे जलीय जीव-जंतुओं पर भी खतरा है। जिला खनिज अधिकारी, नर्मदापुरम शशांक शुक्ला ने बताया कि जिले में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए नजर रखी जा रही है। लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। नर्मदा व तवा किराने सर्चिंग की जा रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

शहरों-गांवों का जन्मदिन

मप्र की शिवराज सरकार देश में नवाचारों की सरकार के रूप में ख्यात होती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए-नए नवाचारों के साथ जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव और कस्बों का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव जैत से की है। बाद में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो प्रमुख नगरों- राजधानी भोपाल का जन्मदिन हर साल 1 जून को और व्यावसायिक राजधानी इंदौर का जन्मदिन 31 मई को मनेगा। इन तारीखों के निर्धारण का आधार पूर्व नवाबी रियासत भोपाल के भारत संघ में विलीनीकरण का दिनांक और इंदौर का जन्मदिन पुण्यश्लोका अहिल्याबाई का जन्मदिन 31 मई है।

बाकी शहरों का जन्मदिन तय करने हर शहर का गजेटिर तैयार करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यह काम बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक पूरा करना है। गजेटियर तैयार होते ही लोगों से मशविरा कर शहर का जन्मदिन तय किया जाएगा। इस पहल का राजनीतिक स्तर पर अभी किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि इसका बाहरी स्वरूप सामाजिक ही है। विरोधी दल इसकी सियासी संभावनाओं को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं।

यूं तो पहली नजर में यह अपने अतीत को याद करने की मोहक पहल दिखाई पड़ती है, लेकिन परोक्ष रूप से शहरों के उस हिंदू इतिहास को जागृत या स्मरण कराना है, जो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सके। यूं भी किसी शहर या गांव का जन्मदिन तय करना आसान काम नहीं है। इस देश में गिने-चुने शहर या गांव होंगे, जिन्हें किसी ने सुनियोजित तरीके से बसाया हो, उसका नामकरण किया हो। कोई गांव कब बस जाता है, धीरे-धीरे कब शहर में बदल जाता है, कोई शायद ही महसूस करता हो।

दरअसल यह किसी नन्हीं बिटिया के जाने-अनजाने युवावस्था को प्राप्त होने जैसा है। बस, गांव है कि बस जाता है। कुछ लोग बस्ती बसाते हैं फिर गांव में तब्दील हो जाती है और बरसों में वही गांव शहर का रूप ले लेता है। किसी एक गांव में पहले चरण किसके पड़े, किसने उस गांव का नाम रखा, क्यों रखा, इसका लिखित इतिहास तो छोड़िए, किंवदंतियों या लोक कथाओं में जिक्र शायद ही मिलता है। बावजूद इसके हर गांव और शहर का इतिहास तो होता है मगर उसे याद करने वाले बहुत कम होते हैं।

जन्मदिन निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री ने जो टास्क सरकारी अमले को दिया है, उसे पूरा करना आसान नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मप्र में 5 बड़े शहरों सहित 16 नगर निगम, 100 नगर पालिकाएं और 264 नगर पंचायतें हैं। ये सभी शहरी क्षेत्र हैं। इनके अलावा प्रदेश के 52 जिलों में कुल 51 हजार 517 गांव हैं। हरेक का गजेटियर तैयार करने और उनकी जन्मतिथि तय करना टेढ़ी खीर है। इस नवाचार की शुरुआत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैतृक गांव जैत से हुई। सीहोर जिले का जैत नर्मदा किनारे बसा गांव है। इस गांव का जन्मदिन नर्मदा जयंती 8 फरवरी को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन ये मुहिम भी शुरू हुई कि क्यों न हर गांव और शहर का भी जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। जैत के 'गौरव दिवस' में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज, उनके परिजन, आला अफसर बैठे थे तो दूसरी तरफ ग्रामसभा बैठी थी। शिवराज ने कहा कि जन्मदिन सार्वजनिक रूप से मनाने का मकसद गांव अथवा शहर का जनता की भागीदारी के साथ विकास करना है। क्योंकि सरकार का पैसा भी जनता का ही पैसा है। गांव का भला तभी होगा, जब गांव वाले ऐसा चाहेंगे। इसके दो माह पहले मुख्यमंत्री ने श्योपुर में 'बेटी बचाओ' और 'लाडली लक्ष्मी अभियान' को गति देने के लिए ऐलान किया था कि हर आंगनवाड़ी में माह के तीसरे मंगलवार को नवजात बेटियों का लाडली जन्मोत्सव मनेगा। उद्देश्य यही कि लोग बेटी के जन्मदिन को बोझ न मानकर वरदान मानें। इसके पहले एक और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए शहरी विकास के पांच मंत्र भी गिनाए। जिसके मुताबिक हर नगर, राज्य के विकास का चेहरा बने, शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो, हर नगरवासी को जीवन की गुणवत्ता मिले, शहरों के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं कम हों तथा सभी को सम्मान से जीवन-यापन का अवसर उपलब्ध हो। बहरहाल नगर जन्मदिन मनाने की इस पहल से एक नई हलचल तो हुई है। अटकलों, तर्कों और ऐतिहासिक तथ्यों, किंवदंतियों का बाजार गर्म हो गया है।

अब सवाल यह है कि गांव, शहर का जन्मदिन तय कैसे हो? क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलना दूभर हैं। इसे देखते हुए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामसभा की बैठक बुलाकर ग्राम गौरव दिवस तय करने के लिए गांव के किसी ऐतिहासिक दिवस को, गांव के किसी महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध पुरुष-महिला के जन्मदिन को ग्राम गौरव दिवस के रूप में तय किया जाए। प्रदेश के कुछ जिलों में इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस पूरी कवायद का मकसद है कि प्रेम, सद्भाव, समरसता और सद्भाव ग्रामीण जीवन का मूलतत्व है। अपने खूबसूरत इतिहास, परम्परा के कारण हर गांव की विशिष्ट पहचान होती है। गांव गौरव दिवस उसी पहचान को कायम रखने का प्रयास है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

जन्मदिन की तिथि पर गर्माएगी राजनीति

मप्र का यह नवाचार अमूमन नेताओं और महापुरुषों की जन्मदिन मनाने और ऐसे आयोजनों को पूरा राजनीतिक रंग देने से थोड़ा अलग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य वही है। जहां तक भोपाल की बात है तो भोपाल के नवाबी रियासत से मुक्त होने और इसके लोकतांत्रिक गणराज्य का हिस्सा बनने की तिथि को शहर का जन्मदिन मान लिया गया है। भोपाल का विलीनीकरण 1 जून 1949 को हुआ था। उसी तरह इंदौर का जन्मदिन होलकर शासिका देवी अहिल्या बाई के जन्मदिन को माना गया है। हालांकि इस पर इतिहासकारों और राजनेताओं में कुछ मतभेद थे। मप्र के उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर आदि शहर भी बहुत प्राचीन हैं। इन्हें किसने और कब बसाया, इसकी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में वो तारीख तय की जाएगी, जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो। हो भी यही रहा है।

मप्र जैविक खेती करने वाला देश का नंबर-1 राज्य बन गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां के माननीय अभी भी परंपरागत खेती कर रहे हैं। दरअसल, प्रदेश सरकार के अधिकांश मंत्रियों और विधायकों ने अपना पेशा तो खेती-किसानी बताया है, लेकिन वे इसमें अपना समय नहीं देते हैं। ऐसे में वे प्रदेश सरकार के नवाचार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

'माननीयों' को नहीं भायी जैविक खेती

मप्र जैविक खेती और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात में देश में अव्वल है। प्रदेश में लगातार जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन रासायनिक खेती का उपयोग कम नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह यह है कि प्रदेश के माननीयों (सांसदों, मंत्रियों, विधायकों) का जैविक खेती से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश सरकार के 23 मंत्रियों का पेशा भी खेती किसानी है, लेकिन उनमें से अधिकांश जैविक खेती से काफी दूर हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तय किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जैविक व प्राकृतिक खेती का मॉडल पेश करने के लिए कहा है, लेकिन अधिकतर मंत्री अभी खेती के प्रयोगों से दूर हैं। मुख्यमंत्री खुद प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन उनके मंत्रीगण परंपरागत खेती की राह पर हैं। शिवराज अनार से लेकर आम तक उगाते हैं, लेकिन उनके मंत्रीगण प्राकृतिक व जैविक खेती से दूर हैं।

मप्र जैविक खेती और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात में देश में अव्वल है। प्रदेश में लगातार जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में 11 लाख 56 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही थी। जबकि, वर्ष 2020-21 में यह क्षेत्र बढ़कर 16 लाख 37 हजार हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से पांच लाख टन जैविक उत्पाद का निर्यात हुआ, जो ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक का था।

प्रदेश सरकार के 30 मंत्रियों में से 23 मंत्री खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर खेती-किसानी के प्रयोगों से दूर हैं। इसकी बड़ी वजह खेती के लिए अमले पर निर्भर रहना है। ऐसे में मंत्रीगण ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद अब तक प्राकृतिक व जैविक खेती को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। प्रदेश सरकार के जिन 23 मंत्रियों का पेशा खेती किसानी है उनमें अरविंद भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिंह सिसौदिया, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कमल पटेल, प्रभुराम चौधरी, बिसाहूलाल सिंह, इंदर सिंह परमार, विजय शाह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तुलसी सिलावट, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, ओमप्रकाश सखलेचा, ओपीएस भदौरिया, भारत सिंह कुशवाह, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव और रामखिलावन पटेल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जैविक खेती के लिए कुछ मंत्रीगण तैयारी कर रहे हैं।

जैविक खेती में देश में अग्रणी है मप्र

प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि देश के अन्य प्रदेश आज जब जैविक खेती की दिशा में कार्य शुरू कर रहे हैं तो मप्र की तारीफ करनी होगी जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वर्ष 2011 में ही जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू कर दिया था। इसी का परिणाम है कि मप्र को न केवल जैविक कृषि लागू करने वाला देश के पहले प्रदेश बल्कि देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश होने का गौरव भी

हासिल है। कृषि के क्षेत्र में मप्र की अपनी विशेषताएं हैं और यह पिछले डेढ़ दशक में प्रमाणित भी हुआ है। इस अरसे में प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेती-किसानी नुकसान के जाल से बाहर निकली। अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का फल वाजिब दामों के रूप में मिला। प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की बेरूखी से होने वाले नुकसान के समय में सरकार के किसानों के साथ खड़े होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य लगातार बेहतर हुआ। आर्गेनिक वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के आधार पर वर्ष 2019 में विश्व का 72.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती हेतु उपयोग में लिया गया है। इसमें एशिया का 5.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती में वृद्धि हुई है जिसमें मप्र जैसे राज्यों का विशेष योगदान है। इसका मुख्य कारण अधिक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाला दुष्प्रभाव हैं, जिसने सरकार को इस दिशा में विचार करने के लिए प्रेरित किया। जैविक खेती के अंतर्गत मुख्यतः खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, सब्जियां तथा बागान वाली वाली फसलों का उत्पादन किया जा रहा है।

पहले कुछ एकड़ में प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मुख्यत: खेती का व्यवसाय करते हैं। अभी तक उन्होंने जैविक व प्राकृतिक खेती नहीं की है। प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अभी तक जैविक खेती नहीं की है, लेकिन इस बार दो एकड़ में यह प्रयोग करने का विचार है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अन्य कई मंत्री परंपरागत खेती ही करते हैं। लेकिन अब जैविक खेती की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं, जिन्होंने रिकार्ड पर खुद को किसान बताया है, लेकिन खेती से दूर ही रहते हैं। इनमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं। इंदर की सीधे तौर पर कोई खेती नहीं है। इसी तरह सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी मुख्य रूप से खेती का रिकार्ड पेश करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर खेती नहीं करते। ऐसे ही अनेक मंत्रीगण खेती से दूर रहते हैं। वही राज्यमंत्री बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि एक बीघा में घर के उपयोग के लिए धान की खेती जैविक की थी। बाकी नहीं। यदि मंत्रियों के अलावा विधायकों की बात की जाए, तो भी करीब 80 फीसदी विधायक खेती-किसानी करना बताते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कई इससे दूर हैं। विधायकों में कई विधायक जैविक खेती करते हैं। अभी 230 में से करीब 175 से ज्यादा विधायक खेती-किसानी से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में विधायक ऐसे हैं, जिनके पास खेती की भूमि है, लेकिन खेती नहीं करते।

दरअसल, जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य उत्पादों की विदेशों में बढ़ती मांग भी इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। मुख्यत: ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा वियतनाम जैसे देशों में निर्यात की संभावनाएं बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इस दृष्टि से मप्र के लिए भी भविष्य में जैविक उत्पाद के निर्यात की नई संभावनाएं बनेंगी।

प्रदेश में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16 लाख 37 हजार हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14 लाख 2 हजार मीट्रिक टन रहा, जो क्षेत्रफल की भांति ही देश में सर्वाधिक है। जैविक खेती को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश में कुल 17 लाख 31 हजार क्षेत्र हेक्टेयर जैविक प्रमाणिक है, जिसमें से 16 लाख 38 हजार एपीडा से और 93 हजार हेक्टेयर क्षेत्र, पीजीएस से पंजीकृत है। इस तरह पंजीकृत जैविक क्षेत्र के मामले में भी मप्र देश में अग्रणी है।

कृषि मंत्री कमल पटेल बताते हैं कि मप्र में 17 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 7 लाख 73 हजार 902 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यह भी देश के दूसरे राज्यों से ज्यादा है। क्योंकि पूरे देश में 43 लाख किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जिसमें से पौने आठ लाख किसान अकेले मप्र के हैं। इसलिए हम जैविक कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में भी नंबर वन पर हैं। साल 2020-21 में देश से कुल 7078 करोड़ रुपए के ऑर्गेनिक कृषि प्रोडक्ट दूसरे देशों को भेजे गए, जिसमें से 2683 करोड़ रुपए अकेले हमारे मप्र के हैं।

● **कुमार विनोद**

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री करते हैं जैविक खेती

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल कुछ हद तक जैविक खेती करते हैं। मुख्यमंत्री की विदिशा में खाम बाबा टीला बेसनगर और छीरखेड़ा के पास खेती है। वे यहां जरबेरा के फूलों सहित प्याज, सब्जियां, अनार और कई तरह के आम का उत्पादन लेते हैं। गेहूं-चने की भी यहां खेती होती है। इनकी खेती में एक बड़ा हिस्सा जैविक खेती का है। खुद शिवराज अक्सर अपनी खेती देखने के लिए पहुंचते हैं। अपने खेत के अनार और आम आदि फलों को ये कार्टून में पैक कर मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। जरबेरा के फूलों के लिए पॉलीहाउस एवं ग्रीन हाउस बनवा रखे हैं, फूलों का यहां बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है जिनकी मार्केटिंग प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के बड़े नगरों में भी होती है। मुख्यमंत्री की खुद की बड़ी डेयरी है, जिसके गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है। कृषि मंत्री कमल पटेल को भी जैविक कृषि पसंद है। वे इस पर भरोसा करते हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि ग्राम बारंगा में स्थित उनके 10 एकड़ खेत में अरहर की जैविक फसल लगाई है। फसल में पूर्ण रूप से गोबर की जैविक खाद का उपयोग किया गया। जैविक खाद से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और शुद्ध फसल का उत्पादन मिलेगा।

जैविक कृषि की विस्तृत कार्ययोजना तैयार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्राकृतिक और जैविक कृषि की विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जा रही है। नर्मदा के किनारे के सिंचित परंतु अधिक रसायन के उपयोग वाले कृषि क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रारंभिक तौर पर किसानों के कुल रकबे में से कुछ क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने पर काम किया जाएगा। राज्य जैविक खेती विकास परिषद का पंजीयन भी किया गया है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जैविक-प्राकृतिक खेती को शामिल करने की योजना है। दोनों कृषि विश्वविद्यालय में कम से कम 25 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती प्रदर्शन क्षेत्र में बदला जाएगा। जैविक खेती में प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने में परम्परागत कृषि विकास योजना का भी योगदान रहा है। योजना में भारत सरकार द्वारा अभी तक 3,728 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं। इन क्लस्टरों में करीब एक लाख 16 हजार कृषक शामिल है, जो सभी पीजीएस पोर्टल पर पंजीकृत है। पंजीकृत कृषकों के जैविक उत्पादों की स्थानीय स्तर पर तथा जैविक केंद्र, मंडला और जबलपुर के माध्यम से मार्केटिंग में मदद की जा रही है।

'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'

मप्र में अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिए नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 'मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ' फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब योजना के दस्तावेज के रूप में किसानों को पहली बार इसकी पॉलिसी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल बीमा के कुल 7618 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। इसमें इंदौर जिले के किसानों को 1300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के बंटवारे में पारदर्शिता रखी है। भारी बारिश के कारण जब सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, उस समय हमने अधिकारियों को रातों को भी काम कराया। उनसे कहा गया था कि किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसका मुआयना करें और जितना भी नुकसान हुआ है, उसे जस का तस लिखें। सभी अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई थी, किसानों का नुकसान ज्यादा लिखा तो चलेगा, लेकिन कम लिखा तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। किसानों को उनके नुकसान भी पूरी भरपाई होनी चाहिए।

गौरतलब है कि अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए मप्र प्रगति का स्वर्णिम इतिहास गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्नदाताओं के प्रति असीम स्नेह सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई पड़ता है। देश का हृदयस्थल मप्र प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित रहा है। खासकर पिछले 22 महीनों में हमने देश में अग्रणी रहकर हमारे अन्नदाताओं को लाभ दिया है। बीते वर्ष खरीफ फसल 2020 व रबी फसल 2020-21 मे किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था जिस कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। हमने रविवार को भी बैंक खुलवाकर किसानों की फसलों का बीमा करवाया। किसानों के चेहरों पर चमक है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल में 49 लाख बीमा दावों की 7 हजार 615 करोड़ रुपयों की राशि का 49 लाख 85 हजार किसानों को भुगतान किया है।

कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी राशि किसानों को नहीं दी गई। न मुआवजा, न बीमा की राशि, न सिंचाई योजनाओं पर काम किया है। फसल खराब होने पर भरपाई के तौर पर 200 से 400 रुपए किसानों के खाते में जमा होते थे। वर्तमान सरकार अब सिंचाई क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया था। हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले बीमा राशि का प्रीमियम भरा। वर्तमान सरकार ने पिछले 22 महीनों में किसानों के खातों में विभिन्न मदों में 1 लाख 72 हजार 854 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सरकार किसानों की बेहतरी के प्रतिबद्ध है। किसान बस मेहनत करते जाएं।

किसानों को सरकारी योजनाओं की सुविधाओं के साथ बीमा का लाभ मिलने लगा तो अन्नदाताओं ने भी कृषि उत्पादन में शानदार परिणाम देकर हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने कई रचनात्मक प्रयास किए। किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने एफपीओ योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत मप्र के हजारों किसान लाभांवित हो रहे हैं। प्रदेश में किसानों को निरंतर एफपीओ के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस योजना की मदद से किसान संगठन बनाकर कारोबारी की तरह काम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की बेरूखी से होने वाले नुकसान के समय में सरकार के किसानों के साथ खड़े होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य लगातार बेहतर हुआ। मप्र के मुखिया और कृषि मंत्री दोनों ही किसान होने का ही प्रतिफल है कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (आईएएफ) में 938.84 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में वितरित कर मप्र राशि व्यय करने में प्रथम स्थान पर है।

कार्यक्रम में कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा की पॉलिसी का वितरण किया गया। साथ ही चयनित फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) को प्रमाण-पत्र भी बांटे गए। कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग और अन्य कंपनियों द्वारा कृषि मेला और प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मेले में किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग के बारे में भी बताया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्ज्वलन किया। इसके बाद उन्होंने कन्या पूजन भी कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद थे। तुलसी सिलावट ने कहा कि शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री की सेवा को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में किसानों को देश की तुलना में सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सांवेर के लिए सड़क, पानी की समस्या को खत्म किया है। पहले कहीं भी बैठकर समीक्षा हो जाती थी लेकिन अब फसल बीमा पॉलिसी से घर पहुंचकर ही पूर्ण करनी होगी।

● **विकास दुबे**

एक समय 200 से 400 मिलते थे, अब 40 लाख तक मिल रहे हैं: तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साल 2016 में फरवरी में सीहोर में ही प्रधानमंत्री बीमा योजना का नया प्रारूप सामने आया था। अब पॉलिसी भी इसी जगह हमारे पास है। यह सबकुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ। शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मप्र में ज्यादा गंभीरता से काम हो रहा है। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजे के तौर पर एक समय 200 से 400 रुपए मिलते थे। अब यह राशि 20 से 40 लाख रुपए हो गई है। किसान के जीवनस्तर में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह राशि सीधे किसानों तक पहुंच रही है, बीच में कोई दलाल नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों का जीवनस्तर बेहतर किया जाए। एमएसपी पर खरीद होने वाली आय सीधे किसान के खाते में पहुंचती है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को, गांव को, आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले प्रदेश में सिंचाई ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन अब 46 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसके लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। किसानों की मदद के लिए जैविक खेती में अब उत्पादन में ज्यादा आय है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ी है और इससे आय भी जैविक खेती में भी मप्र नंबर वन है।

केजरीवाल का बड़ा दुश्मन कौन है?

ये तो पंजाब विधानसभा का चुनाव है जो अरविंद केजरीवाल एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के निशाने पर हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते हैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को? बड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए केजरीवाल के मुंह से झूठा सुनने को मिला था, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में देखी गई बदइंतजामियों के लिए वो टारगेट किए गए, लेकिन शायद ही कभी राहुल गांधी के लिए कायर या मनोरोगी जैसे शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल ने किया हो। कहने को तो मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जनता की तरफ से चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों के लिए भी कह चुके हैं कि संसद के अंदर डकैत, हत्यारे और बलात्कारी बैठे हुए हैं- और ये तभी की बात है जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी।

कुमार विश्वास के आरोपों पर राहुल गांधी तो केजरीवाल से हां या ना में सवाल पूछ ही रहे हैं, पंजाब चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन के दौरान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अभी-अभी कहा है कि हमारी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया और केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह आरएसएस से आया हुआ बताया है। कुमार विश्वास के बयानों की मिसाल देते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल को फिर से खरी खोटी सुनाई है और पंजाब में राहुल गांधी की ही तरह खालिस्तानियों से संबंध होने का शक जाहिर किया है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक्शन लेने को लेकर प्रधानमंत्री से की गई अपील पर आश्वासन भी दे दिया है। वैसे अरविंद केजरीवाल ने तो एक अफसर के हवाले से यहां तक बोल दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एनआईए की तरफ से जांच शुरू की जा सकती है। मुद्दे का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चुनावी माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल में भी रॉबर्ट वाड्रा का अक्स नजर आने लगा है। 2019 के आम चुनाव के वक्त ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मुमकिन है, पंजाब में वोटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल भी रॉबर्ट वाड्रा की तरह थोड़े सुकून की जिंदगी जीने लगें। कम से कम अभी जो कुछ केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है उसे लेकर तो ऐसा ही अनुमान है।

पंजाब में चुनाव आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अकाली दल की तरफ से चुनाव आयोग से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल दूसरे राजनीतिक दलों के खिलाफ बिना किसी आधार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। अकाली दल को आपत्ति आप की तरफ से जारी वीडियो को लेकर रही जिसमें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है और अकाली दल का मानना है कि वीडियो की वजह से लोगों में गलत संदेश जा रहा है। गौर करने वाली बात, इस बीच, ये भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी का जवाब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कार्रवाई के आश्वासन के साथ मिल गया है। देखा जाए तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देश की सुरक्षा के नाम पर भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने हाथ मिला लिया है, जबकि राष्ट्रवाद की राजनीति में दोनों एक-दूसरे के मुकाबले आमने-सामने देखे जाते रहे हैं।

पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री अनुरोध किया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, राजनीति से ऊपर उठकर, कुमार विश्वास के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। चूंकि पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है, लिहाजा प्रधानमंत्री को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। चन्नी के पत्र के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री चन्नी को लिखा है, एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। अमित शाह आगे लिखते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखावाऊंगा।

● **राकेश ग्रोवर**

केजरीवाल की पॉलिटिक्स में ठहराव ज्यादा है या भटकाव?

आखिर अरविंद केजरीवाल आंख मूंद एक ही दिशा में बढ़े चले जा रहे हैं या फिर दाएं-बाएं देखकर चल रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही जितना भी हो सका है, डैमेज कर पाए हैं और उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरह पंजाब में भी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे है। दिल्ली के अलावा भाजपा से भिड़ने के लिए खूंटा गाड़ कर बैठ क्यों नहीं पाते? अरविंद केजरीवाल के ट्विटर प्रोफाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोगन 'सबका साथ...' की छाप देखी जा सकती है- सब इंसान बराबर हैं - और अब तो जय श्रीराम भी बोलने लगे हैं, लेकिन स्पष्ट दूरी बना कर चलते हैं जैसे भाजपा कोई पावर ब्रेक हो। केजरीवाल ने कांग्रेस की दो सरकारों के खिलाफ एक साथ आंदोलन किया - मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार और शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार। फिर कांग्रेस की ही मदद से पहली बार सरकार भी बनाई और खुद मुख्यमंत्री। आम चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भाजपा के साथ नहीं किया। क्या भाजपा के साथ दिखावे का विरोध है, जबकि केजरीवाल भी तो अब हिंदुत्व की राजनीतिक राह पकड़ ही चुके हैं या फिर इसलिए क्योंकि भाजपा केजरीवाल को भाव नहीं देती?

बीहड़ में हो रही अफीम की खेती

अंबाह थाना क्षेत्र के ककरारी गांव के बीहड़ों में लहलहाती मिली अफीम की फसल को पुलिस ने काटकर जब्त कर लिया है। नशे की इस खेती में राजस्थान से लेकर उप्र तक के माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं। जिस अरोपित के खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई है, उसने पूछताछ में बताया कि राजस्थान व उप्र के माफिया पकने के बाद इस फसल को काटकर ले जाते और इसके एवज में 5 लाख रुपए मिलते। एक महीने के भीतर अफीम की फसल पककर कट जाती।

गौरतलब है कि एसपी आशुतोष बागरी द्वारा भेजी गई स्पेशल टीम ने ककरारी गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पास चंबल नदी किनारे बीहड़ों में डेढ़ बीघा जमीन पर अफीम की खेती पकड़ी है। यह खेत ककरारी गांव के मनोज पुत्र पूरन परमार का है। सरसों के खेतों के बीच डेढ़ बीघा जमीन में हो रही अफीम को काटकर जब्त किया तो उसका वजन 397 किलो 200 ग्राम निकला, जिसका बाजार मूल्य एक करोड़ रुपए आंका गया है। उक्त आरोपित ने अब तक हुई पूछताछ में बताया है कि ककरारी गांव के ही धर्मेंद्र तोमर ने उसे राजस्थान के धौलपुर के अलावा उप्र के एक व्यक्ति से मिलवाया था। उप्र व राजस्थान के लोगों ने उसे अफीम का बीज दिया था, जो सरसों के साथ खेत में बोया था। आरोपित मनोज परमार के अनुसार उसने कुछ महीने पहले बेटी की शादी की थी, जिसमें उस पर कर्जा हो गया था। अफीम की खेती करवाने वालों ने कहा था कि पकने के बाद इन पौधों को काटकर ले जाएंगे और इसके बदले में उसे पांच लाख रुपए नकद मिलते। मनोज परमार ने इतनी सारी बातें बताईं, लेकिन राजस्थान व उप्र के तस्करों की सही पहचान नहीं बता पा रहा, इसके लिए धर्मेंद्र तोमर की तलाश है, क्योंकि धर्मेंद्र तोमर ने ही मनोज परमार को अफीम की खेती के लिए तैयार किया था और राजस्थान व उप्र के तस्करों से मुलाकात भी उसी ने करवाई। अब पुलिस को धर्मेंद्र तोमर की तलाश है।

चंबल के बीहड़ों में नशे की खेती लगातार बढ़ती जा रही है। करीब ढाई साल पहले माता बसैया क्षेत्र में अफीम की खेती सबसे पहली बार पकड़ी गई थी। इसके बाद बागचीनी थाने से चंद मीटर दूर गांजे के खेत पकड़े थे। एक साल पहले सबलगढ़ के बटेश्वर-चौकपुरा के बीहड़ों में चार बीघा जमीन में 10 करोड़ रुपए मूल्य की 60 क्विंटल अफीम के पौधे पकड़े गए थे। अफीम की खेती करने वाले लोग मंदसौर के अलावा राजस्थान के धौलपुर व कोटा क्षेत्र से इसके बीज लाते हैं। बीज देने वाले तस्कर ही अफीम के पौधों में डोंडा आने के बाद खरीद लेते हैं।

प्रदेश में अफीम की बढ़ती अवैध खेती ने नारकोटिक्स विभाग को पसोपेश में डाल रखा है। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में बनाए गए नियमों की विसंगतियों का लाभ उठा लोग आसानी से बच निकल रहे हैं। यदि अफीम की अवैध खेती के नियमों में स्पष्टता हो तो सजा के भय से इसकी खेती पर कुछ अंकुश लग पाए। प्रदेश में गत दो माह में पुलिस ने कुछ स्थान पर सामान्य फसलों के बीच अफीम के पौधे बरामद किए। इन लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए है, लेकिन ये लोग नियमों में विसंगतियों का लाभ उठा जमानत हासिल कर लेते हैं।

बगैर लाइसेंस के अफीम, कोको, भांग की खेती करना, उसे कब्जे में रखना, बेचना, आयात-निर्यात और परिवहन करना जुर्म है। ऐसा करने पर कम से कम 10 साल से 20 साल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना है। नशीले पदार्थों से आमजन को बचाने के उद्देश्य से यह कानून करीब 36 साल पहले बनाया गया था, लेकिन 20 साल पहले यानी 2001 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अफीम की खेती में कम मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा की दो कैटेगरी बना दी। सरकार ने नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने पौधे तक अफीम की खेती कम मात्रा में और कितने पर वाणिज्यिक मात्रा में मानी जाएगी। ऐसे में 500 से ज्यादा पौधे उगाकर अवैध खेती करने वाले लोग पकड़े जाने पर नोटिफिकेशन का हवाला देकर चंद दिनों में ही जमानत पर भी छूट रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 में बिना लाइसेंस अफीम की खेती को प्रतिबंधित किया गया है। इसी एक्ट की धारा-16, 18 व 20 में कोको व भांग की खेती, तस्करी आदि पर सजा के प्रावधान हैं। कोको व भांग की बिना लाइसेंस खेती या परिवहन, तस्करी आदि करने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि अफीम की खेती की बात आती है तो इस अपराध को उत्पादन, बेचने, खरीदने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात व उपयोग के आरोप के अंतर्गत रखा गया और धारा-18 के तहत मात्रा के आधार पर सजा का प्रावधान किया। इसमें ए, बी व सी उप धारा बनाई गई। ए क्लॉज में प्रतिबंधित चीज स्मॉल कैटेगरी में है तो एक साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना, बी क्लॉज में प्रतिबंधित चीज कॉमर्शियल कैटेगरी में है तो 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है तथा जो ए व बी क्लॉज के दायरे में नहीं आते हैं, वे सी क्लॉज से कवर होंगे।

● **राजेश बोरकर**

तस्करी के लिए खेती

अफीम की खेती यूं तो कई किसान करते हैं, लेकिन अफीम आने के बाद वे नारकोटिक्स विभाग को तय कीमत पर दे देते हैं, चूकि अफीम का नशे के रूप में भी उपयोग होता है, इस कारण कई काश्तकार इसे अवैध रूप से भी बेचते हैं, इसलिए इसकी अवैध तरीके से खेती की जाती है। इस प्रकार अन्य किसी काश्तकार द्वारा तो अवैध रूप से अफीम की खेती नहीं कर रखी है, इस जांच के लिए विभाग द्वारा ड्रोन मंगाए जा रहे हैं, इसके बाद ड्रोन से तलाश की जाएगी। अवैध रूप से खेती पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारकोटिक्स विभाग के साथ ही मौके पर जावद टीआई सहित पुलिस बल पहुंचा है। चंबल के बीहड़ों में बीते एक साल में यह दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी है। बीते साल 3 मार्च को सबलगढ़ थाना क्षेत्र के बटेश्वरा-चौकपुरा के बीहड़ों में लगभग चार बीघा जमीन में अफीम की खेती को पुलिस टीम ने पकड़ा था।

सरकारी संपत्तियों को बेचने की होड़

पूरे प्रदेश में मुरैना जिला इकलौता है, जहां के तीन नेता संसद में हैं। मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री हैं। सुरजनपुर गांव के निवासी वीडी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो से सांसद हैं और अंबाह निवासी सुमन राय भिंड जिले से सांसद हैं। जिले के तीन पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंषाना, गिर्राज डंडोतिया व रघुराज कंषाना को मप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा विपक्ष भी इतना मजबूत है कि छह विधानसभा में से चार विधानसभा मुरैना, सुमावली, सबलगढ़ व दिमनी में कांग्रेस का कब्जा है। इन सब पर सोने पर सुहागा यह कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुरैना से खास लगाव है।

यह सभी नेता जिले में सरकारी योजनाओं की सौगात लाने, चहुंमुखी विकास के वादे करते हैं, पर हकीकत ये है कि मुरैना जिले में सरकारी संपत्तियों को बेचने की होड़ लगी है। बीते रोज कैलारस शकर मिल का कबाड़ बिक गया। महाराष्ट्र की सिंकोम एक्जीम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने आनलाइन बोली में कैलारस चीनी मिल की मशीनरी व पूरे ढांचे को 13 करोड़ 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इससे पहले पोरसा व मुरैना के बस स्टैंड कौड़ियों के भाव बेचे जा चुके हैं। अब नगर निगम बेशकीमती जमीनों से लेकर आवासहीनों के लिए बनाई गई बहुमंजिला इमारतों को बेचने की तैयारी कर चुका है। उधर सिंचाई विभाग भी मिरघान गांव में खाली पड़ी अपनी जमीनों को बेचने की योजना बना रहा है। हैरानी की बात यह है, कि न तो पक्ष और न ही विपक्ष के जनप्रतिनिधि सरकारी संपत्ति की नीलामी पर एक शब्द का विरोध जताने तैयार नहीं हैं। पूरे मप्र में सरकारी संपत्तियों को इस तरह किसी और जिले में नहीं बेचा जा रहा। इसमें बड़े नेताओं व अफसरों की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।

सरकारी संपत्तियों को बेचने की शुरुआत पिछले साल जनवरी से पोरसा बस स्टैंड की नीलामी के साथ हुई। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का पोरसा बस स्टैंड बीते साल जनवरी में 16 करोड़ में बिक गया। इसकी नीलामी इतनी गोपनीयता से हुई, कि आम जनता तो छोड़िए मुरैना कलेक्टर, अंबाह एसडीएम, तहसीलदार व बस स्टैंड का संचालन कर रही नगर पालिका तक को जब पता लगा, तब नीलामी के बाद इसे खरीदार को हैंडओवर करने का आदेश भोपाल से आ गया। इसके बाद दिसंबर महीने में मुरैना शहर के बीचोंबीच स्थित पुराने बस स्टैंड की प्राइम लोकेशन की 90 हजार वर्गमीटर जमीन को 67 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया। बाजार भाव के हिसाब से कम से कम 200 करोड़ रुपए की इस जमीन को 7500 रुपए वर्गफीट के भाव बेच दिया, जबकि यहां जमीनों का सरकारी भाव ही कई अधिक वर्ग मीटर का है।

एमएस रोड पर ननि मुख्यालय के ठीक पीछे दत्तपुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में नगर निगम की 5200 वर्गमीटर जगह है, जिस पर कर्मचारी आवास बने हुए हैं। इस जमीन को भी कलेक्टर, एसपी के नए बंगले व 180 कर्मचारी अवासों के निर्माण लिए अनूठे तरीके से बेचा जा रहा है। प्रशासन इसे निर्माण कंपनी को देगा, जो इस पर माल बनाकर उसमें दुकानें-शोरूम बनाकर बेचेगी। इसके बदले में कलेक्टर-एसपी व जिला न्यायाधीश के नए बंगले व 180 कर्मचारी आवास, वीआईपी रोड किनारे बनाकर देने होंगे। प्रशासन ने इस जमीन की कीमत 40.40 करोड़ आंकी है। इसमें से ठेका कंपनी 25 करोड़ के निर्माण करेगी, बची हुई 15 करोड़ की राशि कलेक्टर कोष में जमा कराई जाएगी। इसमें झोल यह है, कि यह जमीन वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए की है। इस पर माल बनने के बाद दुकानों की कीमत करोड़ों रुपए की रहेगी।

दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर का कहना हैं यह शिवराज सरकार का 15 साल का विकास है जो सरकारी संपत्तियां बेचकर खर्च चलाए जा रहे हैं। मप्र सरकार पर इतना कर्ज है कि प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40 हजार का कर्ज है। पोरसा, मुरैना बस स्टैंड व कैलारस शकर मिल के बाद मिरघान गांव में सिंचाई विभाग की जमीन को भी बेचने की योजना चल रही है। जनता इस अपराध के लिए सरकार को माफ नहीं करेगी, मैं विधानसभा में इसे लेकर कड़ा विरोध करूंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री दर्जा व पूर्व विधायक मुरैना रघुराज सिंह कंषाना कहते हैं कि यह सारे काम विकास के लिए ही हैं। नगर निगम या जो कोई विभाग संपत्तियों को बेच रहा है, उसे इसका जमकर प्रचार-प्रसार करना चाहिए, जिससे सरकार को अधिक राजस्व मिले। पोरसा व मुरैना बस स्टैंड जैसे बचे गए हैं, उनमें पारदर्शिता रखना चाहिए। नगर निगम अतरसुमा कॉलोनी व ट्रांसपोर्ट नगर बेच रहा है तो, उसमें पारदर्शिता लाए।

● **जयसिंह**

उधारी चुकाने के नाम पर बेची जा रही संपत्तियां

अंबाह, पोरसा के बस स्टैंड व कैलारस शकर मिल को कर्मचारी व हिस्सेदारों की उधारी चुकाने के नाम पर बेचा गया है। इसी होड़ में मुरैना नगर निगम शामिल हो गया है, जो माली हालत खराब और रुके हुए विकास कार्यों का वास्ता देकर 27 साल से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर प्लाट काटकर, कॉलोनाइजरों की तरह बेचने लगा है। ट्रांसपोर्ट नगर की जमीनों का भाव 1500 से 5000 रुपए वर्गफीट तक रखा गया है। इसका विरोध भी ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े दुकानदार व अन्य हितग्राही कर रहे हैं, पर ननि नहीं रुका। इसके बाद अतरसुमा में आवासहीन परिवारों के लिए बनाई गई, बहुमंजिला इमारतों को भी बेचने की तैयारी चल रही है। यहां 2-बीएचके व 3-बीएचके के आवासों वाली बिल्डिंगों को कॉलोनाइजर को बेचकर इन्हें विकसित करवाया जाएगा। इसके बाद कॉलोनाइजर इसे महंगे दाम पर लोगों को बेचेगा।

पचमढ़ी में टाइगर सफारी

प्रदेश के हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल पचमढ़ी में जल्द ही पर्यटक बाघों का दीदार कर पाएंगे। इसके लिए यहां टाइगर सफारी बनाने की तैयारी चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीने में ये सफारी तैयार हो जाएगी।

सरकार जंगलों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश का पहला टाइगर सफारी पचमढ़ी में शुरू करने के संबंध में प्लान तैयार किया जा रहा है। यह काम ईको पर्यटन बोर्ड को दिया गया है, जिसके लिए बोर्ड डीपीआर तैयार कर रहा है। सफारी तैयार करने के लिए पचमढ़ी में हवाई पट्टी के नजदीक 50 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। जिसमें तार की फैंशिंग का एक बड़ा बाड़ा बनाकर जू के बाघों सहित अन्य वन्य प्राणियों को रखा जाएगा। पर्यटक इस बाड़े के अंदर जाली से बंद वाहन में सवार होकर भ्रमण कर सकेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से टाइगर सफारी बनाई जाएगी। पचमढ़ी में 50 हेक्टर क्षेत्र को टाइगर सफारी के लिए आरक्षित किया जाएगा। भारत सरकार से इसकी अनुमति मिल चुकी है। राजस्व विभाग से 50 हेक्टर जमीन हस्तांतरित होने के बाद इसके काम में तेजी आएगी।

पिछले दिनों पचमढ़ी और होशंगाबाद दौरे पर आए वनमंत्री विजय शाह ने टाइगर सफारी शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पचमढ़ी सेंट्रल इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटक बाघ को आसानी से देख सकें और स्थानीय लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य से टाइगर सफारी की सौगात पचमढ़ी को दी जाएगी। निवेशक बाड़ा तैयार करेगा। इसके अलावा वहां सफारी के भ्रमण के लिए सड़क सहित अन्य पर्यटन स्थलों का विकास करेगा। पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं देने का भी काम निवेशक का होगा। वन विहार की तर्ज पर यहां रेस्क्यू किए गए बाघों सहित अन्य वन्य जीवों को रखा जाएगा। इसकी पूरी देख-रेख की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी, विभाग नियामक आयोग की तर्ज पर काम करेगा। सफारी और सुविधाएं देने का काम निवेशक का होगा। इसमें खर्च होने वाली राशि प्रवेश शुल्क और सफारी शुल्क के रूप में वसूली की जाएगी। पर्यटकों से सफारी के लिए शुल्क का निर्धारण वहां की समिति करेंगी, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी होंगे, लेकिन प्रस्ताव निवेशक की तरफ से रखा जाएगा।

मप्र ईको टूरिज्म बोर्ड टाइगर सफारी की डीपीआर तैयार करा रहा है, जो अगले माह तक फाइनल हो जाएगी। इसके बाद निविदा जारी करेगा, जो कंपनी या संस्था निविदा प्रक्रिया में कम राशि में काम करेगी और पर्यटकों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी उन्हें ही इसका काम दिया जाएगा। चयनित क्षेत्र में अधोसंरचना विकास (बाड़ा, पानी और पर्यटकों को भ्रमण कराने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का इंतजाम) करने के साथ अन्य सुविधाएं भी जुटाना होंगी। इन सुविधाओं के आधार पर वन विभाग संबंधित संस्था के समन्वय से सफारी का शुल्क तय करेगा।

वन विभाग ने पचमढ़ी में टाइगर सफारी बनाने के संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) को प्रस्ताव भेज दिया है। सीजेडए की अनुमति के बाद इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। सीजेडए को सरकार को यह भी बताया है कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सीजेडए की शर्तों के आधार पर ही वहां कार्य कराए जाएंगे। ईको टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सत्यानंद का कहना है कि अभी यह प्रस्ताव प्रारंभिक स्टेज पर है। टाइगर सफारी के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सफारी में फिलहाल बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों को रखने का प्रस्ताव है।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जंगल प्राकृतिक है। जंगल के अंदर कोई भी जानवर कहीं भी आ जा सकता है। टाइगर सफारी का स्वरूप यह है कि एक स्थान विशेष को विकसित कर उसमें वन्यजीवों को रखा जाता है। ऐसा करने से वन्यजीवों को आसानी से देखा जा सकता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऐसा नहीं है। टाइगर रिजर्व में नेचुरल वाटर होल, शाकाहारी वन्यजीव पाए जाते हैं, लेकिन टाइगर सफारी में व्यवस्था करनी होगी। टाइगर सफारी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनानी पड़ेगी, जिससे कोई भी जानवर बाहर नहीं आ सकेगा।

● **बृजेश साहू**

एसटीआर में जंगल सफारी पहले से सुविधा

सतपुरा टाइगर रिजर्व के मढ़ई, चूरना के जंगल और मटकुली क्षेत्र में पहले से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है। सैलानी जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। जंगल सफारी के दौरान बाघ व वन्यप्राणी जंगल में कहीं भी विचलन करते दिखाई देते हैं। लेकिन टाइगर सफारी एकदम अलग है। इसका स्वरूप चिड़ियाघर जैसा होता है। चिन्हित क्षेत्र के भीतर ही जंगली जानवर रहते हैं। वे उससे बाहर नहीं जा सकते। एसटीआर के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया पचमढ़ी में टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है। संभावना अगले साल की पहली तिमाही में सफारी का काम शुरू हो जाएगा। जिसके बाद पर्यटक टाइगर सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इसकी क्या टिकट रहेगी, यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

बदलेगा बुंदेलखंड का मिजाज

उप्र विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उप्र और रुहेलंखड के बाद अब सियासी दलों का इम्तेहान बुंदेलखंड के इलाके में होने जा रहा है। 5 साल पहले 2017 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार भाजपा ने बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप किया था और सपा, बसपा और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सकी थीं। भाजपा ने बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ें ऐसी मजबूत कीं, कि सपा और बसपा का गठबंधन भी 2019 के चुनाव में उसे नहीं हिला सका। ऐसे में सभी की निगाहें बुंदेलखंड पर टिकी हैं कि 2022 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है?

बुंदेलखंड का इलाका सियासी रूप से काफी अहम है, जो उप्र और मप्र में फैला हुआ है। उप्र के 7 और मप्र के 7 जिले आते हैं। उप्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और कर्बी (चित्रकूट) जिले की 19 विधानसभा सीटें है। बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर तीन चरणों में चुनाव है, जिसकी शुरुआत तीसरे चरण से शुरू होकर पांचवे चरण तक खत्म हो गई है। तीसरे चरण में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 सीटों पर तो चौथे चरण में बांदा जिले की 4 सीटों और पांचवें चरण में चित्रकूट जिले की 2 सीटों पर मतदान हो चुका है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समय कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। यहां की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ही काबिज रही, लेकिन 1984 के बाद से इस इलाके में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती गई और उसकी जगह सपा और बसपा और फिर भाजपा ने ले ली। 2014 में भाजपा ने बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ें मजबूत की तो फिर उसे कोई उखाड़ नहीं सका। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बुंदलेखंड की सभी 19 विधानसभा सीटों को जीतकर अपना सियासी वर्चस्व कायम किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा मिलकर भी बुंदेलखंड में भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक सकी थी, जिसका नतीजा था इस इलाके की **सभी पांचों संसदीय** सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही थी। भाजपा के इस मजबूत गढ़ पर विपक्षी दलों के नजर लगी हुई हैं।

बुंदेलखंड क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखें तो ओबीसी और दलित वोटर अहम हैं। यहां 22 फीसदी सामान्य वर्ग के वोट हैं, जिनमें ब्राह्मण और ठाकुरों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा वैश्य समुदाय भी हैं। 43 ओबीसी वोटर है, जिनमें कुर्मी, निषाद, कुशवाहा जातियां बड़ी संख्या में हैं। 26 दलित वोटर हैं, जिनमें जाटव की संख्या काफी अधिक है और कोरी समुदाय भी ठीक-ठाक है। सियासी समीकरण के चलते ही बुंदेलखंड का इलाका एक दौर में बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने यहां खासा असर डाला था। एक तरफ मायावती की टीम के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा से आते थे तो वहीं ओबीसी फेस कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा भी यहीं के थे। दद्दू प्रसाद जैसे दलित नेता पार्टी में थे तो पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी जैसे ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। लेकिन, मायावती के साथ आज इनमें से कोई भी नेता नहीं है।

बसपा ने मुस्लिम, ओबीसी, दलित और ब्राह्मणों को साधकर बुंदेलखंड में धाक जमाई थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में भाजपा ने ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित वोटों को अपने साथ जोड़कर अपनी जगह मजबूत कर ली है। वहीं, उप्र में मोदी-योगी सरकार के आने के बाद बुंदलेखंड में विकास को रफ्तार मिली। बुंदेलखंड के विकास के लिए भाजपा सरकार ने बोर्ड का गठन भी किया है। झांसी से चित्रकूट के क्षेत्र को डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया है। इटावा से चित्रकूट तक बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के जरिए विकास की सौगात मिली है। महोबा अर्जुन सहायक परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को पानी की किल्लत से निजात मिल सकती है। चित्रकूट एयरपोर्ट से लेकर अन्य तमाम परियोजनाओं के जरिए भाजपा ने विकास और हिंदुत्व को साथ लेकर चलने का काम किया है।

भाजपा इन विकास योजनाओं के जरिए अपने दुर्ग को मजबूत रखने की कवायद की है, लेकिन बुंदेलखंड में लोकल मुद्दे चुनाव में हावी हैं। बुंदेलखंड में सूखा, बेरोजगारी, पलायन और किसान आत्महत्या अक्सर मुद्दा बनती रही है। यहां पानी की कमी भी सियासी मुद्दा बनी रही। यही वह इलाका है जहां पीने के लिए वाटर ट्रेन तक चलाई गई। मंहगाई और बेरोजगारी का जवाब भाजपा नेताओं के पास नहीं हैं। जमीनी हकीकत की बात करें तो आवारा अन्ना पशुओं से परेशान बुंदलेखंड की कई सीटों पर बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। अन्ना पशुओं से किसानों की फसलें काफी बर्बाद हुई हैं। बुंदेलखंड में आवारा पशु भाजपा के लिए चिंता का सबब बन गए हैं, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर योगी को घेर रहा है। भाजपा को तर्कों के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि इस इलाके में बसपा और सपा जातीय समीकरण फिट करते ही भाजपा से सीटों को छीनने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बुंदेलखंड में वोटों की सेंधमारी

बसपा के लिए बुंदेलखंड में चीजें तब से बदल गईं जब से भाजपा ने ओबीसी और दलित वोट में सेंधमारी की। वहीं बसपा ने जाटवों के अपने कोर वोट बैंक के अलावा, अपने वोट हासिल करने की उम्मीद में अन्य समुदायों के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम आबादी कम होने के कारण सपा की उम्मीद यादवों के अलावा अन्य समुदायों के वोट बटोरने पर टिकी है। सपा ने इस बार बुदंलेखंड के सियासी समीकरण को देखते हुए कुर्मी, दलित, कुशावाहा समुदाय के कैंडिडेट उतार रखे हैं। ललितपुर से सपा ने पूर्व विधायक और भाजपा नेता रमेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सपा नेता चंद्र भूषण सिंह बुंदेला को सपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली तो बसपा की ताल ठोक रहे हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार विधायक राम रतन कुशवाहा हैं। मौरानीपुर सीट पर भाजपा विधायक बिहारी लाल आर्य ने 2017 में सपा की रश्मि आर्य को हराया था। इस बार आर्य भाजपा के सहयोगी अपना अल (एस) के उम्मीदवार हैं। सपा ने बसपा से आए तिलकचंद अहिरवार और बसपा ने रोहित रतन अहिरवार को मैदान में उतारा है। बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में, बसपा एक कारक बनी हुई है और कुछ सीटों पर भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है।

रूस-यूक्रेन युद्ध
दो महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग

जब एक डर दूसरे डर के विरुद्ध होता है तो युद्ध होता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध किसी देश के पराक्रम का युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों के भयभीत होने का युद्ध है। दरअसल, दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। अमेरिका नाटो के जरिए अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगा हुआ है। इसके लिए उसने यूक्रेन को मोहरा बनाया है, ताकि वह रूस के दरवाजे पर अपनी ताकत जमा सके। यह बात रूस को नागवार गुजरी है। उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन को समझाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिम के बल पर यूक्रेन ने रूस को चुनौती दे दी, जिसका परिणाम दोनों देशों के बीच युद्ध के रूप में सामने आया है। इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। इस युद्ध में भारत की कूटनीति का भी इम्तिहान होगा।

● राजेंद्र आगाल

आखिरकार वही हुआ, जिसका अंदेशा था। तमाम वैश्विक दबावों को झुठलाते हुए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस और जर्मनी की बीच-बचाव की कोशिशें, अमेरिका की पाबंदी की घुड़कियां और संयुक्त राष्ट्र की मैराथन बैठकें रूस को यूक्रेन पर हमला बोलने से नहीं रोक सकीं। सवाल है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन इतने आक्रमक क्यों बने हैं?

कहां है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्तित्व? यूक्रेन में व्यापक जान-माल के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों और युद्ध के धमाकों के बीच यह बेहद जरूरी हो गया है कि मानवता की रक्षा की जाए, इंसान और इंसानियत को बचाया जाए। लेकिन भारत को छोड़कर पूरा विश्व इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। शायद यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में हुई वार्ता पूरी तरह विफल हो गई। इससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई है।

हमने दो विश्व युद्धों का जख्म झेला है और अनुभव यही है कि युद्ध किसी भी समस्या का न तो विकल्प हो सकता है और न ही समाधान। जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और विश्व के बड़े हुक्मरान इस समस्या का समाधान निकालें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन के प्रतिनिधि के बयान पर जरा गौर कीजिए। उसने साफ तौर पर ये आरोप लगा दिया है कि सुरक्षा परिषद पूरी तरह रूस के 'वायरस' का शिकार है और फिलहाल इस 'वायरस' की कोई कारगर 'वैक्सीन' नहीं है। इस बयान के कई मायने हैं। इसके जरिए अब यूक्रेन अमेरिका और यूएन पर दबाव डालना चाहता है कि वह खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। साथ ही ये भी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य न बनाए जाने से ये गंभीर स्थिति पैदा हुई है।

अमेरिका की महत्वाकांक्षा

भले ही युद्ध यूक्रेन में लड़ा जा रहा है, लेकिन यह अमेरिका और रूस की महत्वाकांक्षा का परिणाम है। दरअसल अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो के 30 सदस्य देशों में यूक्रेन को शामिल करने को लेकर दो राय रही है और पिछले कई वर्षों से यूक्रेन की कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया है। तीसरा ये कि यूक्रेन अमेरिका को ये खुली चुनौती दे रहा है कि अगर वह रूस से ज्यादा ताकतवर है तो उसके पास इस 'रूसी वायरस' की 'वैक्सीन' होनी चाहिए। रूस का लगातार ये दावा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर रूस का हिस्सा रहा है लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से स्वतंत्र हुए यूक्रेन पर अमेरिका अपना वर्चस्व कायम रखने और उसके जरिए रूस के करीब अपना सैन्य बेस बनाने की कोशिश करने की फिराक में है। जाहिर है रूस ऐसा नहीं होने देगा।

दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लगातार ये कोशिश रही है कि वह अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने 'सर्वशक्तिमान' दिखाने वाली छवि को तोड़ें। पिछले करीब छह-सात दशकों से तमाम देश इन दोनों महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग और इसका दुनिया पर असर देख रहे हैं। चाहे वो ईरान का संकट हो, खाड़ी युद्ध हो, अफगानिस्तान का मसला हो या फिर दुनियाभर में फैला आतंकवाद और अलगाववाद का संकट। इन दोनों ही साम्राज्यवादी ताकतों ने तीसरी दुनिया के ज्यादातर देशों को अपने-अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है और अपने फायदे के लिए तमाम देशों में आंतरिक संघर्षों और अलगाववादी समूहों के जरिए अशांति बरकरार रखने की रणनीति पर काम करते रहे हैं। दोनों ही महाशक्तियां अपने-अपने वर्चस्व की जंग में

यूरोप-अमेरिका समर्थित राष्ट्रवाद और रूसी डर

इस विकास के साथ ही जब सोवियत संघ ढलान पर आया तो यूक्रेन के लोगों को अपनी आजादी का ख्याल भी आने लगा। यूक्रेन यूरोप से लगती हुई सोवियत संघ की सीमा पर था इसलिए अमेरिका और यूरोप को आसानी से यूक्रेन में आजादी और देशभक्ति का जज्बा भरने का मौका मिला और सोवियत संघ के विघटन के लिए अमेरिका और रूस ने यूक्रेन के लोगों की भावनाएं खूब भड़काई। राष्ट्रवादी कहानियां और कविताएं इस दौर में यूक्रेन में लिखी और पढ़ी जाने लगी। यूरोप के फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे चकाचौंध दुनिया वाला देश बनाने का सपना यूक्रेन के लोगों की आंखों में जगाया जाने लगा। इधर सोवियत संघ के कम्युनिस्ट सरकार में आपस में संघर्ष शुरू हुआ और उधर यूक्रेन ने आजादी का ऐलान कर दिया। अगस्त 1991 में कम्युनिस्टों के निखारे गोर्बाचोव के असफल तख्ता पलट के दौरान यूक्रेन के संसद ने आजादी का ऐलान कर दिया। रूस को आज भी लगता है कि यूक्रेन की वजह से और फिर यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ने बढ़ावा दिया उसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को संभालने में लगे थे तब यूक्रेन अपनी आजादी की घोषणा करने वाला पहला देश बना उसके बाद तो सोवियत संघ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। फिर तो बाकी के 14 देश सोवियत संघ से टूटकर अलग हो गए। रूस के दिलो-दिमाग में आज भी डर बैठा हुआ है कि अगर यूक्रेन हमारे साथ नहीं रहा तो फिर हमारे साथ अमेरिका और यूरोप धोखा कर सकते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका को लगता है कि अगर यूक्रेन हमारे साथ नहीं रहा तो रूस की धौंस दुनिया में बढ़ जाएगी। रूस को हम यूक्रेन के जरिये ही घेर सकते हैं।

लगातार शह और मात का खेल खेलती आई हैं और इनकी बिसात पर तीसरी दुनिया के तमाम देश मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। जाहिर है यूक्रेन कोई अपवाद नहीं है।

पुतिन-जेलेंस्की में कौन भारी

रूस की ओर से यूक्रेन में छेड़ी गई जंग दोनों ही देशों के लिए काफी भारी साबित हो रही है। जहां रूस ने अपने करीब 1 लाख 90 हजार सैनिकों को हथियारों, टैंकों और एयरक्राफ्ट्स के साथ यूक्रेन पर हमले के लिए भेजा है, वहीं यूक्रेन भी लगातार अपने सैनिकों और नागरिकों की मदद से रूस के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश में है। इस बीच दोनों देशों में युद्ध को लेकर अब तक कई आंकड़े साफ नहीं हो पाए हैं। मसलन इस युद्ध में अब तक कितनी जानें जा चुकी हैं। दोनों देशों को इस युद्ध से कितना आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है और उसे सेना पर कितना खर्च करना पड़ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों को लेकर जहां यूक्रेन लगातार आंकड़े रख रहा है, वहीं रूस ने ये तो कबूला है कि उसके सैनिक भी यूक्रेन में मारे गए और घायल हुए हैं, लेकिन पुतिन सरकार की तरफ से मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया गया। इस बीच रूसी सैनिकों को लेकर भी यूक्रेन की तरफ से दावे किए गए हैं।

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक, उसके कुल 352 नागरिक मारे जा चुके हैं और 1684 घायल हैं। यूक्रेन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें कितने सैनिक और कितने आम नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह जरूर बताया गया है कि मरने वालों में 14 बच्चे और घायलों में कुल 116 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के इन दावों पर यूएन की तरफ से भी बयान जारी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसने यूक्रेन के 240 लोगों के युद्ध में हताहत होने की पुष्टि की है।

यूक्रेन-रूस दोस्ती दिखाने का दौर

मार्च 1953 में स्टैलिन के मरने के बाद यूक्रेन यूएसएसआर सरकार के कम्युनिस्ट सेक्रेटरी निकिता पूरे सोवियत संघ के हेड बने तो यूक्रेन के घाव पर मरहम लगाने का काम शुरू हुआ। यूक्रेन पर अत्याचार और रूसीफिकेशन को पहली बार गलत बताया गया। 1654 में कोसाक हेतमांते साम्राज्य के दौरान 300 साल पहले यूक्रेन और रूस के एकीकरण की पेरिसास्लाव संधि की तीन सौवीं वर्षगांठ पूरे जश्न के साथ कीव और लेनिनग्राद में मनाई गई। इसे ऐतिहासिक मौका बनाने के लिए 1954 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया जबकि केवल 22 फीसदी क्रीमियन यूक्रेनी है। इसके बाद यूक्रेन के रहने वाले लियोनेड ब्रेझनेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट सेक्रेटरी बने। यूक्रेनियन के सोवियत संघ के मुखिया बनने पर दोनों इलाकों में जमकर जश्न मना। सोवियत संघ को अमेरिका-यूरोप के यूक्रेनी प्रोपोगांडा से निपटने और यूक्रेन का दिल जीतने की कोशिश के तौर पर इसे देखा गया। स्टालिन के बाद का यह सोवियत संघ का जमाना था जब यूक्रेन में प्रगति अपने चरम पर पहुंची। आज जो मौजूदा यूक्रेन है वह उसी दौरान विकास की ऊंचाइयां पा गया था। हथियार, परमाणु रिएक्टर से लेकर जमकर औद्योगिकीकरण हुआ।

इनमें से कम से कम 64 लोग मारे गए हैं। यूएन ने यह भी कहा कि मौतों और घायलों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। मॉस्को की तरफ से यूक्रेन में सैनिकों के मरने का कोई आंकड़ा नहीं रखा गया है। लेकिन क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि उसके सैनिकों की मौत की संख्या यूक्रेन के मुकाबले काफी कम है। दूसरी तरफ यूक्रेन के ही रक्षामंत्री ने बताया है कि अब तक उसके साथ युद्ध में 5300 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं।

दोनों देशों को नुकसान

रूस और यूक्रेन दोनों ही एक-दूसरे की सेनाओं को हुए जबरदस्त नुकसान को गिनाने में जुटे हैं। लेकिन दोनों ने ही अपने नुकसान को लेकर कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक चार दिन में रूस को 191 टैंकों, 816 बख्तरबंद गाड़ियों, 60 ईंधन टैंकों, एक बुक सिस्टम (एयर डिफेंस), चार ग्रैड सिस्टम (रॉकेट लॉन्चर), 29 फाइटर जेट्स, 26 हेलिकॉप्टर, दो शिप-बोट, 74 तोपें, सैनिकों को लाने-ले जाने वाले 291 वाहन और 5300 से ज्यादा वेयरहाउस गंवाने पड़े हैं। उधर, रूस ने भी यूक्रेन के नुकसानों को गिनाते हुए कहा है कि उसने यूक्रेन के 1114 सैन्य लक्ष्यों को तबाह कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रूसी सैनिकों ने एस-300 से लेकर बुक एम-1 (एयर डिफेंस) सिस्टम और बेराक्तर ड्रोन्स को निशाना बनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने इसका ब्यौरा देते हुए कहा कि पिछले चार दिन में उनकी सेना ने यूक्रेन के 31 कमांड पोस्ट और संचार केंद्रों के अलावा 38 एस-300 और बुक एम-1 सिस्टमों के अलावा ओसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टमों को तबाह किया है। इसके अलावा 56 रडार सिस्टम भी निशाने पर आए हैं। इसके अलावा 31 एयरक्राफ्ट (फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर) भी तबाह किए गए। 57 मल्टिपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 121 फील्ड आर्टिलरी गन और मोर्टार और 274 विशेष सैन्य वाहनों भी रूसी सेना के निशाने पर आए हैं।

रूस की ओर से छेड़े गए इस युद्ध का असर दोनों ही देशों पर पड़ने की संभावना है। जहां पहले ही रूस-यूक्रेन कोरोनावायरस की वजह से बड़े नुकसान झेल चुके हैं। वहीं, अब युद्ध का नुकसान भी दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से लगाया गया हर एक प्रतिबंध रूस के लिए कांटे की तरह है। इसमें कहा गया है कि अगर यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका रूस पर तेल और गैस से जुड़े प्रतिबंधों का ऐलान करते हैं, तो उसकी 120 लाख करोड़ रुपए (1600 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था, जो कि मुख्य तौर पर तेल-गैस के निर्यात पर निर्भर है, वह एक बार में 4.1 फीसदी तक गिर जाएगी। वहीं, अब तक लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस का बाकी सामान का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है, जिससे रूस को लगातार नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। पश्चिमी देशों की तरफ से मशीनरी और उपकरणों पर प्रतिबंधों की वजह से रूस को अर्थव्यवस्था में 0.5 फीसदी, मोटर वाहन और पार्ट्स में प्रतिबंधों की वजह से 0.3 फीसदी और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर प्रतिबंध के चलते 0.1 फीसदी जीडीपी का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा करीब एक दर्जन अन्य क्षेत्रों पर यूरोपीय देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था के पूरी तरह तबाह होने की संभावना है। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर रूस इस बीच बाकी देशों की तेल-गैस सप्लाई बंद करने की धमकी देता है, तो भी इससे पुतिन सरकार का नुकसान ही ज्यादा है, क्योंकि इन हालात में रूस के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घटता जाएगा।

यूक्रेन पर कैसे पड़ेगा प्रभाव?

रूस की ओर से शुरू किए गए युद्ध का जितना असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव यूक्रेन पर पड़ने के आसार हैं। दरअसल, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था रूस से 10 गुना छोटी है। फिलहाल इस देश की जीडीपी 13.5 लाख करोड़ रुपए (180 अरब डॉलर) आंकी जाती है और यह ज्यादातर आयात पर आधारित है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने से पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ऐलान किया था कि रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के लोग 95 हजार करोड़ (करीब 12.5 अरब डॉलर) निकालकर देश से बाहर जा चुके हैं। यानी फिलहाल युद्ध से यूक्रेन की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर एस्तोनिया के पूर्व रक्षा प्रमुख रिहो टेरस ने कहा कि इस युद्ध से रूस को रोज 1500 करोड़ यूरो (लगभग 1508 अरब 72 करोड़ 49 लाख 96 हजार रुपए) खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पुतिन का युद्ध योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, क्योंकि रूस की पूंजी और हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं।

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह

रूस और यूक्रेन का विवाद अब एक युद्ध का रूप ले चुका है। रूस के यूक्रेन पर हमले की सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने की कवायद है। अमेरिका के वर्चस्व वाले इस संगठन में 30 देश शामिल हैं जिनमें से अधिकतर यूरोप के ही हैं। हालांकि इसमें सबसे अधिक जवान अमेरिका के ही हैं। रूस पर दबाव बनाने और अपने पुराने विवादों के कारण अमेरिका लगातार इस तरह की कवायद करता रहा है। अमेरिका पहले से ही रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसको दबाव में लाने की कवायद कर चुका है। हालांकि उसकी ये चाल अब तक काम नहीं आई थी। अब वो यूक्रेन के सहारे इस काम को करना चाहता है। रूस की चिंता ये है कि यदि यूक्रेन नाटो के साथ चला जाता है तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचाने में आशिंक रूप से सफल हो सकता है। इस हमले की दूसरी वजह अमेरिका और पश्चिमी-यूरोपीय देशों का नार्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना भी शामिल है। आपको बता दें कि रूस ने इस परियोजना पर अरबों डॉलर का खर्च किया है। रूस इसके जरिए फ्रांस, जर्मनी समेत समूचे यूरोप में गैस और तेल की सप्लाई करना चाहता है। इससे पहले ये सप्लाई जिस पाइपलाइन के जरिए होती थी वो यूक्रेन से जाती थी। इसके लिए रूस हर वर्ष लाखों डालर यूक्रेन को अदा करता था। नई पाइपलाइन के बन जाने से यूक्रेन की कमाई खत्म हो जाएगी। यूक्रेन के रूस से अलगाव की एक बड़ी वजह में ये भी शामिल है। तीसरी वजह ये है कि रूस नहीं चाहता है यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि रूस का यूक्रेन से भावनात्मक रिश्ता है। रूस की नींव यूक्रेन की धरती से ही रखी गई थी। रूस की पहचान यूराल पर्वत श्रृंखला भी यूक्रेन से ही होकर गुजरती है। अमेरिका और रूस के बीच का विवाद काफी लंबे समय से है। शीतयुद्ध के बाद भी स्थितियां बदली नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूस केवल इतना ही चाहता है उसका मान कायम रहे और उसको बदनाम न किया जाए। विदेश मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुष्पेश पंत का कहना है कि रूस ने अपना आक्रामक रूप दिखाकर न सिर्फ पश्चिम देशों को बल्कि समूचे यूरोप और खुद को दुनिया की महाशक्ति बताने वाले अमेरिका को उसकी औकात बता दी है। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला करने के बाद भले ही अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे केवल उनको ही नुकसान होने वाला है। अमेरिका के पास इससे अधिक कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं।

नाटो पर अटका तार

पड़ोसी देश होने की वजह से और सोवियत संघ के विघटन से पहले तक उसका हिस्सा रहने वाले यूक्रेन को लेकर अगर रूस वहां के नागरिकों की अस्मिता की लड़ाई में उनका साथ देता रहा है तो इसे वह अपना नैतिक दायित्व भी बताता है। लेकिन कूटनीतिक जानकार लगातार ये भी कहते आए हैं कि अमेरिका पूर्वी यूक्रेन में नाटो के सैन्य ठिकाने बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस पर नजर रखना चाहता है जिसे रूस जानता है और इसीलिए वह लगातार नाटो का विरोध करता है और इसकी जरूरत पर सवाल उठाता है। नाटो का गठन सोवियत संघ के जमाने में हुआ था, लेकिन रूस का तर्क है कि जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो नाटो की जरूरत क्यों है। इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। जबकि अमेरिका कूटनीतिक तौर पर नाटो के बहाने तमाम देशों में फैली अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए शांति सैनिक भेजकर अपना वर्चस्व बनाए रखने की रणनीति पर चलता रहा है। अब रूस के इन दोनों प्रांतो पर कब्जा कर लेने के बाद वहां जश्न भी मनाए जा रहे हैं और इन प्रांतों के लोग भी इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि अब यहां अलगाववादी गुटों और यूक्रेन की सेना के बीच पिछले 8 साल से चल रही गोलाबारी और हमले बंद हो जाएंगे, इलाके में शांति रहेगी और रूस की सेना होने की वजह से वे सुरक्षित रहेंगे।

रूस जानता है कि इस कदम के बाद यूरोपीय देश और पश्चिम के तमाम देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, कई तरह की बंदिशें लगेंगी, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगेंगे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह उसने 2014 में क्रीमिया को कब्जे में लिया था, उसी तरह इस बार भी उसने इन दोनों प्रांतों को स्वायत्त घोषित कर और वहां के अलगाववादी गुटों से समझौता कर अपना मकसद हासिल कर लिया है और अमेरिका के मंसूबों को फिलहाल नाकाम कर दिया है।

कौनसा देश किसके समर्थन में?

अगर रूस की बात करते हैं तो क्यूबा सबसे पहले उसका समर्थन करेगा। दरअसल, क्यूबा ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने का आव्हान किया था। इसके अलावा रूस को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा। चीन पहले ही ऐलान कर चुका है कि नाटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। दरअसल, पश्चिमी देशों ने जब चीन के विरोध में कदम उठाए थे, तब रूस ने चीन का समर्थन किया था। हकीकत यह है कि रूस और चीन दोनों ने ही सेना से लेकर अंतरिक्ष तक अलग-अलग क्षेत्रों में कई साझेदारी कर रखी हैं।

इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने छह देशों के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रूस पर हमला होता है तो ये देश इसे खुद पर भी हमला मानेंगे। इनके अलावा अजरबेजान भी रूस की मदद के लिए आगे आ सकता है।

अगर हम मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं तो ईरान रूस का साथ दे सकता है। दरअसल, न्यूक्लियर डील असफल होने के बाद से रूस लगातार ईरान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा सीरिया से युद्ध के दौरान रूस ने ही ईरान को हथियार मुहैया कराए थे। वहीं, युद्ध की स्थिति में उत्तरी कोरिया भी रूस का साथ दे सकता है। दरअसल, उत्तरी कोरिया ने पेनिनसुला में जब मिसाइल लॉन्च की थीं, उस वक्त अमेरिका ने

उस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो रूस और चीन दोनों ने विरोध जताया था। वहीं, पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकता है।

अब हम उन देशों के बारे में जानते हैं, जो विश्व युद्ध के हालात बनने पर यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इनमें अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक साबित हो सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने हाल ही में मॉस्को का दौरा करके विवाद शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के दो राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया और वहां सेना भेजने का ऐलान किया, तब जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की इजाजत को रोक दिया। वहीं, अन्य पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया।

अब हम उन देशों से रूबरू होते हैं, जो रूस-यूक्रेन संकट पर तटस्थ की भूमिका में मौजूद हैं। इस मसले पर भारत अकेला ऐसा देश है, जिसने तटस्थ रुख अपना रखा है। दरअसल, अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत की जीडीपी का 40 फीसदी हिस्सा फॉरेन ट्रेड से आता है। 1990 के दौर में यह आंकड़ा करीब 15 फीसदी था। भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से होता है। भारत हर साल पश्चिमी देशों से करीब 350-400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है। वहीं, रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार है।

युद्ध में भारत का रुख

हालांकि अमेरिका जिस तरह लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, उससे दहशत और असमंजस की स्थितियां बनी हुई है और भारत समेत तमाम देश अपने-अपने नागरिकों को वहां से वापस बुलाने की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में रहने वाले करीब 20 हजार भारतीय भी वापस लाए जा रहे हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए अहम है। सुरक्षा परिषद में भी भारत लगातार अपना रुख साफ करता रहा है कि तमाम मसलों का हल मिल बैठकर शांति से होना चाहिए। यूक्रेन के मसले पर भी यही होना चाहिए। भारत के रूस और अमेरिका दोनों से ही करीबी व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं और जाहिर है भारत अपने रिश्तों से कोई समझौता नहीं कर सकता।

पिछले करीब दो महीनों से बनी इस स्थिति का यह निर्णायक दौर है और यूक्रेन लगातार खबरों में है। वैसे भी युद्ध और अशांति के साथ साथ दो महाशक्तियों के टकराव की खबरों में हमेशा लोगों की दिलचस्पी रही है और वह भी तब जब मामला दो महाशक्तियों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग का हो और गरजते हथियारों का। यूक्रेन अभी कुछ समय तक सुर्खियों में बना रहेगा और भारत में चुनावी गहमा गहमी के बीच भी यह खबर लोगों में दिलचस्पी पैदा करती रहेगी।

रूस को अलग-थलग करने की रणनीति

रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया ने एकजुट होने और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं, बैंकिंग, खेल और गहरे संबंध के अनगिनत अन्य धागों से एक साथ जुड़े होने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। रूस को अलग-थलग करने के लिए तमाम देश उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे वह कई मोर्चों पर दुनिया से अचानक कट गया है। बैंक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्षमताएं कम हो गई हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उसकी भागीदारी चरमरा रही है। यूरोप में उसके विमानों पर रोक लगा दी गई है। उसकी 'वोदका' (एक तरह की शराब) का अमेरिकी राज्यों ने आयात बंद कर दिया है। यहां तक कि स्विटजरलैंड, जो अपनी तटस्थता के लिए पहचाना जाता है वह भी सावधानी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुंह मोड़ रहा है। केवल पिछले तीन दिन में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। कई देशों की सरकारों से लेकर कई गठबंधनों, संगठनों आदि ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। कई मायने में ये प्रतिबंध ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों से भी कहीं अधिक कड़े हैं।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस को हल्के में लेकर गलती की

अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले संगठन नाटो में शामिल देशों की रूस के साथ बातचीत विफल होने के बाद यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले की आशंका बढ़ गई थी। अंततः रूस यूक्रेन पर हमला करके ही माना। इस हमले के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। ये देश सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाए। रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर उसे विफल कर दिया और भारत, संयुक्त अरब अमीरात एवं चीन ने खुद को मतदान से अलग रखा। भारत मतदान से अनुपस्थित अवश्य रहा, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया कि वह यूक्रेन के घटनाक्रम से व्यथित है। भारत ने कूटनीति का रास्ता त्यागने पर अफसोस जाहिर करते हुए यह भी कहा कि हिंसा और शत्रुता तुरंत खत्म करने के सभी प्रयास करने चाहिए। एक तरह से भारत ने रूस को यह संदेश दिया कि वह उसकी कार्रवाई से खुश नहीं। भारत के रुख से अमेरिका और उसके सहयोगी देश असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि भारत के सामने चीन की चुनौती है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि दुनिया यूक्रेन पर रूस के हमले से उपजे अभूतपूर्व संकट का सामना किस तरह करेगी? रूस यूक्रेन के समर्पण करने के बाद ही उससे बात करने को तैयार है और वह हथियार डालने को राजी नहीं है। रूस के रवैये को देखते हुए यह साफ है कि उसे अमेरिका और अन्य देशों की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों की परवाह नहीं है।

एमसीडी में सत्ता-परिवर्तन के आसार

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। हालांकि दिल्ली की दूसरी सत्ता के इन चुनावों में भले ही दो-ढाई महीने का समय बचा है और देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के शोर में एमसीडी के चुनावों का शोर बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में हर रोज आरोप-प्रत्यारोप के हमले तेज होते जा रहे हैं। क्योंकि एमसीडी के चुनाव का दिल्ली की सियासत में बड़ा महत्व है। तभी तो एमसीडी को दिल्ली की छोटी सरकार कहा जाता है। दिल्ली की इस छोटी सत्ता में पिछले करीब 15 साल से भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता एमसीडी में भी सत्ता-परिवर्तन चाहती है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 2012 में तीन भागों में बांटा गया था, तब पूर्वीनगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्थापित किए गए थे, ताकि जनता को अपने काम करवाने के लिए कोई दिक्कत न हो। उसके बाद से तीनों नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा है। 2012 से एमसीडी में कांग्रेस हाशिए पर है। 2017 में हुए एमसीडी की 272 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 181 सीटें जीतीं, जबकि आप पार्टी ने 49 जीतीं और कांग्रेस सिमटकर 31 सीटों पर ही जीत दर्ज करा सकी। बताते चलें कि जब आम आदमी पार्टी (आप) का उदय नहीं हुआ था, तब एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता था। लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर 49 सीटों के साथ खाता खोलकर एमसीडी की सियासत में नए समीकरणों को जन्म दिया।

इसके बाद 2021 में एमसीडी के उपचुनाव में पांच में से चार सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि एमसीडी के होने वाले 2022 चुनाव में वह जीत हासिल कर सकती है। क्योंकि इस बार 2022 में एमसीडी के चुनाव के पूर्व ही माहौल और मिजाज बदला-बदला सा नजर आ रहा है। उसको लेकर जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि इस बार एमसीडी में भाजपा 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जिससे जनता काफी नाराज है। क्योंकि एमसीडी को जो बजट दिल्ली सरकार से मिलना चाहिए। उसको दिल्ली सरकार ने रोका है। इससे एमसीडी के काम-काज में बाधा आई है। जनता को आप पार्टी की सरकार मुफ्त की राजनीति कर गुमराह कर रही है। जनता आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों को समझ गई है।

वहीं भाजपा के नेता दीपक कुमार का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता एक समय कहते थे कि वे किसी भी ऐसे दल से समझौता व उनका समर्थन नहीं करेंगे, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। लेकिन जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सिर्फ भाजपा का विरोध करने लिए सभी अन्य दलों का समर्थन कर रही है, जिसको जनता बखूबी जान-समझ रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में विकास कार्य ठप पड़े हैं। एमसीडी के तहत जो भी काम हो रहा है, वो ही दिख रहा है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो रहा है।

वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2022 के एमसीडी के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। क्योंकि जिस कदर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है और कर रही है, उसका हिसाब जनता चुनाव में लेगी। एमसीडी के तहत आने वाले स्कूलों और अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि निगम के स्कूलों में सिर्फ कागजों पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है। एमसीडी ने लगभग 100 स्कूलों को बंद कर दिया है, जबकि दिल्ली सरकार ने स्कूलों का विस्तार किया है। इसका असर एमसीडी के चुनाव में दिखेगा और आप को जीत मिलेगी।

● **अक्स ब्यूरो**

जनता बदलाव के मूड में

एमसीडी की कार्यप्रणाली से अवगत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमन कुमार का कहना है कि जिस अंदाज में भाजपा और कांग्रेस से नेता आकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमसीडी में दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में सफल होती है, तो एमसीडी के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम का कहना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव फिर से दिख रहा है। क्योंकि देश की राजनीति में जिस प्रकार वोटों को लेकर खींचतान की जा रही है, उस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। धर्म और जाति की राजनीति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। वही हाल लोगों ने साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में देखा है। इसलिए दिल्ली की जनता एमसीडी के चुनाव में उसी राजनीतिक दल का समर्थन देगी, जो हिंसा और ध्रुवीकरण की राजनीति न करती हो। दिल्ली की एमसीडी में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग चल रही है। लेकिन जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी की डिस्पेंसरियां नाममात्र को काम कर रही हैं। जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं के लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय जनता में व्याप्त गरीबी को दूर करने तथा वंचित तबकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी सुनियोजित एवं प्रभावी योजना प्रस्तुत करनी चाहिए और इस आधार पर जनता को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करके चुनावी राजनीति में एक स्वस्थ परम्परा की शुरुआत करनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं सत्तापक्ष एवं विपक्ष द्वारा क्यों की जाती हैं?

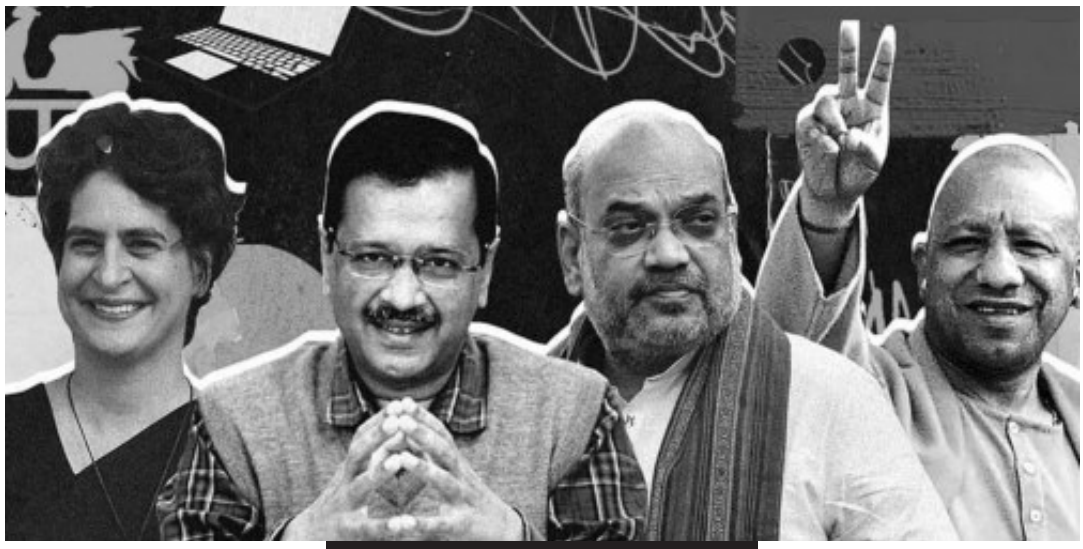

मुफ्त का चंदन...!

5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इन सभी राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जी जान से पार्टी हर प्रकार के हथकंडे अपना रही हैं। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु एक के बाद एक नकद एवं मुफ्त उपहारों की घोषणा की जा रही है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में ऐसे दलों के द्वारा सरकारी खजाने से नकद एवं मुफ्त उपहारों का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने एवं चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है।

प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह की लोक-लुभावन घोषणाओं के माध्यम से, विशेषकर चुनावों से ठीक पहले जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढा जा सकता है? क्या राजनीतिक दलों द्वारा वोट प्राप्त करने हेतु एवं चुनाव जीतने मात्र के लिए, आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बगैर ऐसी घोषणाएं करने पर रोक लगनी चाहिए?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 2013 में आया था और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भ्रष्ट व्यवहार की श्रेणी में नहीं माना था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि इस प्रकार की चुनावी घोषणाओं ने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की जड़ों को कमजोर किया है और निसंदेह मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। विगत वर्षों में कुछ राज्यों के चुनावी परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि राजनीतिक दल इस प्रकार की तत्कालिक चुनावी घोषणाओं के माध्यम से जनता को कुछ हद तक अपने पक्ष में करने में सफल भी रहे हैं। विगत 10 वर्षों में परिस्थितियां और बिगड़ी हैं, शायद यही कारण है कि न्यायालय ने इस बार इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया है।

भारत में चुनावों के दौरान ऐसे वादे करना एवं चुनाव जीतने पर भूल जाने की संस्कृति नई नहीं रही है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत तत्कालीन आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव द्वारा की गई जब उन्होंने 2 रुपए किलो चावल देने की घोषणा की तथा उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में इसका वृहत्तर स्वरूप

आवंटन में विभागों के बीच हेराफेरी

हमने अपने अध्ययन में पाया कि सामान्य वर्षों की तुलना में जिस वर्ष माफी की सबसे ज्यादा रकम का भुगतान किया गया उस वर्ष विभिन्न विभागों के बजट आवंटन में बड़ा हेरफेर किया गया। कर्ज माफी के साथ क्रियान्वयन विभागों के लिए आवंटन बेशक कई गुना बढ़ गए। पंजाब में कृषि विभाग के लिए आवंटन में 66 फीसदी, उप्र में कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए आवंटन में 610 प्रतिशत, महाराष्ट्र में सहकारी विपणन एवं कपड़ा विभाग के लिए आवंटन में 887 फीसदी की वृद्धि हो गई। इसी के साथ, कई प्रमुख विभागों के लिए आवंटन में गिरावट आ गई। सबसे उल्लेखनीय गिरावट इन विभागों के लिए आवंटन में आई– बिजली, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, सिंचाई, उद्योग एवं श्रम आदि। हालांकि विभागों के बजट में कटौती के लिए सिर्फ कृषि कर्ज माफी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि कर्ज माफी जैसी खर्चीली योजनाओं के लिए बजट में मनमाना फेरबदल किया जाता है। शिक्षा, बिजली, ऊर्जा, जल संसाधन जैसे प्रमुख विभागों के खर्चों में कटौती करके राज्य सरकारें राज्य के भविष्य के लिए जरूरी निवेश को रोक रही हैं। इसके अलावा, कृषि कर्ज माफी से किसानों की तकलीफ शायद ही दूर होती है।

देखने को मिला। वहां दोनों ही क्षेत्रीय दलों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एक से बढ़कर एक लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती रही हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, कामकाजी महिलाओं को स्कूटी खरीदने में सब्सिडी से लेकर प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, मंगलसूत्र तक देने की भी घोषणा की गई।

भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर गरीबी व्याप्त है क्या वास्तव में ऐसी घोषणाएं दीर्घकाल में भी जनता की गरीबी दूर करने में सफल होंगी? क्योंकि जनता की वास्तविक गरीबी दीर्घकालीन एवं सुनियोजित नीतियों के माध्यम से ही दूर हो पाएगी न कि इस तरह की चुनावी घोषणाओं एवं योजनाओं से। यदि हम राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही मुफ्त घोषणाओं को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि समय के साथ मुफ्त घोषणाओं में हमें मौलिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। प्रारंभ में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा इत्यादि की घोषणाएं होती थी किंतु अब तमिलनाडु के पैटर्न पर उप्र में भी टीवी, मोबाइल, स्मार्टफोन, टेबलेट, लैपटॉप, लोन माफी की बातें हो रही हैं जिन्हें यदि पूरी तरह वास्तविक धरातल पर उतारा जाए तो पूरे प्रदेश की शायद अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए।

अगर हम समग्र रूप से उप्र में मानव विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें तो नीति आयोग द्वारा 2020-21 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत जनता निर्धन है तथा उप्र मात्र बिहार और झारखंड से ही बेहतर स्थिति में है। ठीक इसी प्रकार मातृ-मृत्यु दर में राज्य की भयावह स्थिति है। स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से उप्र, देश के 21 बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर हैं। राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 31 है, 0-5 आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर 51 (प्रति 1000 जीवित बालक) है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

यह समझने की आवश्यकता है कि इन लोकलुभावन घोषणाओं को जिस जनता के लिए किया जाता है वह पैसा राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं अर्जित नहीं बल्कि करदाताओं का पैसा होता है जिसका परोक्ष भार महंगाई एवं कर के रूप में पुन: उन्हीं के ऊपर आता है। यह उन राज्यों में या उन अर्थव्यवस्थाओं में तो सही हो सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा आमदनी के मजबूत स्रोत हैं किंतु भारत में आश्चर्यजनक रूप से उन राज्यों में भी चुनावों के दौरान ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है तथा कर्ज में डूबी हुई हैं। उदाहरण के लिए उप्र में प्रत्येक नागरिक पर 22,242 रुपए का कर्ज है तथा प्रदेश सरकार पर कुल 516 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा उप्र में धरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने का चुनावी वादा किया गया है जबकि प्रदेश का विद्युत विभाग 90 हजार करोड़ रुपए के घाटे में है।

कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश की आधी आबादी को रिझाने के लिए लड़कियों को फ्री स्कूटी देने के वादे के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक दलों द्वारा ठीक चुनावों से पहले ऐसी घोषणाएं क्या मतदाताओं को प्रभावित करने मात्र हेतु नहीं की जाती हैं? क्या यह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा? राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मुफ्त घोषणाओं को वह कैसे पूरा करेंगे, इसकी जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस तरह की घोषणाएं लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर नहीं करती हैं? क्या राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय इस प्रकार के आचरण ने शासन को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाए जाने के लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत राजनीतिक दलों, सरकार व जनता के संबंधों को सेवा-प्रदाता और ग्राहक के रूप में नहीं बदल दिया है?

जिस प्रकार विभिन्न सेवा-प्रदाता फर्में स्वयं को चयनित किए जाने हेतु अलग-अलग लुभावने प्रस्ताव देती हैं उसी प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा भी मतदाताओं को वोट के बदले अनेक आकर्षक वस्तुएं दिए जाने की घोषणाएं की जा रही है। इस संदर्भ में योजना आयोग ने भी बहुत पहले राज्यों को मतदाताओं के तुष्टिकरण पर रोक लगाने तथा समावेशी विकास पर ध्यान देने की बात की थी क्योंकि इस तरह की लोकलुभावन नीतियां दीर्घकाल में लाभकारी नहीं हो सकतीं तथा अर्थव्यवस्था पर बोझ डालती हैं एवं मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं।

● **विपिन कंधारी**

दुष्चक्र में फंसे किसान

भारत में खेती कई कारणों से जोखिम भरा काम है। इसमें उत्पादन चक्र के साथ दूसरे कारण जुड़कर ऐसी स्थिति बना देते हैं कि किसानों के लिए कर्ज न लेना असंभव हो जाता है। लगातार घाटा और घटता मुनाफा उन्हें कर्ज का भुगतान करने में चूकने के लिए मजबूर करता है। यह चूक उन्हें और तकलीफ में डालती है, और कभी-कभी तो उन्हें आत्महत्या तक करने को मजबूर कर देती है। कर्ज माफी उस कर्ज से मुक्ति दिलाती है जो कहीं ज्यादा जटिल मर्ज का नतीजा है या लक्षण है। इसलिए, उसकी तकलीफ के जिन कारणों (मसलन लगातार फसल खराब होना, पैदावार की लाभकारी कीमत न मिलना, या निजी नुकसान आदि) का उपाय नहीं किया जाता उसके चलते किसान की स्थिति कर्ज माफी के बाद थोड़े समय के लिए भले ठीक हो जाती है लेकिन कुछ ही वर्ष बाद वह फिर कर्ज में फंस जाता है और उसे फिर कर्ज माफी की जरूरत पड़ने लगती है। इसलिए कर्ज माफी के जरिए राज्य सरकार न केवल वर्तमान की खातिर राज्य की भावी क्षमताओं का सौदा करती है बल्कि वह वर्तमान को भी पूरी तरह संवार नहीं पाती। कर्ज माफी के कारण देश की उधार संस्कृति और उधार देने के मामले में बैंकों के उत्साह पर जो बुरा असर पड़ता है वह तो अलग ही मामला है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को ऐसे समाधान ढूंढने चाहिए, जो राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से तर्कपूर्ण हों और अंततः किसानों को ताकत दें।

विपक्ष खेला के फिराक में

चुनाव नतीजे आने के बाद देश की राजनीति का मिजाज बदलने वाला है - मुंबई पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने के बाद ये संकेत भी दे दिया है।

मौजूदा भाजपा नेतृत्व भी लगता है फील गुड फैक्टर से संक्रमित हो चुका है और भाजपा को एक बार फिर इंडिया शाइनिंग वाले मोड में जाते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जोश और अमित शाह के चाणक्य मिशन के चालू रहते हुए भी, ऐसा लगता है भाजपा इस बात से बेखबर है कि उसके खिलाफ क्या कुछ चल रहा है। जिस विपक्ष को भाजपा बिखरा हुआ समझ रही है, वो चुपचाप परदे के पीछे से अपना काम कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का मुंबई दौरा देश में बदलते राजनीतिक मिजाज की तरफ इशारा करने लगा है। मुंबई में केसीआर की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार की मुलाकातों और दिल्ली में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मीटिंग में सीधे तौर पर कोई कनेक्शन हो न हो, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब भाजपा के खिलाफ साजिशों की कवायद ही है।

भाजपा ने जांच एजेंसियों का हौव्वा खड़ा करके विरोधियों के बीच जो राजनीतिक आतंक का माहौल बनाया है, विपक्षी खेमे के लोग उससे मुकाबले का तरीका बहुत हद तक सीख चुके हैं। हर कोई ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है कि भाजपा को शिकस्त दी जा सके। हो सकता है जरूरत के हिसाब से अभी की तैयारियां नाकाफी हों, लेकिन कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है।

विपक्ष जान चुका है कि अगर एकजुट होने की कोशिशें सरेआम हुईं तो नेताओं के घरों पर या फिर उनके करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। बीमारी की रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। कोरोनाकाल में भी मेडिकल साइंस की ये थ्योरी फेल तो नहीं ही हुई है। विपक्ष भी ऐसे ही सबक के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है भाजपा को अंग्रेजों की तरह पूरे देश में अपना एक संभावित साम्राज्य नजर आने लगा है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में उनके औपनिवेशिक साम्राज्य की सूर्योदय से सूर्यास्त तक फैले इलाके की संज्ञा दी जाती थी। भाजपा भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मन ही मन सपने को साकार होते देखने लगी है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि अंदर ही अंदर खेला शुरू हो चुका है।

ममता बनर्जी ने बंगाल में कभी पोरिबोर्तन का नारा दिया था और भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव में बार-बार वही दोहरा रही थी, लेकिन फेल हो गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मुंबई पहुंच कर कहा है, देश को परिवर्तन की जरूरत है। केसीआर का भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने वैसे ही सपोर्ट किया है जैसे कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी और उसके बाद सोनिया गांधी को किया था। केसीआर से मुलाकात के बाद बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस भी हुई है और हाल फिलहाल विपक्ष की तरफ से ऐसी

ममता और पवार की दूरी को कैसे समझें?

उप्र चुनाव को लेकर शरद पवार और ममता बनर्जी दोनों के बयान आए हैं, लेकिन दोनों ही एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने जरूर लखनऊ का दौरा किया और अखिलेश यादव के सपोर्ट में साथ बैठकर प्रेस कांफ्रेंस भी की है, लेकिन ये सब ऐसे पेश किया गया जैसे भाजपा को गफलत में रखा जा सके। एनसीपी का तो एक उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है, लेकिन ममता का कोई कैंडीडेट नहीं है। अनूप शहर से अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत एनसीपी के केके शर्मा को टिकट दे रखा है और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। शरद पवार ने उप्र चुनावों से भी उतनी ही दूरी बनाए रखी, जितनी पश्चिम बंगाल के वक्त देखने को मिली थी, लेकिन ये भी भाजपा नेतृत्व को झांसा देने की कवायद ही लगती है। उप्र का उन्नाव सीट बेहतरीन नमूना है कि कैसे सपा और कांग्रेस अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और करहल जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं।

पहली कोशिश लगती है। अब तक विपक्ष की मुलाकातें होती रहीं। कभी कांग्रेस को किनारे रखकर तो कभी कांग्रेस के बुलावे पर, लेकिन बाहर आकर गोलमोल बातें ही होती रहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि केसीआर और उद्धव ठाकरे एक साथ मीडिया के सामने आए हैं और कुछ ठोस आश्वासन भी दिया है। हम लोग एक बात पर सहमत हुए कि देश में बड़े परिवर्तन की जरूरत है। देश के माहौल को खराब नहीं करना चाहिए... जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं। नाजायज काम से हम लड़ना चाहते हैं।

केसीआर की बातों को उद्धव ठाकरे एनडोर्स भी करते हैं और जो कहते हैं वो कहने भर को सांकेतिक होता है, बल्कि सब कुछ साफ और सटीक होता है, हमारा हिंदुत्व बदला लेने वाला नहीं है! 2019 के आम चुनाव से पहले भी केसीआर खासे एक्टिव देखे गए थे। बल्कि, अपने नजदीकी पड़ोसी चंद्रबाबू नायडू के समानांतर भी। तब वो ममता बनर्जी से मिलने के लिए ऐसे ही कोलकाता तक गए थे, लेकिन ममता बनर्जी साथ में मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं हुईं, उद्धव ठाकरे ने कोशिशों पर गंभीरता की मुहर लगा दी है। तभी तो डंके की चोट पर केसीआर कह रहे हैं, जल्द ही देश के कुछ और नेताओं से बातचीत के बाद एजेंडा पेश किया जाएगा, ये एजेंडा किसके खिलाफ होगा ये तो मालूम है, लेकिन क्या होगा अभी ये साफ नहीं है।

विपक्ष ने सरवाइवल का तरीका खोज लिया है। जिन इलाकों में अपराधियों का दबदबा होता है, वहां के लोग सरवाइवल के तौर-तरीके से धीरे-धीरे सीख जाते हैं। चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाका हो या फिर बिहार में जंगलराज का दौर रहा हो, बड़े-बड़े डॉक्टरों और कारोबारियों ने अपहरण और फिरौती के दौर में उसके साथ जीना सीख लिया था। लाइफस्टाइल ऐसी बना ली थी जिससे लगे कि वो जैसे-तैसे गुजारा कर रहा हो। सभी तो नहीं लेकिन ऐसे उपाय करके बहुतों ने जिंदगी जीने का तरीका निकाला और शिकारी को चकमा देते रहे। कॉनफ्लिक्ट जोन में रह चुके लोगों से बात करने पर ऐसे तमाम किस्से सुनने को मिल जाते हैं।

सपा-बसपा गठबंधन टूटने और उप्र चुनाव 2022 में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन न होना सबसे बड़ा उदाहरण है। 2018 के चुनाव के समय जब अखिलेश यादव और मायावती के बीच मौखिक गठबंधन हुआ, तो बकौल योगी आदित्यनाथ, प्रयोग को बहुत हल्के में ले लिया गया था और भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर 2019 में शिद्दत से तैयारी हुई और भूल सुधार भी कर लिया गया।

भाजपा की चुनावी तैयारियों का एक हिस्सा ये भी रहा कि उसने गोरखपुर से चुनाव जीतने

मायावती किसके साथ हैं?

माना तो यही जा रहा है कि मायावती पूरी उप्र में जगह-जगह भाजपा की मदद कर रही हैं, लेकिन करहल का राजनीतिक समीकरण देखने पर पता चलता है कि कैसे बसपा अखिलेश यादव की जीत में बाधा नहीं बन रही है। मायावती ने गोरखपुर सदर या जहूराबाद की तरह करहल में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ऐसा ही बिहार चुनाव में भी देखने को मिला था। चिराग पासवान भी वहां भाजपा के लिए मायावती जैसे ही मिलते जुलते रोल में थे, लेकिन तेजस्वी यादव की सीट पर ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया था कि जीत में कोई रुकावट न आए। ऊपर से भले लग रहा हो कि मायावती किसी मजबूरी में भाजपा के मनमाफिक काम कर रही हैं, लेकिन ये सब मन बहलाने वाले गालिब ख्याल ही लगते हैं। और भाजपा के फील गुड की ताजा मिसाल है अपने लिए एक और कंगना रनौत की खोज, कुमार विश्वास को वाय कैटेगरी की सुरक्षा दिया जाना भी तो वैसा ही है। फर्क बस ये है कि कंगना ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुमार विश्वास के मुंह से अभी अरविंद केजरीवाल का ही पुराना डायलॉग निकल रहा है- न कभी सुरक्षा की जरूरत समझी, न मांगी है।

वाले प्रवीण निषाद को ही तोड़ लिया और गोरखपुर की योगी वाली सीट पर जीत का रास्ता साफ हो गया। इलाके के ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का भाजपा ने रविकिशन शुक्ला में कारगर नुस्खा खोज लिया और काम बन गया। लेकिन लगता है भाजपा विपक्ष की ताजा गतिविधियों से बेखबर है और परदे के पीछे कैसे भाजपा के खिलाफ रणनीति पर काम चल रहा है, लगता है उसे मालूम भी नहीं है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस के साथ-साथ उसने विपक्ष मुक्त भारत का सपना साकार कर लिया है।

नीतीश और पीके भी यूं ही नहीं मिले हैं। मुंबई में केसीआर की ठाकरे और पवार के साथ हुई मुलाकातों जैसी ही नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है अभी दोनों आपसी जरूरतों के चलते मिले हों, लेकिन आगे चलकर ऐड-ऑन फीचर तो बन ही सकते हैं। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के रिश्तों को अलग करके देखा जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है दुश्मन को चकमा देने की रणनीति का ही हिस्सा हो। आखिर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की पोजीशन भी तो यथास्थिति में ला ही दी है। और लालू प्रसाद को लेकर प्रियंका गांधी का बयान भी यूं ही नहीं लगता। लालू को लेकर प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, राहुल गांधी के मुंह से ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला।

राहुल गांधी भले ही तेजस्वी यादव के साथ लंच कर लेते हों, लेकिन दागी नेताओं को बचाने वाले ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़े जाने के बाद से दोनों ही एक-दूसरे से बचते रहे हैं और कन्हैया के कांग्रेस में आने और बिहार उपचुनाव के दौरान महागठबंधन में जो किचकिच हुआ है, उसके बाद लालू और सोनिया गांधी की बातचीत के बाद बात भी खत्म सी हो गई है। प्रियंका गांधी का ताजा रुख भी उसी का नतीजा लगता है। 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटें तय कराने में भी प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। ये तब की बात है जब लालू जेल में हुआ करते थे। लालू यादव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वही बयान दिया है जो तेजस्वी ने ट्विटर पर पिन कर रखा है- 26 दिसंबर 2017 से।

● **इन्द्र कुमार**

माओवादी इलाकों में खबरी पर लग रही बाजी

नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच खबरी पिस रहे हैं। दरअसल, माओवादी इलाकों में खबरी ही वह कड़ी है, जो नक्सलियों की गतिविधियों और सुरक्षाबल की रणनीति को एक-दूसरे के पास पहुंचाते हैं।

माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच खबरी पर बाजी लग रही है। खबरी को लेकर कभी सुरक्षा बल, नक्सलियों पर भारी पड़ते हैं, तो कभी नक्सली बड़े हमले को अंजाम देकर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। हथियारों की बात करें तो दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का है। मुठभेड़ के दौरान एके 47, इंसास, एसएलआर, यूबीजीएल, एलएमजी, मोर्टार, बीजीएल, राकेट लॉन्चर, जैसे हथियारों का इस्तेमाल होता है। हालांकि असल बाजी, अब भी खबरी पर ही लगती है। जिसका इंटेलिजेंस इनपुट सटीक हुआ, समझो उसी का वार निशाने पर लग जाएगा।

नक्सलियों के अभेद ठिकाने और सीपीआई माओवादी के हेडक्वॉर्टर माड़ (अबूझमाड़) के आसपास 40-50 किलोमीटर दूरी तक का इलाका ऐसा है कि वहां पर या तो नक्सल हैं या सीआरपीएफ है। चूंकि नक्सली, जंगल में बहुत अंदर तक छिपे हैं, इसलिए वहां एकाएक पहुंचना आसान नहीं है। अगर उन्हें सुरक्षाबलों की मूवमेंट दिखती है, तो ढोल बजा देते हैं। ढोल की आवाज उस मांद तक जाती है, जहां इनके हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप हैं। नक्सलियों की मांद तक पहुंचने का एकमात्र जरिया नए कैंप हैं। अब सीआरपीएफ द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं।

पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि बस्तर हो या बालाघाट या किसी दूसरे नक्सल प्रभावित इलाके में इंटेलिजेंस का काम आसान नहीं है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, ऑपरेशन आसान नहीं है। जंगल में 40-50 किलोमीटर तक नक्सली मिलेंगे या सुरक्षा बल। गांव हैं, लेकिन वहां नक्सली, भोले-भाले ग्रामीणों को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा लेते हैं। इंटेलिजेंस जुटाने के लिए जिस तरह से सुरक्षाबलों के खबरी हैं, उसी तरह से नक्सलियों ने भी बड़े पैमाने पर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इसका तोड़ अभी सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सुरक्षाबलों की पल-पल की सूचना, नक्सलियों तक पहुंच जाती है। इस वजह से कई बार आखिरी मौके पर अहम ऑपरेशन को टालना पड़ा है।

बड़े ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों की कई टीमें अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ती हैं। नक्सली, जंगल के चप्पे-चप्पे पर अपना आदमी रखते हैं। उन्हें जैसे ही सुरक्षाबलों की मूवमेंट नजर आती है, वे ढोल बजा देते हैं। इसके बाद घने जंगल में नक्सलियों की मांद तक अलर्ट पहुंच जाता है। इसके चलते ऑपरेशन की रणनीति बदलनी पड़ती है। माड़ इलाके का तो कई दशकों से सर्वे ही नहीं हुआ है। इससे भी वहां की भौगोलिक स्थिति का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। ऑपरेशन को बचाए रखने के लिए सुरक्षाबल, रात के समय चलना शुरू करते हैं। हालांकि रात में एक घंटे में मुश्किल से एक किलोमीटर चला जाता है, जबकि दिन में वही रास्ता चार-पांच किलोमीटर तय हो जाता है। अगर पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं तो **ऑपरेशन में सहूलियत** होती है। दूर तक की गतिविधि नजर आ जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घेरा डालने के लिए नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। दो वर्ष में तीस से ज्यादा कैंप स्थापित हो चुके हैं। इन्हीं कैंपों की मदद से नक्सलियों पर निर्णायक प्रहार होगा।

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला तो 40 वर्षों से भी अधिक समय से नक्सलियों के प्रहार झेल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सीआरपीएफ एवं दूसरे सुरक्षाबलों ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी के अनुसार, दो वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 236 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 86 नक्सली मारे गए हैं। इनमें हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। 863 नक्सली बस्तर पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 909 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के कब्जे से 158 हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें एके-47, एसएलआर, इंसास और यूबीजीएल शामिल है। देशभर में साल 2016 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक माओवादी हमलों में 733 जवान घायल हुए हैं। घायलों की सर्वाधिक संख्या 486 छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में 80 व महाराष्ट्र में 110 जवान घायल हुए हैं। साल 2016 में 145, 2017 में 153, 2018 में 152, 2019 में 82, 2020 में 108 व 2021 में 93 जवान घायल हुए हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

सुरक्षा बलों के 118 जवान और अधिकारी शहीद

नक्सल प्रभावित इलाकों में साल 2016 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक विभिन्न सुरक्षाबलों के 118 जवान और अधिकारी शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 87 जवान शहीद हुए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में 932 वामपंथी उग्रवादी मारे गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ में 492, झारखंड में 102, उड़ीसा में 98 और महाराष्ट्र के 144 उग्रवादी शामिल हैं। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के मामले कम हो रहे हैं। गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 70 फीसदी की कमी होने का दावा किया है। साल 2009 में हिंसा के 2258 केस थे तो 2020 में इनकी संख्या 665 है। आम नागरिकों और सुरक्षाबलों के जवानों की मौत का आंकड़ा भी 80 फीसदी तक गिर गया है। 2010 में इनकी संख्या 1005 थी तो 2020 में ये आंकड़ा 183 है। हिंसा का भौगोलिक विस्तार भी सीमित हो गया है। साल 2013 की बात करें तो माओवादी हिंसा का क्षेत्र 10 राज्यों के 76 जिलों तक फैला था। अब वह क्षेत्र कम होकर 9 राज्यों के 53 जिलों तक सिमट चुका है।

नवाब के साथ पूरी सरकार

केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी रस्साकशी के ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अफसर गत दिनों सुबह-सुबह करीब 6 बजे नवाब मलिक के घर पहुंच गए और उन्हें अपने साथ साउथ मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर ले गए। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मलिक को मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से जुड़े एक केस में सामने आया है। इकबाल कासकर को इसी माह ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की इस कार्रवाई से एनसीपी भड़की हुई है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, और किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को ईडी दफ्तर की घेराबंदी करनी पड़ी। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर अपने एजेंडे के तहत केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

गौरतलब है कि नवाब मलिक का केंद्रीय एजेंसियों के साथ छत्तीस का आंकड़ा रहा है। खास तौर से जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके दामाद समीर को पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही एनसीबी के साथ उनकी तनातनी जारी है। पिछले साल ही एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद नवाब मलिक ने एनसीबी और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर **गंभीर आरोप लगाए** थे। इनमें जानबूझकर लोगों को ड्रग्स केस में फंसाने, अपनी जाति के बारे में झूठ बोलने और बार का लाइसेंस लेने जैसे आरोप शामिल हैं। हाल ही में समीर वानखेड़े को उनकी जाति के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। वानखेड़े थाने के कोपरी थाने में बार लाइसेंस के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश हुए थे। एनसीबी पर निरंतर हमलों के बाद ऐसी आशंका थी कि नवाब मलिक पर भाजपा हमलावर होगी ही। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इशारों-इशारों में कहा था कि जल्द ही नवाब मलिक ईडी के शिकंजे में होंगे। इसके अगले दिन से ही ईडी ने महाराष्ट्र भर में वक्फ की संपत्तियों पर छापेमारी शुरू कर दी थी।

रोचक है कि जिस एफआईआर के आधार पर ईडी ने इकबाल कासकर और अब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है, उसे लेकर भी विवाद है। 2017 में ठाणे पुलिस की एंटी एक्स्टॉर्शन सेल ने इकबाल कासकर को आपराधिक धमकियां देने और जबरन वसूली के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। इकबाल पर आरोप था कि उसने बिल्डरों, ज्वैलरों और कारोबारियों से जबरन वसूली की थी और उनके फ्लैटों पर कब्जा कर लिया था। कासकर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तार किया था। शर्मा उस समय एंटी एक्स्टॉर्शन सेल के इंचार्ज थे। वहीं प्रदीप शर्मा इस समय जेल में हैं। उन्हें एनआईए ने एंटीलिया विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया था। शर्मा पर आरोप था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के केस में उनका भी हाथ है और उन्होंने इस केस से जुड़े लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। इस पूरे मामले का मास्टमाइंड सचिन वाजे को माना गया था। आरोप है कि इसकी सच्चाई छिपाने के लिए ठाणे के रहने वाले मुकेश हिरेन की हत्या कर दी गई।

जबसे एनआईए ने सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है तबसे ही भाजपा महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी शिवसेना के टिकट पर लड़ा था। उस समय शिवसेना का महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन था। जिस एफआईआर से प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया उसी के आधार पर ईडी ने इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर ही अपनी जांच की थी। इस एफआईआर में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मामले थे।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का नाम इस्तेमाल करना भाजपा की पुरानी नीति रही है। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले उनके खिलाफ भी दाऊद इब्राहिम का नाम इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार में दाऊद का नाम लेते हुए वादा किया था कि अगर वे चुने गए तो दाऊद इब्राहिम को भारत लेकर आएंगे और उसके अपराधों की सजा दिलाएंगे। लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है। नवाब मलिक को मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी और दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों के साथ आर्थिक लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से लोग उनकी संपत्ति के बारे में जानने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं ऐसे में ये सवाल भी सामने आ रहे हैं कि आखिर नवाब मलिक के पास कितनी संपत्ति है।

● **बिन्दु माथुर**

महाराष्ट्र खुफिया विभाग से खफा शरद पवार

महाविकास अघाड़ी सरकार के राज में जल्द ही बड़े बदलाव के संकेत हैं। सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव नौकरशाही से लेकर सरकार तक में हो सकते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया शरद पवार और तमाम प्रभावशाली मंत्री इस बात से खासे नाराज हैं कि राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीएफ का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और राज्य के खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई मंत्रियों ने और खुद शरद पवार ने गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। इधर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकरशाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट के बराबर मूवमेंट कर सकें।

महारानी की बढ़ी सक्रियता

राजस्थान में 2023 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। वहीं राजस्थान भाजपा में नेतृत्व को लेकर कलह के कई बार संकेत सामने आए हैं। राजस्थान में गृहमंत्री अमित शाह ने दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि राजस्थान में चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कई बार शक्ति प्रदर्शन भी देखे गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सब आए और रैलियों में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो ऐसे नारे भी लगे। वहीं उपचुनाव के दौरान पार्टी को मिली करारी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। राजस्थान में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को लेकर अपनी सहमति जताई है लेकिन कहीं ना कहीं दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व अशोक परनामी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज होने लगी हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं रहा है। राजस्थान में दो बार भाजपा की सरकार के दौरान वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहीं। वहीं वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी लंबे समय से हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और जन समर्थन भी उनके साथ में है। राजस्थान भाजपा में बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री दावेदार नेताओं की लिस्ट लंबी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, सांसद दीया कुमारी, सांसद भूपेंद्र यादव, सांसद अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लंबे समय बाद फिर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा के धरने में वो शामिल हुईं। यही नहीं विधानसभा में भी राजे ने रीट परीक्षा मामले की अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तख्तियां लहराई। राजे अब कई नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रही हैं। इसे उनकी सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। गत दिनों राजे बांदीकुई पहुंचीं। यहां उन्होंने आरएसएस प्रचारक शिव लहरी के पिता के निधन पर संवेदना प्रकट की। इसके बाद उन्होंने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की। भाजपा के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर भाभड़ा से भी राजे ने मुलाकात की। आगरा रोड पर गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ वे बांदीकुई पहुंची थीं। इससे पहले भी उन्होंने कई जगहों पर धार्मिक यात्रा निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री होने के नाते वो राजस्थान में नेताओं से मिलती रहती हैं।

राजे के साथ उनके खेमे के नेताओं की एकजुटता भी साफ नजर आई। प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक परनामी, रामचरण बोहरा, नरपत सिंह राजवी, अशोक लाहोटी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, सुरेंद्र पारीक, कैलाश वर्मा, डीडी कुमावत समेत अन्य कई नेता कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए। ये सभी वो नेता हैं जो गाए-बगाए राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग उठा चुके हैं।

कोरोना और लॉकडाउन की पाबंदियां हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों पार्टी और संगठन में काफी सक्रिय दिख रही हैं। खासतौर पर जिलों में संगठन के पदाधिकारियों के बीच राजे के आ रहे फोन कॉल चर्चा में हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे कुछ जिलों में भाजपा के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को अचानक फोन कर उनकी और परिवार की कुशलक्षेम पूछ रही हैं। इस दौरान क्षेत्र में भाजपा संगठन की ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी भी ली गई। वहीं, क्षेत्र के अन्य पार्टियों से जुड़े नेताओं के कामकाज को लेकर भी जानकारी जुटाई गई। खास बात यह है कि इस बार वसुंधरा राजे के फोन जिन छोटे कार्यकर्ताओं के पास गए, उनमें से अधिकतर ऐसे थे, जिन्होंने अपनी राजनीति में पहली बार फोन पर वसुंधरा राजे से बात की है। यही कारण है कि जब फोन पर बात हुई तो यह नेता भी उत्साहित हुए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैडम आपको यहां सब लोग मिस करते हैं। दरअसल, वसुंधरा राजे की लंबे समय से प्रदेश भाजपा में हुए बदलाव में उनकी भूमिका कुछ खास नहीं रही। अब जिलों में भाजपा पदाधिकारियों के पास पहुंच रहे उनके फोन कॉल ने उनकी बढ़ती सक्रियता की ओर इशारा किया है, जो प्रदेश भाजपा में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

बहुत लोकप्रिय नेता हैं वसुंधरा राजे

जोधपुर सूरसागर विधानसभा के भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास का कहना है कि वसुंधरा राजे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उनके साथ में जन समर्थन भी है। राजमाता की बेटी हैं और मिलनसार भी हैं। अगर ऐसा होता है तो पार्टी फिर सत्ता में लौट सकती है। पूर्व शिक्षा मंत्री अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी कहते हैं कि अमित शाह आए थे उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुलाकात भी हुई है, अच्छी बात है, क्योंकि वह हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मुलाकात तो करेंगे ही इन सवालों का कोई महत्व नहीं है जब केंद्रीय नेतृत्व अपनी बात रख चुका है। भाजपा को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा इसको लेकर भी पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। तीन नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इनमें श्रीचंद कृपलानी, सीपी जोशी और एक अन्य नाम सामने आए हैं।

मुद्दों में गायब है भविष्य का एजेंडा

उप्र के विधानसभा चुनाव में उप्र ही नदारद है। सत्ता के एक दावेदार को जनता से यह अपेक्षा है कि वह अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे तीर्थों के उद्धार के लिए उसके हाथ मजबूत करे, जबकि दूसरा दावेदार लोगों को पिछले 5 वर्षों में हुई फर्जी मुठभेड़ों और दमन की घटनाओं की याद दिला रहा है। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि यह चुनाव शायद सड़क और हवाई अड्डा बनवाने के नाम पर लड़ा जाए, लेकिन ऐसे दावे करने वाले पक्ष को ऐन मौके पर अंदाजा हो गया कि ये कथित विकास परियोजनाएं बहुत सारे लोगों का विस्थापन और कई परिवारों की बर्बादी भी अपने साथ लाई हैं। नतीजा यह कि इस विशाल राज्य का चुनाव ले-देकर वापस उसी व्यर्थ की उत्तेजना और जाति-धर्म की धुरी पर घूमने लगा है, जो पिछले तीन दशकों से उप्र की राजनीतिक पहचान बनी हुई है।

भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में उप्र की स्थिति धीरे-धीरे एक असाध्य पहेली जैसी हो चली है। 25 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही इस राज्य की आबादी संसार में सिर्फ चार देशों- चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से पीछे है। इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई के पास **एक अर्से** से भविष्य का कोई एजेंडा नहीं। ठोस मुद्दों पर राजनीति का चलन न केंद्रीय चुनावों में है, न ही किसी और राज्य में। लेकिन कोई भी चुनाव हो, उसमें राज्य या देश के हित-अनहित पर कुछ बातें तो हो ही जाती हैं। मीडिया को भी घुमा-फिराकर इस विषय पर कुछ बोलना ही पड़ता है। उप्र इस मामले में बिल्कुल अलग है।

कांग्रेस की लुटिया यहां 1989 के विधानसभा चुनाव में डूबी थी, जब कुल 425 सीटों में पहली बार 100 से कम सीटें उसके हाथ लगी थीं। उसके बाद उभरी तीनों पार्टियां- सपा, बसपा और भाजपा यहां किसी न किसी वोट बैंक की राजनीति करती हैं और उसे अच्छे से संबोधित करते रहने के अलावा बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करतीं। एक समय ऐसा लगता था कि इस राजनीति की अपनी सीमा है, लेकिन फिर तीनों ने अपने तरीके में ज्यादा बदलाव किए बगैर 5-5 साल पूर्ण बहुमत की सरकारें भी चला लीं तो सीमा की चिंता समाप्त हो गई।

उप्र की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो पिछले साल इसका जीडीपी 17 लाख करोड़ रुपया दर्ज किया गया था, जबकि 6 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा इस पर सरकारी कर्ज था। 25 करोड़ आबादी को देखते हुए ये आंकड़े निराशाजनक हैं। करोड़ का हिसाब एक तरफ रख लें तो मामला कुछ ऐसा बनता है कि 25 लोगों का एक खानदान सालभर में 17 लाख रुपए कमाता है, जबकि 6 लाख का कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है। विकास के नाम पर राज्य सरकार कुछ नामी मंदिरों के अलावा कुछ सड़कें और एक-दो शहरों में पचासेक किलोमीटर मेट्रो रेल दिखाती है, लेकिन इतने बड़े राज्य में औद्योगिक इलाकों या साइबर सिटीज के नाम पर बहुत बड़ा शून्य पसरा हुआ है।

उप्र का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र अभी तीन दशक पहले तक कानपुर हुआ करता था। पूरब का मैंचेस्टर, जिसको भारत में टेक्नॉलजी का गढ़ मानते हुए खड़गपुर और बॉम्बे के बाद तीसरे आईआईटी की स्थापना यहीं की गई। आजादी के पहले दशक में देश के कई अन्य राज्यों में इस बात को लेकर भुनभुनाहट थी कि रुड़की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसे बड़े तकनीकी संस्थानों के होते हुए उप्र में एक और अग्रणी तकनीकी संस्थान की क्या जरूरत? लेकिन उस समय कोलकाता और मुंबई को छोड़कर कानपुर के आसपास भी खड़ा हो सकने वाला कोई औद्योगिक शहर कहां था?

पुणे और अहमदाबाद क्या, बेंगलूरु और हैदराबाद भी तब कानपुर होने के सपने देखते थे। वही कानपुर आज कहां है? इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की गिनती भारत ही नहीं, संसार के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों के रूप में हुआ करती थी। इनकी पढ़ाई-लिखाई का हाल, यहां छपने वाले शोधपत्रों का स्तर अभी कैसा है? चपरासी-बेलदार की नौकरियों के लिए जब लाखों ग्रैजुएट उप्र के तमाम शहरों में हर साल लाठियां खाने और भगदड़ में मारे जाने के लिए जमा होते हैं, उनमें कुछ एमबीए, बीटेक और पीएचडी की डिग्रियां दिखाते हैं तो राजनीतिक स्तर पर बयान जारी होते हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, युवा अपने कौशल का विकास करें। कुछ ज्ञानी राजनेता यहां तक बोल जाते हैं कि नौकरियां भरी पड़ी हैं, योग्य व्यक्तियों का ही अकाल है। लेकिन लंबी योजना की, राष्ट्र निर्माण वाली समझदारी की जरूरत यहीं पड़ती है। एक जवाबदेह सरकार देश-दुनिया में पैदा हो रही नई मांग के अनुरूप चीजों और सेवाओं के निर्माण का ढांचा कैसे तैयार करे और अपनी नई पीढ़ी को इसके लिए जरूरी कौशल और शिक्षा से लैस कैसे करे। कुछ न कुछ बेरोजगारी इसके बाद भी बनी रह सकती है, लेकिन संसार की पांचवीं सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के लिए पिछले 30 वर्षों में क्या यह चिंता का विषय भी रहा है?

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

दशा-दिशा भी तय करेंगे चुनाव

3 राज्यों में विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं और उप्र एवं मणिपुर के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी है। 5 राज्यों के इन चुनावों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका जनादेश राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कैसे प्रभावित करेगा? पिछले कुछ वर्षों के दौरान खासतौर से 2019 के आम चुनाव के बाद भाजपा को भी विधानसभा चुनाव जीतने में मुश्किलें आ रही हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस का वजूद लगातार सिकुड़ रहा है तो उसके लिए विधानसभा चुनावों के इस दौर में प्रतिस्पर्धा खासी कड़ी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी आप और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल अपने विस्तार में लगे हैं। जहां आप पंजाब में खुद को सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में पेश कर रही है तो उत्तराखंड और गोवा में उसे अपना दायरा बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच तृणमूल पूर्वी राज्यों विशेषकर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने में जुटी है। इतना ही नहीं गोवा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में खींचकर राज्य में प्रमुख दल के रूप में उभरने के तृणमूल के अरमान परवान चढ़ रहे हैं।

लालू फिर जेल में

लालू प्रसाद यादव की कुंडली से जेल योग नहीं निकल रहा है। लगातार 40 महीने जेल में बिता चुके राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 8वीं बार जेल पहुंच गए हैं। चारा घोटाला में डोरंडा ट्रेजरी से फर्जी कागजात के आधार पर 89 लाख रुपए की निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 15 फरवरी 2022 को फिर से जेल जाना पड़ा। इसके पहले झारखंड के चाईबासा, दुमका और देवघर कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे तक सजा भुगत चुके हैं। गत दिनों सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसए शशि ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा सुनाई। लालू समेत 99 लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई, जिसमें 24 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है।

चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनके ऊपर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में 1996 से अब तक साढ़े 32 साल की सजा हो चुकी है। दरअसल करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के झारखंड से जुड़े सभी मामलों में सजा सुना दी गई है। ऐसे में अब इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 32 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर 1.65 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें, चारा घोटाले का शाप लालू यादव का पीछा साल 1996 से कर रहा है। उस साल पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान 30 जुलाई 1997 को विशेष अदालत में सरेंडर और उन्हें पहली बार जेल भेजने की कहानी शुरू हुई थी। इसके पहले 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत से गिरफ्तारी का वारंट निकाले जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।

कई बार जा चुके हैं जेल

डोरंडा ट्रेजरी केस बहुचर्चित चारा घोटाले में से एक मामला है। 1990-92 के बीच चाईबासा ट्रेजरी से अफसरों और नेताओं ने 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था। इस केस में 10 महिलाएं भी आरोपी हैं। मामले में चार राजनीतिज्ञ, दो वरीय अधिकारी, चार अधिकारी, 6 लेखा कार्यालय के, 31 पशुपालन पदाधिकारी स्तर के और 53 आपूर्तिकर्ता आरोपी बनाए गए हैं। अब मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपी हैं जिन्हें अदालत दोषी करार दे चुकी है। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 1996 में पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच शुरू हुई थी। इस जांच में उन्हें उनके पटना की विशेष अदालत में सरेंडर और पहली बार जेल जाने की शुरुआत हुई थी। इसके पहले भी 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। लालू यादव को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था।

चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से जुड़े पहले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इस कोषागार से 37.70 करोड़ अवैध निकासी की गई थी। वहीं चारा घोटाला के देवघर कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 3.5 साल की सजा मिली थी और उन पर 10 लाख का जुर्माना था। चाईबासा कोषागार से 33.13 करोड़ की अवैध निकासी के एक और मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगा है। बता दें, लालू प्रसाद यादव को सबसे अधिक सजा दुमका कोषागार से अवैध निकासी में मिली थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी और पीसी एक्ट में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों मामलों में लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में गत दिनों लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

लालू यादव की बिहार में मजबूत पैठ है। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि उन्हें चारा घोटाले में जान-बूझकर फंसाया गया है, क्योंकि बिहार की जनता लालू यादव से काफी प्रभावित होती है। आरजेडी प्रमुख को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल भेजा गया था। वहां उन्हें 135 दिन जेल में रखा गया था। इसके बाद 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार फिर जेल भेजा गया, 5 अप्रैल 2000 को तीसरी बार जेल भेजे गए तो 11 दिनों बाद जमानत मिली। उन्हें साल 2000 के ही 28 नवंबर को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। लालू यादव तीन अक्टूबर 2013 को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 70 दिन जेल में रहे। फिर, 23 दिसंबर 2017 को एक और मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेजे गए तो 17 अप्रैल 2021 को जमानत मिल सकी थी। अब 15 फरवरी 2022 को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव अब फिर जेल में हैं।

● **विनोद बक्सरी**

आर्थिक संकट में श्रीलंका

घरेलू लोन और विदेशी बॉन्ड्स का भुगतान करने छापना पड़ रहा पैसा

सरकार को घरेलू लोन और विदेशी बॉन्ड्स का भुगतान करने के लिए पैसा छापना पड़ रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ श्रीलंका की इस बदहाली के लिए केवल चीन से लिए गए कर्ज की बात से इनकार करते हैं। इन विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी इस दशा के लिए श्रीलंका की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। श्रीलंका के कुल कर्जे में से चीन का हिस्सा मात्र 10 प्रतिशत है। इससे कहीं ज्यादा कर्ज श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उठा रखा है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 'लोवी इंस्टीट्यूट' के अनुसार इस समय श्रीलंका के कुल कर्ज का 47 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उठाया गया ऋण है। 22 प्रतिशत कर्ज विश्व बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का है। 10 प्रतिशत कर्ज जापान का है। ऐसे में अकेले चीन को श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अब तक के इतिहास में बड़ा आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के ऊपर इतना विदेशी कर्ज हो गया है कि वो 'दिवालिया' होने की कगार पर आ गया है। श्रीलंका की इस हालत के पीछे बड़ी वजह जो सामने आ रही है, वो है उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। श्रीलंका के पास अब इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो अपनी जरूरत का सामान आयात कर सके। पिछले साल मार्च में श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे चीनी और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कमी भी हो गई थी। हालांकि, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर का था, जो नवंबर 2021 में घटकर 1.6 अरब डॉलर का रह गया। श्रीलंका अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए मदद मांग रहा है। उसने चीन से भी मदद मांगी है। हालांकि, चीन की ओर से अभी तक मदद नहीं दी गई थी। श्रीलंका ने भारत से भी मदद मांगी थी। भारत की ओर से श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया जा रहा है।

आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है। 2010 से ही श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में लगातार बढ़ता रहा है। कोरोना संक्रमण से पहले यह ऋण जीडीपी के 42.9 प्रतिशत तक पहुंच गया था। कोरोना संकट के चलते पैदा हुए वैश्विक आर्थिक संकट ने श्रीलंका का यह कर्ज देश की जीडीपी से 101 प्रतिशत ज्यादा पहुंच गया। नतीजा यह रहा कि श्रीलंका सरकार द्वारा 2021 में देश की **अर्थव्यवस्था के संकट** को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना। अब वहां हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के समाप्त होने के चलते श्रीलंका अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की ना तो अदायगी कर पा रहा है, न ही उस पर तय ब्याज का भुगतान कर पा रहा है।

ये आर्थिक संकट श्रीलंका के आर्थिक विकास के मॉडल के कई दशकों का नतीजा है। मध्यम आय वर्ग के देश में बदलने के बावजूद लंबे गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से श्रीलंका बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में नाकाम रहा। श्रीलंका अपने आर्थिक विकास को सॉवरेन बॉन्ड और अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यावसायिक कर्ज के जरिए बरकरार रखने में लगा रहा। इस तरह के कर्ज आम तौर पर ऊंची ब्याज दर मिलते हैं और इन्हें कम समय में चुकाने की शर्त होती है। इसकी वजह से श्रीलंका सरकार को मजबूर होकर अपनी आमदनी और विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करना पड़ा और खर्च चलाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ा। 2020 तक श्रीलंका पर बाहरी कर्ज बढ़कर 35.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

गत वर्ष श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे चीनी और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कमी होने लगी। वर्ष 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर का था, जो वर्ष 2021 में घटकर 1.6 अरब डॉलर का रह गया। श्रीलंका अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा है।

श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने इस बात को माना है कि उनका देश भारी कर्ज से जूझ रहा है। उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा था कि श्रीलंका पर चीन, भारत और जापान का कर्ज है। उन्होंने बताया था कि श्रीलंका को इस साल 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। इसमें से 500 मिलियन डॉलर का कर्ज 18 जनवरी तक देना था। श्रीलंका को अगले 5 साल में 26 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। वही श्रीलंका पर चीन का ही 6 अरब डॉलर का कर्ज है। श्रीलंका ने चीन से पहले 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। बाद में आर्थिक संकट से निकलने के लिए फिर से पिछले साल 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म और उससे जुड़े सेक्टरों की हिस्सेदारी 10 फीसदी के आसपास है। कोरोना के चलते पर्यटकों के न आने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि महामारी के चलते श्रीलंका में 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। श्रीलंका की आर्थिक समस्या पर **विशेषज्ञों** का मानना है कि इस आर्थिक हालात के लिए विदेशी कर्ज खासकर चीन से लिया गया कर्ज भी जिम्मेदार है। चीन का श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर से अधिक कर्ज है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अगले 12 महीनों में देश को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब 7.3 अरब डॉलर की जरूरत है। नवंबर तक देश में विदेशी मुद्रा का भंडार महज 1.6 अरब डॉलर था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

चीन की चुनौती

व्हाइट हाउस ने अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीतिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को चीन से महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियों और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसके आक्रामक व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में चीनी भूमिका पर चिंता जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन की तरफ से जारी पहली क्षेत्र-विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका भारत पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि चीन अपनी आर्थिक, राजनयिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को बढ़ा रहा है, ताकि दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन सके। रिपोर्ट चीन को यह कहते हुए धोखेबाज के रूप में पेश करती है कि चीन का जनवादी गणराज्य मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रख रहा है, जिसमें नौपरिवहन की स्वतंत्रता के साथ अन्य सिद्धांत शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। नतीजा यह है कि चीन की आक्रामकता भारत को वाशिंगटन के करीब ले जा रही है।

हालांकि चीन हमेशा अपने नापाक मंसूबों में लिप्त रहा है और उसका अपने ही एक रेजिमेंट कमांडर, जो गलवान संघर्ष में घायल हो गया था, को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशालची बनाने का निर्णय परेशान करने वाला है। यह अधिकारी उस सैन्य कमान का हिस्सा था, जिसने भारत पर हमला किया था और उइगरों के खिलाफ नरसंहार में भी शामिल था। यह सब चीनी सेना के अरुणाचल प्रदेश के एक 17 वर्षीय लड़के के कथित अपहरण और प्रताड़ना के बाद आया है। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि चीन पिछले 6 दशक में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर चुका है। चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों में पुल का निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति चीन द्वारा सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा न करने के लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण थी।

सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह की तरफ से एक साल तक की गई गलवान डिकोडिड जांच के निष्कर्षों के मद्देनजर बीजिंग पहले से ही उलझन की स्थिति में है। इन निष्कर्षों के मुताबिक, जून 2020 में भारत के साथ गलवान घाटी सीमा संघर्ष में चीन की तरफ हताहत होने वालों की संख्या उसके आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। यह चीन की बढ़ती ताकत और विस्तारवादी गतिविधियों को उजागर करता है। वास्तव में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक सम्मानजनक आंकड़ा दर्शाना पड़ा, क्योंकि उसके सिर्फ चार मौतों के दावे के विपरीत एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम-से-कम 38 चीनी सैनिक अंधेरे में शून्य से भी नीचे के तापमान वाली तेज गति से बहने वाली नदी को पार करते समय डूब गए। इसमें कहा गया है कि वास्तव में जो हुआ, उसके बारे में बहुत सारे तथ्य बीजिंग ने छिपाए थे और ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां दुनिया को बताई गईं। इससे पहले एक रूसी समाचार एजेंसी ने चीनी पक्ष के 45 लोगों के मारे जाने का खुलासा किया था। भारत ने बताया था कि उसने 20 सैनिकों को खोया है। इनमें से कुछ को वीरता पदक से सम्मानित किया है। लेकिन पीएलए ने केवल चार मौतों को स्वीकार किया और वह भी बहुत देर बाद। वास्तव में इतिहास को विकृत नहीं किया जा सकता और नायकों को भुलाया नहीं जा सकता।

पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अब तक चली वार्ताओं में कई इलाकों को लेकर जिद बरकरार है। हाल में उपग्रह तस्वीरों के आधार पर अरुणाचल सीमा के पास चीन लारा गांव बसाए जाने, भूटान की सीमा के भीतर निर्माण किए जाने की खबरें आई हैं। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देपसांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। दरअसल, जब तक कैलाश रेंज पर भारतीय जवानों का कब्जा रहा, चीन दबा रहा। वार्ता के दौरान चीन ने कई इलाकों में अपनी फौज पीछे हटाने के एवज में भारत से कैलाश रेंज खाली करने की मांग रखी। जब कैलाश रेंज खाली हो गया तो चीन फिर से अपने रंग में लौट गया। अब भारत के सामने चीन को देपसांग इलाके में पीछे धकेलने की चुनौती फिर से मुंह बाए खड़े है।

देपसांग क्षेत्र में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने हैं। वार्ताओं में सहमति के बावजूद चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पिछले साल से ही अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पाइंट पीपी-10, 11, 11ए, 12 और 13 के साथ-साथ देमचोक क्षेत्र सेक्टर में 'ट्रैक जंक्शन' चार्डिंग निंगलुंग नाला (सीएनएन) तक जाने नहीं दे रही है। चीनी सैनिकों ने इन इलाकों के रास्ते रोक रखे हैं। भारत चाहता है कि देपसांग पठार में उसे गश्त के पुराने अधिकार मिलें, जहां चीनी सैनिक अभी उसे पीपी 10 से 13 तक जाने नहीं दे रहे। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देपसांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के 13वें चरण में देपसांग में तनाव कम करने पर जोर देते हुए अपना रुख पुरजोर तरीके से रखा था।

● **कुमार विनोद**

घुसपैठ से उठे सवाल

चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की दो घटनाओं की पृष्ठभूमि में 13वें दौर की बातचीत हुई थी। पहला मामला उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सामने आया था। पिछले महीने की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास भारतीय और चीनी सैनिकों का कुछ देर के लिए आमना-सामना हुआ था। हालांकि, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दोनों पक्षों के कमांडरों के बीच वार्ता के बाद कुछ घंटे में मामले को सुलझा लिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान की जमीन पर कई गांव बसा लिए हैं। पिछले एक साल में 100 वर्ग किलोमीटर में ये गांव बसाए गए हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। चीनी सेना की गतिविधियों की उपग्रह तस्वीरें जारी हुई हैं। एक विशेषज्ञ ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए दावा किया है कि चीन ने भूटान के अंदर पिछले एक साल में नए गांव बसा लिए हैं।

भारत अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। तमाम ऐसी प्रथाएं हैं जो सुनने-देखने में अटपटी लगें लेकिन लोगों के बीच उनका चलन आम है। ऐसी ही एक प्रथा है पैठू प्रथा जिसके चलते छत्तीसगढ़ में न केवल एक महिला शादी से पहले गर्भवती हुई। बल्कि उसने बेटे को जन्म भी दिया। दिलचस्प ये है कि कोई भी महिला के चरित्र पर अंगुली नहीं उठा रहा और जश्न का माहौल है।

पैठू प्रथा में कुंवारी मां के लिए तानों की गुंजाईश नहीं

न तो कोई जबरदस्ती है और न ही लालच

कोई बड़ी बात नहीं कि जिस घर में ऐसा हुआ हो उसके बारे में तरह-तरह की बातें हों। हो ये भी सकता है कि ऐसे लोगों का हुक्का-पानी बंद हो जाए और वो सोशल बॉयकॉट की भेंट चढ़ जाएं। लेकिन चूंकि ये सब आदिवासी समाज में हो रहा है तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वहां आज भी लोगों को इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या कहेगा बल्कि मुद्दा लड़की और लड़के की खुशी है जो उन्हें पैठू प्रथा के जरिए दी जा रही है। जिसमें किसी तरह की न तो कोई जबरदस्ती है और न ही लालच।

एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए जहां किसी लड़की की शादी हो। लोग तैयारियों और शादी से जुड़ी रस्मों में उलझे हों। तभी अचानक लड़की यानी दुल्हन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए। उसे अस्पताल ले जाया जाए। अस्पताल से ये खबर आए कि दुल्हन को पुत्ररतन की प्राप्ति हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों ही सकुशल हैं। खबर के बाद लोग लड़की के चरित्र पर अंगुली न उठाते हुए सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाएं... जैसा हमारा समाज है और जैसी अपब्रिंगिंग हमारी है शायद ही कोई इन बातों पर यकीन करे लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है और अपने ही देश भारत के छत्तीसगढ़ में हुआ है। भले ही सुनने में अटपटा लगे लेकिन बस्तर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार में शादी थी हल्दी की **रस्म के दौरान दुल्हन को प्रसव पीड़ा** हुई और शादी के कार्यक्रम को बीच में ही रोक देना पड़ा। परिजन दुल्हन को तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया।

मामले के मद्देनजर किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुल्हन की मां ने अपना पक्ष रखा है। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली दुल्हन की मां सरिता मंडावी ने बताया कि उनकी बेटी गर्भवती हुई और उसके बेटा हुआ। इसकी वजह पैठू प्रथा है। दुल्हन की मां के अनुसार उनकी बेटी शिवबती मंडावी अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपनी पसंद के लड़के चंदन नेताम जो बांसकोट का रहने वाला है। उसके यहां घर पैठू के लिए गई हुई थी। जहां पर वो 6 माह रही और गर्भवती हुई।

जैसा कि ज्ञात है छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी आदिवासी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में अपनी तरह की एक बेहद अनूठी प्रथा है जिसे पैठू के नाम से जाना जाता है। बात अगर बरसों पुरानी इस प्रथा की हो तो इसमें न तो मुहूर्त देखा जाता है और न ही कुंडली का मिलान होता है। इसमें लड़के-लड़कियां एक-दूसरे को पसंद कर शादी के लिए स्वतंत्र होते हैं।

इस प्रथा के अनुसार शादी योग्य लड़के-लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़की, लड़के के घर में चली जाती है जिसे पैठू प्रथा के नाम से जाना जाता है। मामले में दिलचस्प ये है कि ये प्रथा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जैसी ही अपनाई जा रही है। चूंकि इस मामले में रोचक तथ्य ये भी है कि लड़का-लड़की न केवल एक-दूसरे को पसंद कर चुके थे। वो पहले ही 6 महीने साथ रह चुके थे तो परिजनों ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया था। बाद में दोनों पक्ष बैठे और बात पक्की हुई। फिर लड़के और लड़की के घरवालों ने बाकायदा शादी के कार्ड छपवाए और इस शादी के लिए अपने रिश्तेदारों के अलावा स्थानीय गांव वालों को भी निमंत्रित किया।

अभी बीते दिनों ही लड़की की हल्दी की रस्म चल रही थी। घर पर **आशीर्वाद समारोह** और भोज का आयोजन था। लेकिन हल्दी की रस्म के दौरान ही दुल्हन की तबियत बिगड़ी और उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। परिजन उसे तुरंत ही पास के अस्पताल ले गए। जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में लड़का आया इससे न केवल परिजन बल्कि गांव वाले भी खुश हैं और लड़के की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं।

वो तो छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज है। वहां ये प्रथा बरसों बरस से है इसलिए न केवल बात आई-गई हुई बल्कि आम लोगों में भी खुशी की लहर है। एक बार कल्पना करके देखिए यदि ऐसा हमारे आसपास होता तो क्या लोगों का तब भी ऐसा या ये कहें कि मिलता-जुलता अंदाज होता? इस सवाल का सबसे बेहतर या ये कहें कि अनुकूल जवाब क्या होगा? इससे हम सभी वाकिफ हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

संसारिक दुखों की अचूक दवा है गीता

श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि।।

यानी हे अर्जुन। कर्म करने में तेरा अधिकार है। उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। श्रीमद् भागवत गीता ऐसे कई मंत्र हैं जिसके कारण इसे संसारिक दुखों की अचूक दवा माना गया है।

दरअसल श्रीमद् भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रन्थ है बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आंइसटीन तक अनेकों महापुरूष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। पृथ्वी पर जब-जब धर्म लुप्त हो जाता है, तो धर्म की पुन: स्थापना के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते है। भगवान श्रीकृष्ण की अमृतवाणी गीता पर बोलते हुए कहा कि संसारिक दुखों की केवल एक ही अचूक दवा है गीता। जिसका मनन करने से मनुष्य को कोई दुख नहीं सताता। गीता का मूलमंत्र भी यही है कि तुम अपना उद्धार स्वयं बनो। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। संसार एक नाट्यशाला है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से इस भूमि पर अच्छे बुरे कर्मों को करता है। संसार में मनुष्य अच्छे कर्म को करके अपने कुल और खानदान का नाम रोशन करता है। बुरे कर्म करके अपने और अपने कुल को बर्बाद कर देता है। मनुष्य को सदा सत्कर्म के ऊपर ही विशेष ध्यान देना चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि...

योगस्थ: कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धय-सिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।

यानी हे धनंजय (अर्जुन), कर्म न करने का आग्रह त्यागकर, यश-अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योगयुक्त होकर, कर्म कर, (क्योंकि) समत्व को ही योग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं गलत निर्णय सफलता की ऊंचाइयों से हमें जमीन पर भी ला सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने भागवत गीता में निर्णय लेने कुछ नियम बताए हैं। जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रन्थ है जो हर इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आगे जानते हैं कि भगवत गीता की वो बातें कौन-कौन सी हैं, जिसे अपनाकर हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि...

विहाय कामान् य: कर्वान्पुमांश्चरति निस्पृह:।
निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति।।

यानी जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो चीज हमें अच्छी अनुभूति देती हैं हम उसे ही पसंद करते हैं। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध खोने का डर था। परंतु श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती हैं। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय में श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए, कहीं ये निर्णय गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं ले रहे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। गीता में एक शब्द बार-बार दोहराया गया है, जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए।

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन।।

यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात् कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावें।

भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो इस काम को न करें। अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी न हो वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कोई निर्णय न लें। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। साथ ही उसकी हार कभी नहीं होती है।

● **ओम**

अंधविश्वास

प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो रही थी। पिछले दस दिनों में पंद्रह लोगों की जानें जा चुकी थीं। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। कोई नहीं बचेगा इस गांव में। अगले महीने तक सब मर जाएंगे। इस गांव को उस फकीर की बद्दुआ लग गई है, जिसके साथ दीपक ने गाली-गलौज और हाथापाई की थी। अगर उस दिन दीपक उस फकीर के मांगने पर बिना हुज्जत किए उसे पांच सौ रुपए दे देता तो आज दीपक हमारे बीच जिंदा होता। खुद तो मरा ही, पूरे गांव के सर्वनाश का आगाज भी कर गया। मैं तो कहता हूं उस फकीर को ढूंढ़ो और सारे गांव वाले मिलकर उससे माफी मांग लो। वह फकीर ही हमें इस कहर से बचा सकता है, बबलू ने अपना डर प्रकट करते हुए गांव वालों से कहा।

पागल मत बनो बबलू! गांव वालों की मौत किसी फकीर की बद्दुआ के कारण नहीं बल्कि विषाणु जनित वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हो रही है। मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूं अगर जिंदा रहना है तो अपने-अपने घरों में रहो। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से मत निकलो। हमेशा मास्क लगाकर रखो। सैनिटाइजर का प्रयोग करो। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दो। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करो। फिर देखना किसी को कुछ नहीं होगा, मास्टर दीनानाथ ने बबलू को समझाते हुए गांव वालों से कहा।

बबलू और उसके कुछ दोस्तों को छोड़कर बाकी गांव वाले मास्टर दीनानाथ की बातों से सहमत थे। बबलू और उसके दोस्त पहले की भांति इधर-उधर घूमते रहे, जबकि बाकी गांव वालों ने मास्टर दीनानाथ की बातों पर अमल करते हुए बबलू और उसके दोस्तों से दूरी बना ली।

तीन महीने पश्चात, बबलू और उसके दोस्तों को छोड़कर बाकी सभी गांव वाले जीवित और स्वस्थ थे।

- आलोक कौशिक

सब कुछ तुम्हारे हाथ में है...!

एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिलकुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहां तो पानी का नामो-निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला-क्या भगवान आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़-पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती! ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा-मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो! तभी एक चमत्कार होता है, नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है!

वह उस इलाके में बरसों से आ-जा रहा था पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई।

एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ! वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोउंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है, पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था!

अब वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है, उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने दो-चार कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है- मैंने तुम्हे पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी। पानी ढोने का साधन भी दिया, अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हे रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के लिए चाहिए, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है! आदमी एक क्षण के लिए ठहरा गया पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा-भरा नहीं बन पाया।

- अज्ञात

आ गए फिर से लुटेरे

वोट का धन लूटने को,
आ गए फिर से लुटेरे।।

मंडियां सजने लगी हैं,
भीड़ है व्यापारियों की।
वायदों की पोटली में,
गंध है मक्कारियों की।
एक सी खिचड़ी पकाते,
भाई मौसेरे-फुफेरे।।

आसमां को आप अपने,
पांव के नीचे समझिए।
कौन, क्या, कैसे करेगा,
इस बहस में मत उलझिए।
मछलियों को फांसने में,
हैं बहुत माहिर मछेरे।

मुफ्तखोरी की नशीली,
गोलियां मिलने लगी हैं।
मूढ़ जनता के दिलों में,
कोंपलें खिलने लगी हैं।
वे खड़े हैं चींटियों की
राह में शक्कर बिखेरे।

दल बदलने के बहुत से,
कारणों की बात होगी।
रात में सूरज उगेगा,
दोपहर में रात होगी।
एक दल में शाम है तो,
दूसरे दल में सवेरे।।

रैलियों पर रैलियां कर,
भीड़ लाई जा रही है।
और पीछे संक्रमण की,
धुन बजाई जा रही है।
हैं नजरअंदाज इस पल,
वायरस के भी बसेरे।।

- बृज राज किशोर 'राहगीर'

प्रतिभाओं की युवा टोली

हाल के कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेट खिलाड़ी का लक्ष्य आईपीएल में बेहतर नीलामी में जगह बनाना बन गया है। दरअसल सच तो यह है कि भारतीय टीम में चयन भी अब काफी हद तक आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर होने लगा है। अब, जबकि भारत ने रिकॉर्ड पांचवीं बार विश्व अंडर-19 कप जीत लिया है, तो चर्चा यह होने लगी है कि इनमें से कौन-कौन खिलाड़ी आईपीएल मेगा नीलामी में ऊंची बोली में जाएंगे? इस बात की चर्चा बहुत कम है कि इनमें से कौन-कौन खिलाड़ी हैं, जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट को मजबूती देंगे। इस बार की विश्व विजेता टीम में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, जिन्हें बेहिचक भारतीय टीम के भविष्य के सितारे कहा जा सकता है।

ठीक है कि आईपीएल भी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) का ही हिस्सा है, लेकिन आईपीएल सीमित ओवर का, वह भी महज 20 ही ओवर का खेल है। रणजी ट्रॉफी और दूसरी चार-पांच दिन वाली घरेलू प्रतियोगिताओं में टेस्ट टीम में आ सकने वाली प्रतिभाओं की ज्यादा परख होती है। लेकिन आईपीएल चूंकि कारपोरेट का भी खेल है, घरेलू प्रतियोगिताओं के मुकाबले उसकी ही चर्चा हर जगह होती है। हाल के कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि भारत में आईपीएल के मैच देखने के लिए तो टिकट की होड़ मची रहती है, टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में खिलाड़ियों के अलावा गिने-चुने दर्शक ही दिखते हैं।

इस बार की विश्व विजेता कप टीम को देखा जाए, तो इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने प्रतिभा के बूते सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इनमें यश ढुल, अंगकृष रघुवंशी, राज बावा, शेख रशीद, हरनूर सिंह, विक्की ओसवाल, निशांत सिंधु और राजवर्धन हंगरगेकर शामिल हैं। पिछले 20 साल के युवा विश्व क्रिकेट कप का इतिहास देखा जाए, तो जाहिर होता है कि भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसमें से निकले कुछ खिलाड़ी देश की टीम का हिस्सा बने, जिनमें विराट कोहली भी शामिल हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस विश्व कप से देश के लिए युवा क्रिकेटरों की ऐसी टोली निकली है, जो प्रतिभा से भरपूर है। आईपीएल की नीलामी में निश्चित ही इनका बोलबाला रहेगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि यह प्रतिभाएं आईपीएल तक सीमित न रहें। टेस्ट मैच से लेकर भारतीय टीम के दूसरे फॉर्मेट में भी अवसर पा सकें और खुद को साबित कर सकें।

सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में कदम रखते ही भारतीय युवा टीम ने यह जता दिया था कि भारत किस इरादे से यहां है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 44.5 ओवर में 189 रन पर इंग्लैंड का बिस्तर बांध दिया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे राज बावा ने महज 35 रन देकर पांच विकेट लिए। इस मैच ने सन् 1983 के विश्व कप की याद ताजा कर दी, जिसमें सीनियर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 184 रन पर समेट दिया था। उसे याद करके भी लगा कि भारत अब पांचवें युवा विश्व कप के नजदीक खड़ा है। हालांकि हुआ भी ऐसा ही, लेकिन दिलचस्प अंदाज में। भारत ने 48.4 ओवर में जाकर 6 विकेट पर 195 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की शुरुआत वैसे खराब रही। ओपनर अंगकृष रघुवंशी खाता खोले बिना पहले ही ओवर में जोशुआ बॉडेन की गेंद पर चलते बने। इसके बाद हरनूर सिंह और शेख रशीद ने मजबूत मोर्चा संभाला, लेकिन 49 रन पर हरनूर 21 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मैदान में उतरे उपकप्तान शेख रशीद और कप्तान यश ढुल ने टिककर बल्लेबाजी की। शेख ने 84 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनके जाने के बाद कप्तान यश भी 17 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिससे भारत को चौथा झटका लगा।

स्कोर 97 रन पर चार विकेट का हो गया, तो राज बावा और निशांत सिंधु ने 88 गेंदों में 67 रन की साझेदारी करके भारत के लिए उम्मीद जिंदा रखी। हालांकि 43वें ओवर में राज बावा के आउट होने से कराते हुए बड़ा झटका दे दिया। राज गेंदबाजी के बाद बल्ले से भी कमाल करने में कामयाब रहे, जिसकी भारत को जरूरत थी। बावा ने 35 रन बनाए। निशांत ने हाफ सेंचुरी पूरी की, तो 48वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश ने सिक्स लगाते हुए भारत को खिताब जितवा दिया। हरनूर सिंह (50) और निशांत सिंधु (50*) ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। बावा ने तो युगांडा के खिलाफ ताबड़तोड़ 168 रन ठोके थे। इससे पहले इंग्लैंड ने 44.5 ओवर में 189 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए जेम्स रीयू (95) ने देश की टीम को बहुत-ही कम स्कोर पर आउट होने से बचा लिया। इंग्लैंड के लिए रीयू और जेम्स सेल्स (नाबाद 34) ने आठवें विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड का स्कोर 11वें ओवर में तीन विकेट पर महज 37 रन था। टूर्नामेंट में भारत का सफर प्रभावशाली रहा। पहले मैच में 15 जनवरी को उसने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन, 19 जनवरी को आयरलैंड को 174 रन, 22 जनवरी को युगांडा को 326 रन, 29 जनवरी को बांग्लादेश को पांच विकेट से, 2 फरवरी को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन, जबकि फाइनल में 6 फरवरी को इंग्लैंड को चार विकेट से हराया।

● **आशीष नेमा**

भारतीय टीम ने 5वीं बार कप जीता

भारत ने अंडर-19 विश्व कप-2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को चार विकेट से हराया। मैच दिलचस्प बन गया था। भारतीय टीम ने 5वीं बार कप जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जिसने तीन ट्रॉफी (एक बार यूथ वर्ल्ड कप) जबकि पाकिस्तान दो बार, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश ने एक-एक बार खिताब जीता है। वैसे तो पहला विश्व कप सन् 1988 में हुआ था, लेकिन भारत ने सन् 2000 में पहला खिताब जीता, जब मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के कप्तान थे। इसके बाद भारतीय टीम अलग-अलग वर्षों में तीन बार चैंपियन बनी। अब इसी साल (2022) का विश्व कप जीतकर उसने पांचवीं जीत हासिल की है।

300 फिल्मों में काम कर चुकीं श्रीदेवी थीं बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार

श्री देवी ने अपने तीन दशक लंबे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। श्रीदेवी ने अपनी शादी के लगभग 15 साल के बाद गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ कमबैक किया। श्रीदेवी को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें चालबाज और लम्हे के लिए बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था।

हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत साल 1979 में आई फिल्म सोलहवां सावन से की। इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। श्रीदेवी वापस दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर लौट गई। साल 1983 में श्रीदेवी ने एक बार फिर फिल्म हिम्मतवाला के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और फिर यहीं की होकर रह गईं। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेत्री वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं।

साउथ-बॉलीवुड में बस लैंग्वेज का ही फर्क है, काम करने का स्टाइल और प्राइज सेम हैं: प्रियामणि

साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रियामणि अजय देवगन के साथ मैदान में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह जैकी श्रॉफ और सनी लियोनी के साथ तमिल फिल्म में काम कर रही हैं। पेंडेमिक में काम करने पर आने वाले बदलाव पर प्रियामणि कहती हैं, आई थिंक, पर्सनल एक्सप्रीरिंस में बहुत सारा चेंज तो नहीं देखा है। बेशक, जब से काम कर रही हूं, तब से थोड़ा-बहुत चेंज तो आया ही है और यह चेंज होता ही रहता है। अगर साउथ और नॉर्थ, दोनों इंडस्ट्री में देखेंगे, तब प्रोफेशनलिज्म वही है। काम भी वैसा ही हो रहा है। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है।

प्रियामणि कहती हैं कि पहले लोग बिना मास्क के भी घूम रहे थे, लेकिन अब सब लोग मास्क पहन रहे हैं। अगर कोई नहीं पहन रहा है, तब लोग उसे बोल भी रहे हैं। लोग सैनिटाइजर साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे जहां तक पता है, लोग सोशल डिसटेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। डायलॉग, डायरेक्टर, को-स्टार और यूनिट का अंतर है, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं है। काम करने की स्टाइल और प्राइज भी सभी जगह पर सेम ही होगा।

मेरा जज करने का तरीका एक दोस्त की तरह होता है... प्रियामणि कहती हैं कि जब मैं जज की कुर्सी पर बैठती हूं, तब एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूं। मुझे जैसा अच्छा लगता है, वैसा सजेस्ट करती हूं। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी लगे, तब डिसकरेज नहीं करती हूं। मेरा जज करने का तरीका एक दोस्त की तरह होता है। मैं फ्रेंड की तरह प्रतिभागियों को हेल्प करती हूं। अगली बार परफॉर्मेंस दें, तब उसे बेहतर बनाने के लिए क्या जोड़ या निकाल सकते हैं। इस तरह सजेस्ट करती हूं। मैं ही नहीं, बल्कि मेरे को-जजेस भी इन बातों पर ध्यान देते हैं। एक प्रतिभागी का नॉन स्टॉप 6 मिनट का डांस करना बहुत बड़ी बात है। बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं और सुबह से लेकर रात तक बहुत हार्डवर्क और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में एक दोस्त की तरह ही उन्हें एडवाइज करती हूं।

एक्टर बनने आए डैनी को डायरेक्टर ने ऑफर की थी गार्ड की नौकरी

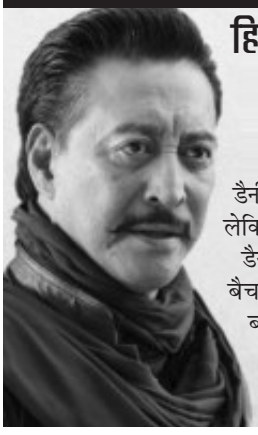

हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक डैनी डेन्जोंगपा हिंदी के साथ नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने कांचा चीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे किरदार पर्दे पर निभाए और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। सिक्किम जैसे छोटे राज्य से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। लेकिन उनके संघर्ष का कहानी बड़ी रोचक है।

डैनी का असली नाम शेरिंग पेंत्सो था। उन्हें डैनी नाम उनकी बैचमेट जया भादुड़ी (जया बच्चन) ने दिया था। एक बार की बात है, डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू वो इलाका था जहां धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे उस दौर के फेमस एक्टर्स के बंगले थे। तभी डैनी की नजर मोहन कुमार के बंगले के बाहर पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड थे। जिस कारण डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात तो की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा रखी।

मोहन उनपर जोर-जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर की। उस दिन डैनी ने खुद से ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला बनाएंगे। वक्त गुजरता गया और डैनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन उन्हें खुद से किया अपना वादा याद था। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली जमीन को खरीद उस पर खुद का बंगला बनवाया।

चांद पर प्लाट का लफड़ा

उसका आवेदन पत्र पढ़ने के बाद वे कुछ देर मुस्कराए और फिर बोले- देखिए बसंल जी, आपकी शिकायत तो वाजिब है लेकिन अब वह कंपनी ही बंद हो चुकी है और जिन्होंने कंपनी बनाई थी, वे भी मर खप गए हैं तो कैसे आपके प्लाट का कब्जा आपको दिलवा सकेंगे।

सर, मुझे एक कम्प्लेंट करना है।

हां, तो कर दो, उन्होंने बगैर सिर उठाए ही कहा।

सर, मैंने छः महीने पहले भी डिजीटली एफआईआर दर्ज की थी और तभी से लगातार थाने के चक्कर लगा रहा हूं लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आपके पास निवेदन करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे न्याय दिलवाएंगे।

इस बार उन्होंने थोड़ा सिर ऊपर उठाया और बोले-हूंअ, क्या शिकायत है आपकी! अभी थोड़ा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ओरली ही बता दो।

सर, मुझे मेरे प्लाट का कब्जा चाहिए।

तो भाई, जिससे खरीदा है, उसी से कब्जा भी प्राप्त करो।

नहीं सर, प्लाट मैंने नहीं खरीदा था, मेरे दादाजी ने खरीदकर मेरी दादी को विवाह के अवसर पर गिफ्ट किया था।

तब तो उन्होंने कब्जा लिया ही होगा। अब तुम कब्जा प्राप्त करने वाले कौन? यदि कब्जा नहीं मिला था तो फिर उस समय तुम्हारे पिता ने प्लाट का कब्जा क्यों नहीं लिया। क्या उस पर संपत्ति का विवाद है या किसी दूसरे ने उस पर कब्जा कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह प्लाट किसी दूसरे को भी बेच दिया गया हो और उसने कब्जा कर लिया हो।

नहीं सर, असल में मेरे दादाजी को ही उस प्लाट का कब्जा नहीं मिल पाया था और उस प्लाट को खरीदने और कब्जा लेने के चक्कर में सरकारी दफ्तरों के चक्कर खा-खाकर उनके जूते-चप्पल घिस गए और घर के भांडे-बर्तन तक बिक गए। बाद में पिताजी भी इसके लिए यहां-वहां भटकते रहे।

तो क्या कॉलोनी गवर्नमेंट से एप्रूव नहीं थी। यानी रेरा की स्वीकृति, स्थानीय प्रशासन की अनुमति और विकास कार्य के बगैर प्लाट काटे गए थे।

नहीं सर, वास्तव में प्लाट तो चांद पर काटे गए थे। बड़े-बड़े लोकलुभावन परिदृश्य दिखाए गए थे। जिस कंपनी ने प्लाट बुक किए थे, बाद में वह बंद हो गई। अब उसके कोई पदाधिकारी मिल नहीं रहे हैं। मैंने अपने आवेदन में सब स्पष्ट रूप से लिखा है।

उसका आवेदन पत्र पढ़ने के बाद वे कुछ देर मुस्कराए और फिर बोले-देखिए बसंल जी, आपकी शिकायत तो वाजिब है लेकिन अब वह कंपनी ही बंद हो चुकी है और जिन्होंने कंपनी बनाई थी, वे भी मर खप गए हैं तो कैसे आपके प्लाट का कब्जा आपको दिलवा सकेंगे। और वैसे भी आपके दादाजी ने अपनी शादी के अवसर पर आपकी दादी के नाम चांद पर बुक किए गए प्लाट का अनुबंध ही तो किया था। उसकी रजिस्ट्री और प्लाट के आधिपत्य के कोई पेपर तो आपके पास हैं नहीं। और फिर जैसा कि आपने अपने आवेदन में लिखा है कि देश की जिस कंपनी का उस समय अमेरिकी कंपनी से मिलकर प्लाट बेचने की योजना थी, बाद में उससे अमेरिकी कंपनी ने समझौता तोड़ दिया था और अमेरिकी कंपनी की जगह चाइनीज कंपनी से उसका समझौता हो गया। ऐसे में किसके खिलाफ मामला दर्ज करें! वैसे भी इन चीनियों का कोई भरोसा भी तो नहीं है।

आपकी बात तो सही है सर, लेकिन फिर भी कंपनी के कागजात तो हमारे पास हैं ही! बाद में दादाजी ने उससे रिवाइज्ड एग्रीमेंट भी करवा लिया था।

हां तो! कागज पर तो कितने ही काम हो रहे हैं। शासन की पेपरलैस योजना के बाद भी सरकारी दफ्तरों में पेपर ही आज भी कार्रवाई हो रही है। हम तो बिना कागज के भी जांच कर करके थक चुके हैं भाई। कागजी खानापूर्ति से ही यदि काम चल जाता तो हम भी आपको चांद पर कागजों में ही प्लाट का कब्जा दिलवा देते। बहरहाल, यह बताइए कि क्या तब उस कंपनी ने देश की सरकार से चांद पर कॉलोनी विकसित करने और आबादी बसाने की वांछित अनुमति प्राप्त कर ली थी।

सर, मूल योजना तो अमेरिकी कंपनी की थी जिसे बाद में चाइनीज कंपनी ने टेकओवर कर लिया था। सुना तो यह भी गया था कि चांद पर उस जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया था।

तब तो यह भी हो सकता है कि आपके दादा-दादी ने पहले ही चांद पर प्लाट का कब्जा ले लिया हो और बगैर किसी को बताए वे लोग वहीं रहने चले गए हों! अब देखो यह चन्द्रलोक और भूलोक के अलावा आपका पारिवारिक मामला लगता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कहकर ऑफिसर फिर सिर झुकाकर अपने काम में यानी लैपटॉप पर तीन पत्ती खेलने में व्यस्त हो गए।

● **डॉ. प्रदीप उपाध्याय**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{2} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687